



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236508
CG-DL-E-11062022-236508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944

No. 150]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

मामला सं. एडीडी (एसएसआर)-11/2021

विषय : रूस, जार्जिया और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अमोनियम नाइट्रेट” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/11/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स स्मार्टकेम टेक्नोलॉजी लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने रूस, जार्जिया और ईरान (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट (जिसे यहां आगे “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के अनुरोध के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

2. मूल जांच जार्जिया, इंडोनेशिया, ईरान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में पाटन की प्रकृति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उसके क्षतिकारक प्रभाव की जांच करने के लिए 5 अगस्त, 2016 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने, अपने 1 अगस्त, 2017 के अंतिम जांच परिणाम सं. 14/1/2016-डीजीएडी द्वारा जार्जिया, इंडोनेशिया, ईरान और रूस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 44/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 सितंबर, 2017 द्वारा प्रभावी किया गया था। उपर्युक्त शुल्क यदि बढ़ाए नहीं गए, 11 सितंबर, 2022 को समाप्त हो जाएंगे।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पहले न हटाए गए हों, उनके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“अधिनियम के तहत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क तब तक उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि की समाप्ति से पूर्व की उपयुक्त समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् सिद्ध अनुरोध पर अथवा अपनी पहल पर उस अवधि से पूर्व शुरू की गई समीक्षा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं आते हैं कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।”

4. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् सिद्ध अनुरोध के आधार पर समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. आवेदक ने पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए और जार्जिया, इंडोनेशिया, ईरान और रूस से अमोनियम नाइट्रेट के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की मांग करते हुए 29 अप्रैल, 2021 को एक आवेदन-पत्र दायर किया। यह अनुरोध इन आधारों पर था कि उपायों की समाप्ति से विचाराधीन उत्पाद का पाटन होने की संभावना है और फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य से युक्त विधिवत् सिद्ध आवेदन-पत्र के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने जार्जिया, ईरान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 11 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 7/11/2021-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। इंडोनेशिया के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि के दौरान न तो इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात थे और न ही लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य था।

ख. प्रक्रिया

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 1 अगस्त, 2017 के अंतिम जांच परिणाम सं. 14/1/2016-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं, जिससे संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।
8. वर्तमान जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 11 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 7/11/2021-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित की।

- ii. सार्वजनिक सूचना की प्रति प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत के संबंध में उन्हें सूचित करने के लिए भेजी थी।
- iii. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा संबद्ध देशों की सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से और उन हितबद्ध पक्षकारों को जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित में अनुरोध किया था, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भेजी। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।
- iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अथवा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में प्रश्नावली के उत्तर दायर करने का अवसर प्रदान करने और नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया गया था।
- v. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना की प्रतियां भेजी:
 - क. रुस्तवी अजोट एलएलसी, जार्जिया
 - ख. शिराज पेट्रोकेमिकल कंपनी, ईरान
 - ग. यूरोकेम ग्रुप, रूस
 - घ. जेएससी एक्रोन (नवगोरोड), रूस
 - ङ. फोसाग्रो – चेरपोवेट्स, रूस
 - च. उरलाकेम ग्रुप-एमएफपी केसीसीडब्ल्यू, रूस
 - छ. उरलाकेम ग्रुप-जेएससी एजोट (बेरेजनिगी), रूस
- vi. संबद्ध देशों की सरकार से भारत में उनके दूतावास के माध्यम से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबंधित संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के ब्यारे के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी।
- vii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
 - क. एजोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क)
 - ख. साइटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 - ग. ड्रेमूर फर्टिलाइजर्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
 - घ. यूरोकेम ट्रेडिंग जीएमबीएच
 - ङ. यूरोकेम ट्रेडिंग आरयूस, एलएलसी
 - च. जेएससी एजोट, केमेरोवो
 - छ. नेविनोमिस्की एजोट नेविनोमिस्की
 - ज. राफर्ट ऑफशोर एसएएल
 - झ. रिनो रॉक लिमिटेड
 - ञ. एसबीयू निट्रोटेड एजी

- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की प्रति भेजी:
- क. एकेएस एक्सपो-केम प्राइवेट लिमिटेड
 - ख. अंबल्स एक्सप्लोसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ग. एपी एक्सप्लोसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - घ. अरावली एक्सप्लोसिव केमिकल्स
 - ङ. बीजासन एक्सप्लोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 - च. भारत एक्सप्लोसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - छ. ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ज. ब्लास्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - झ. बूम बाईंग प्राइवेट लिमिटेड
 - ञ. कनपेक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ट. सीडीईटी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - ठ. दिशामन फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
 - ड. जीओसीएल कारपोरेशन लिमिटेड
 - ढ. गौतमी एक्सप्लोसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ण. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
 - त. आइडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिक्स
 - थ. आईडीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - द. इंडियन एक्सप्लोसिक्स लिमिटेड (ओरिका)
 - ध. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
 - न. इंडो गल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - त्त. इंटराकेम कंपनी
 - प. काकतिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - फ. कारोलिंस्का इंडस्ट्रीज
 - ब. केलटेक एनर्जिज लिमिटेड
 - भ. लबधि केमिकल्स इंडस्ट्रीज
 - म. एलएस केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स
 - कक. महानंदी मेटल्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - खख. मेर्क लाइफ साईंस प्राइवेट लिमिटेड
 - गग. मोलीकेम
 - घघ. नल्लाबोलु इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - ङ.ड. ओडिसा एक्सप्लोसिक्स लिमिटेड
 - चच. पेरी नाइट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड

- छछ. प्रसाद एक्सप्लोसिब्स एंडकेमिकल्स
जज. प्रीमियर एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड
झझ. राजा एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
ञ.ञ. राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड
टट. रेजेनसिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
ठठ. साल्वो एक्सप्लोसिब्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
डड. ससन पावर लिमिटेड
ढढ. एसबीएल एनर्जी लिमिटेड
णण. सिगमा एल्दरिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
तत. शिवशक्ति इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
थथ. सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
दद. स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड
धध. श्री अमन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
नन. श्री कृष्णा एक्सप्लोसिब्स एसेसरीज कंपनी
पप. विष्णु एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
फफ. स्टैंडर्ड केमिकल कारपोरेशन
बब. ठक्कर इंटरनेशनल
भभ. दि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
मम. टोटेम इंटरनेशनल लिमिटेड
यय. वेटरीवेल एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
ककक. विशु केमिकल्स
खखख. वागेश एनर्जी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- क. ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
ख. आईडीएल एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड
ग. सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
घ. स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड
ङ. इंडियन एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
- x. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में अनुरोध दायर किए हैं:
- क. ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिब्स प्राइवेट लिमिटेड
ख. एक्सप्लोसिब्स मैनुफैक्चर्स वेलफेयर एसोसिएशन
ग. आइडियल इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड
घ. आईडीएल एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड
ङ. रिजेंसीज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
च. सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- xi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 और जांच की अवधि शामिल है।
- xii. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन-वार आयात डेटा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त किया गया था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि डीजीसीआई एंड एस डेटा में रिपोर्ट किए गए अनुसार रूस से आयात की मात्रा रूसी सीमा शुल्क डेटा के साथ-साथ भाग लेने वाले उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार निर्यात की मात्रा से बहुत कम है। इसलिए, प्राधिकारी ने रूस के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा और मूल्य की गणना करने वाले रूसी सीमा शुल्क आंकड़ों और अन्य विषय-देशों के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xiii. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक और सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xiv. क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की ईष्टम उत्पादन लागत और निर्माण और बिक्री लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। यह क्षति रहित कीमत यह सुनिश्चित करने के लिए मानी गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनसे इस अनुरोध के साथ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से पहुंच में नहीं थी।
- xvi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 नवंबर, 2021 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- xvii. जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क और दी गई सूचना पर वर्तमान जांच के लिए उनके साक्ष्य के साथ समर्थित होने की सीमा और संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xviii. नियम 17 के साथ पठित नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी ने 20 मई, 2022 के पत्र द्वारा केन्द्र सरकार से 6 माह तक जांच की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। तथापि, दिनांक 6 जून, 2022 के पत्र द्वारा केन्द्र सरकार ने समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति नहीं दी। इन आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सीमित समय दिया है क्योंकि जांच 11 जून, 2022 को समय-बद्ध हो जाएगी।
- xix. प्राधिकारी ने, जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की प्रशुद्धता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया जो यथासंभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है और संगत मानी गई सीमा तक, व्यावहारिक और आवश्यक सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की

गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- xxi. जहां कहीं, किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई ऐसी सूचना दर्शाते हैं।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमयदर 1 अमरीकी डॉलर=74.99 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

9. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:-

“4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) वही है जो पूर्व जांच में था, अर्थात् “अमोनियम नाइट्रेट चाहे प्रिल्ड, ग्रेनुलर अथवा अन्य ठोस रूपों में, एडीटिव्स अथवा कोटिंग के साथ अथवा उसके बिना और 0.83 जी/सीसी से अधिक भारी घनत्व वाला”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. अमोनियम नाइट्रेट (जिसे यहां आगे “एएन” भी कहा गया है) सभी रूपों और सभी घनत्वों में समान उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पिघला हुआ और ठोस अमोनियम नाइट्रेट के भिन्न रूप हैं तथा सभी रूपों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। एएन मेल्ट का उत्पादन किया जाता है और ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है। अन्य ठोस रूपों में एएन मेल्ट और एएन के बीच कोई तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अंतर नहीं है।
- ख. मूल जांच में निर्धारित उत्पाद का क्षेत्र उपयुक्त नहीं था और उसे निर्णायक समीक्षा में दुबारा से देखा जाना चाहिए।
- ग. उत्पाद का वर्णन करने के लिए भारी घनत्व को रखने का कोई आधार नहीं है क्योंकि सभी घनत्व परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एडीएएन और एचडीएएन केवल संकेन्द्रण के स्तर के मामले हैं और उनमें कोई तकनीकी भेद नहीं है।
- घ. वर्ष 2003 में, निष्कर्ष निकाली गई जांच में प्राधिकारी ने प्राथमिक जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट के सभी रूपों को शामिल किया। तथापि, अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने किसी तकनीकी साहित्य के संदर्भ के बिना भिन्न दृष्टिकोण लिया। यूरोपीय आयोग ने अपने विनियम (ईयू) सं. 2020/2100 में भी माना है कि दोनों प्रकार के एएन की समान तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं हैं, आसानी से परस्पर परिवर्तनीय हैं।
- ड. आवेदक के पास 0.87जी/सीसी तक के भारी घनत्व के अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण की ही क्षमता है। प्राधिकारी ने कई जांचों, यथा – हाई स्पीड स्टील, प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड, विकस्कोस फिलामेंट यार्न, आदि में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र उस सीमा तक प्रतिबंधित किया है, जहां तक घरेलू उद्योग उसका उत्पादन कर रहा था।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

11. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है, जैसाकि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

- ख. मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट विचाराधीन उत्पाद के लिए एक वाणिज्यिक स्थानापन नहीं है क्योंकि इसमें अधिक परिवहन और भंडारण लागत शामिल होती है तथा लंबी दूरियों तक इसका परिवहन नहीं किया जा सकता।
- ग. मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट भारत में आयात नहीं किया जा रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग ठोस के रूप में समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है और इसीलिए मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट समान वस्तु नहीं मानी जा सकती।
- ङ. मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट न तो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है और न ही समान वस्तु के क्षेत्र में, जैसाकि सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेस्टेट द्वारा माना गया है।
- च. प्रयोक्ताओं ने खुद ही स्वीकार किया है कि मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट पूर्व जांच में समान वस्तु नहीं है और इसीलिए अपने दावे का विरोधाभाष कर रहे हैं।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के प्राथमिक जांच परिणामों पर विश्वास किया है जिसमें उन्होंने खुद की एएन मेल्ट और एलडीएएन मेल्ट को बाहर रखने का तर्क दिया है। प्राधिकारी ने इन तर्कों को अंतिम जांच परिणाम में स्वीकार किया।
- ज. प्राधिकारी ने पूर्व जांच में पहले ही माना है कि आवेदक ने 0.83जी/सीसी से अधिक और अधिकतम 0.94जी/सीसी घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन किया है।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अमोनियम नाइट्रेट है चाहे वह प्रिल्ड, ग्रेनुलर अथवा अन्य ठोस रूपों में, एडीटिव्स अथवा कोटिंग के साथ अथवा उसके बिना और 0.83 जी/सीसी से अधिक भारी घनत्व वाला हो।
13. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जां मूल जांच में था। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

“(i) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व जांच में था, अर्थात् “अमोनियम नाइट्रेट चाहे प्रिल्ड, ग्रेनुलर अथवा अन्य ठोस रूपों में, एडीटिव्स अथवा कोटिंग के साथ अथवा उसके बिना और 0.83 जी/सीसी से अधिक भारी घनत्व वाला हो, जो उप शीर्ष 3102 30 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 31 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

(ii) अमोनियम नाइट्रेट, फार्मूला एनएच₄एनओ₃ के साथ रासायनिक मिश्रण, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के सॉल्ट का सम्मिश्रण है। नाइट्रेजन की मात्रा ठोस रूप में भार के 28 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। कमरे के तापमान में, अमोनियम नाइट्रेट सफेद क्रिस्टलिन रंगहीन स्वरूप में दिखाई देता है। इसका मेल्टिंग प्वाइंट 169.6 डिग्री सेल्सियस अथवा 337.3 डिग्री फरेनाइट है।

(iii) अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन विभिन्न रूपों, यथा – मेल्ट, प्रिल्स, फ्लेक्स, ग्रेनुल्स, लंप्स, आदि में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। संबद्ध सामान 0.83 जी/सीसी से अधिक घनत्व वाला ठोस रूप में अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट 0.83 जी/सीसी तक के भारी घनत्व वाले किसी भी रूप में और किसी भी घनत्व में मेल्ट अथवा लिक्विड रूप में अमोनियम नाइट्रेट विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।

(iv) भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग प्रमुख रूप से विस्फोटकों के विनिर्माण में, यथा – इम्लस्न विस्फोटकों के विनिर्माण में किया जाता है, जबकि विश्व के कई अन्य भागों में उनका प्रयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग भारत में केवल विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए किया जा सकता है।”

14. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 3102 3000 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 31 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
15. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट को शामिल करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त मुद्दे में सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में पहले ही माननीय सेस्टेट द्वारा निर्णय ले लिया गया है। माननीय अधिकरण सभी तथ्यों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि चूंकि मेल्ट फार्म में अमोनियम नाइट्रेट के कोई आयात नहीं हैं और घरेलू उद्योग 0.83जी/सीसी से अधिक के घनत्व वाले ठोस रूप में अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन कर रहा है, अतः आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में दूसरी वस्तु पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।

“हमने सभी पक्षों को सुना है और अपील रिकॉर्ड देखें हैं। हम संबद्ध सामानों के भारतीय आयातक/प्रयोक्ता द्वारा दायर अपील को लेते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में विनिर्मित सामानों की स्थिति और प्रकृति संबद्ध देश के हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। वस्तुतः, इंडोनेशियाई निर्यातक द्वारा कोई शिकायत अथवा अपील नहीं है। इंडोनेशिया में विनिर्मित सामानों की प्रकृति की सही वास्तविक स्थिति के संबंध में स्पष्ट स्थिति रखे बिना भारतीय आयातक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता। किसी भी दशा में हम नोट करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने खुद ही तर्क दिया है कि अमोनियम नाइट्रेटमेल्ट रूप में आयात नहीं किया जा सकता। चूंकि 0.83 से अधिक के घनत्व वाले ठोस अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन और बिक्री है, अतः दूसरी वस्तु को आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु मानना अनुपयुक्त है। यह रिकॉर्ड किया जाता है कि केवल ऐसी स्थिति में, जहां देश में ठोक अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन न हो वहां अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट को आयातित उत्पाद की समान वस्तु माना जा सकता है। आवेदक के इस दावे के संदर्भ में कि अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड को अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट में से परिवर्तित किया जाता है, यह देखा जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मेल्ट से ठोस अमोनियम नाइट्रेट के ऐसे उत्पादन का कोई सत्यापनीय साक्ष्य नहीं दिया है। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी उस ठोस अमोनियम नाइट्रेट को घरेलू उद्योग की ओर लेने की स्थिति में नहीं थे। पीटी काल्टिम नाइट्रेट, इंडोनेशिया के दावे के संबंध में हम नोट करते हैं कि उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए और केवल कुछ तर्क प्रस्तुत किए। कंपनी द्वारा निर्यातित आठ सामानों 2017 के एडी/51864 के संबंध में कोई सत्यापनीय सूचना नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीटी काल्टिम नाइट्रेट, इंडोनेशिया को उनके द्वारा दायर अपूर्ण-निर्यातक के उत्तर के मद्देनजर असहयोगी माना है।

16. अधिकरण ने यह भी नोट किया है कि यदि समान वस्तु अर्थात् देश में ठोस रूप में अमोनियम नाइट्रेट का कोई उत्पादन नहीं था तो तभी जो वस्तु सभी दृष्टि से समान नहीं है और जांचाधीन वस्तु अर्थात् मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट से बारीकी से समानता रखने वाली विशेषताएं नहीं हैं, को समान वस्तु माना जा सकता है। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष छूट याचिका भी 6 अगस्त, 2018 के आदेश द्वारा खरिज कर दी गई है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वर्तमान निर्णायक समीक्षा में संशोधित नहीं किया जा सकता। अतः, वर्तमान जांच में विचाराधीन जांच का क्षेत्र वही है जो पूर्व जांच में था, उसने मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
17. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कम घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निर्णायक समीक्षा के स्तर पर बड़ा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कम घनत्व वाला अमोनियम नाइट्रेट संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। कम घनत्व वाला अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग, घनत्व, कीमत तथा गुण-धर्मों के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद की तुलना में पृथक उत्पाद है। कम घनत्व वाला अमोनियम नाइट्रेट वाणिज्यिक रूप से विस्फोटक अथवा औद्योगिक अमोनियम नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है। कम घनत्व वाले नाइट्रेट की तेल सोखने और प्रतिधारण क्षमता के कारण यह प्रयोग विस्फोटक और प्रयोग के लिए खतरनाक है। दूसरी ओर, विचाराधीन उत्पाद उर्वरक ग्रेड के अमोनियम नाइट्रेट अथवा तकनीकी ग्रेड के अमोनियम नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद कम छिद्रिल, कम तेल सोखने वाला होता है, इसलिए यह प्रयोग के लिए सुरक्षित है। कम घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट और विचाराधीन उत्पाद, दोनों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बिल्कुल भिन्न हैं।

चूंकि कम घनत्व वाला अमोनियम नाइट्रेट एक भिन्न उत्पाद है, अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता।

18. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास 0.87जी/सीसी से अधिक के अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे को पूर्व जांच के दौरान पहले ही हल कर लिया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने सत्यापित किया कि घरेलू उद्योग के पास 0.94जी/सीसी तक के अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करने की क्षमता है।
19. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक विशेषताओं विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकारीय एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों का वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में 0.85जी/सीसी से अधिक के घनत्व वाले एएन ठोस को ही शामिल किया जा सकता है, तथापि समान वस्तु के क्षेत्र में आधार का निर्धारण करने के लिए एएन के सभी रूपों को शामिल किया जाना चाहिए।
 - ख. आवेदक ने देश में अमोनियम नाइट्रेट के अन्य उत्पादकों से संबंधित सूचना रोकी है, उसने भारत में एकमात्र उत्पादक होने का गलत दावा किया है। गुजरात वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी देश में अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादक हैं, जो उत्पादकों की वेबसाइट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से सिद्ध है। घरेलू उद्योग का आधार इन उत्पादकों के उत्पादन को शामिल करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए था।
 - ग. विजय गैस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुखदेव केमिकल्स, मौनी नाइट्रोकेम, डालमिया केमिकल्स और मच्छर इंडस्ट्रीज भी ठोस रूप में उत्पादन कर रहे हैं।
 - घ. विनिर्माताओं के नाम और आवेदक और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की मात्रा से संबंधित सूचना भी प्राधिकारी द्वारा पैट्रोलियम और एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी आर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) से मंगाई जाए। हाल के मामलों में, यथा – पीएसवाई और विटामिन सी के मामले में प्राधिकारी ने ऐसी सूचना मंगाई थी।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में, आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. स्मार्टकेम टेक्नोलॉजिस लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पादक के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है, और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।
 - ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, आवेदक ने पहले ही प्रकट कर दिया है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भारत में अमोनियम नाइट्रेट के अन्य उत्पादक हैं। तथापि इनमें से कोई भी उत्पादक ठोस रूप में अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माता नहीं है।
 - ग. आधार के निर्धारण के लिए एएन मेल्ड का विनिर्माण करने के उत्पादन पर विचार करना पाटनरोधी नियमावली, प्राधिकारी के विगत जांच परिणाम और सेस्टेट द्वारा दिए गए निर्णय के असंगत है।

घ विजय गैस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुखदेव केमिकल्स, मौनी नाइट्रोजन, डालमिया केमिकल्स और मच्छर इंडस्ट्रीज एएन मेल्ट को एएन ठोस में परिवर्तित करने वाले हैं। अतः, उन्हें संबद्ध सामानों का उत्पादक नहीं माना जा सकता। लाइसेंसधारी परिवर्तक केवल संबद्ध सामानों के “प्रसंस्करणकर्ता” हैं और इसीलिए, प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार समान वस्तु के “घरेलू उत्पादक” नहीं माने जा सकते।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी भारत में संबद्ध सामानों के विनिर्माता हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त कंपनियां मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण करती हैं क्योंकि मेल्ट रूप में अमोनियम नाइट्रेट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा गया है, अतः उपर्युक्त कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता।

24. अन्यहितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि विजय गैस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुखदेव केमिकल्स, मौनी नाइट्रोकेम, डालमिया केमिकल्स और मच्छर इंडस्ट्रीज ठोस रूप में एएन के उत्पादक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके संबंध में केवल अनुरोध किए हैं, परंतु कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त कंपनियां केवल अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट को ठोस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अतः उपर्युक्त कंपनियां परिवर्तक हैं और विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माता नहीं हैं तथा तदनुसार उन्हें समान वस्तु के घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता।

25. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान वस्तु का एक ही उत्पादक अर्थात् आवेदक है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं है और उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक ने मांग, उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग, आयातों का बाजार हिस्सा, पाटित कीमतों पर निर्यात, मांग की तुलना में पाटित कीमतों पर निर्यात, मांग की तुलना में क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात, भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों में क्षमता, भारतीय मांग की तुलना में संबद्ध देशों में निर्यात योग्य क्षमता, भारतीय मांग की तुलना में संबद्ध देशों में बेकार क्षमता, भारत में मांग की तुलना में भारतीय कीमतों से कम पर निर्यात के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. आवेदक व्यापार सूचना 10/2018 के तहत अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है क्योंकि उसने अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के देशवार आकलन, कैप्टिव खपत, आरएंडडी खर्चों, निर्यात कीमत प्रति यूनिट और खरीद मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।
- ग. आवेदक ने हितबद्ध पक्षकारों को लेन-देनवार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं जो एक्सोटिक डेकरप्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टेट के निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है।

- घ. ईरान के लिए आवेदक ने निर्मित सामान्य मूल्य अपनाया है, परंतु कच्ची सामग्री की कीमत और खपत मानदंड गोपनीय रखे गए हैं, जिन्हें प्राधिकारी ने स्वीकार किया है।
- ड. आवेदक ने याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और विलगन करार तथा भंडार मालसूची नीति के उद्धरण संपादित किए हैं।
- च. आवेदक उनके द्वारा किए गए भारी निवेश को प्रकट करने में विफल रहा जिसका अर्थ यह है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- छ. अपीलीय अधिकरण ने विट्रिफाइड टाइलों के मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना केवल इसलिए गोपनीय माने जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई है और उन्होंने गोपनीयता के दावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए हैं।
- ज. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली और व्यापार सूचनाओं का उल्लंघन किया है और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, एटीएमए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य में निर्णयों के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। उन्होंने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने मौखिक सुनवाई के समय प्रस्तुत पेपर-बुक परिचालित नहीं की है और न ही आईएचएस मार्केट रिपोर्ट परिचालित की है और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है और न ही अगोपनीय सार उपलब्ध कराया है, लेन-देनवार रूसी सीमाशुल्क आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्यातक उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर में संगत सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं।
- ख. निर्यातक ने भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और प्रश्नावली के उत्तर में अपने ही विवरणों का विरोध किया है।
- ग. निर्यातकों ने निष्पादन मानदंडों, वितरण के चैनलों, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में समायोजनों, संबद्ध पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद, देशवार उत्पादन, मांग और निर्यात, कारपोरेट ढांचा, उत्पादित उत्पादों की सूची, लेखांकन परिपाटियों, स्वामित्व, वित्तीय संपर्कों/संयुक्त उद्यमों, विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पाद विशिष्टियों, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, कच्ची सामग्री की कीमतों, संविदागत बिक्री और लगाई गई ब्याज लागत के आधार के संबंध में, अत्यधिक गोपनीय का दावा किया है।
- घ. आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने उत्तर के अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त प्रकटन करने के लिए निर्यातकों को विनिर्देश दें।
- ड. निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के कारण आवेदक के पास निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर की पूर्णता के संबंध में स्पष्टता नहीं है और प्राधिकारी उसकी जांच करें।
- च. आवेदक के हितों के प्रति घोर पूर्वाग्रह किया गया है क्योंकि गोपनीयता के संबंध में उनके अनुरोधों को स्वीकार करने अथवा रद्द करने के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- छ. निर्यातक द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के कारण आवेदक यह पहचान करने में असमर्थ है कि क्रिस्टेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ड्रेमूर फर्टिलाइजर्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और राइनो रॉक लिमिटेड द्वारा किसके उत्पाद निर्यात किए गए हैं।
- ज. यूरोकेम ग्रुप द्वारा दायर उत्तर का अगोपनीय रूपांतर कमी वाला है क्योंकि उन्होंने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना के लिए कोई समायोजन सूचित नहीं किए हैं। यदि गोपनीय उत्तर में कोई समायोजन सूचित नहीं किए जाते हैं तो उसे अपूर्ण होने के कारण रद्द किया जाना चाहिए।

- झ. निर्यातकों ने रूसी उत्पादकों द्वारा आस्ट्रेलिया और यूक्रेन को निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में सूचना छिपाई है।
- ञ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत आवेदक ने याचिका के अगोपनीय रूपांतर में दावा की गई गोपनीयता के लिए तर्क दिए हैं क्योंकि आवेदक एकल उत्पादक हैं, अतः उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग प्रवृत्ति के रूप में सांझा किए गए हैं।
- ट. चूंकि आवेदक एकमात्र उत्पादक है, अतः मांग के प्रकटन से घरेलू बिक्री का प्रकटन होगा, इसीलिए मांग साझा नहीं की गई है। तदनुसार, मांग के संबंध में बाजार हिस्सा, क्षमताएं और निर्यात साझा नहीं किए जा सकते। विलगन करार व्यापार स्वामित्व वाली सूचना होने के कारण साझा नहीं की गई है।
- ठ. आवेदक ने व्यापार सूचना 07/2018 में उल्लिखितानुसार पीडीएफ फॉर्म में आयात आंकड़े देने का अपना दायित्व पूरा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हितों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है क्योंकि वे सीधे ही डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
- ड. चूंकि ईरान के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है, अतः कच्ची सामग्री की कीमत और खपत मानदंड साझा नहीं किए जा सकते क्योंकि वे व्यापार संवेदी सूचनाएं हैं।
- ढ. आवेदक बनाम निर्यातक की गोपनीयता के दावों के बीच तुलना ये दर्शाएगी कि आवेदक ने सभी संगत सूचनाएं प्रकट की हैं और निर्यातकों ने सभी व्यावहारिक सूचना छुपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य किया है।
- ण. संस्थापित क्षमता, कैप्टिव खपत, आरएंडडी व्यय, निर्यात कीमत प्रति यूनिट, व्यापार स्वामित्व की सूचना, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता।
- त. याचिका में कोई प्रपत्र अथवा विशेष प्रश्न नहीं था जिसमें किए गए निवेश के संबंध में सूचना के लिए पूछा गया हो। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक ने वह सूचना नहीं छिपाई क्योंकि वह सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों की पहुंच में थी।
- थ. आईएचएस मार्केट रिपोर्ट और रूसी सीमा शुल्क आंकड़ों, दोनों का अगोपनीय रूपांतर सार उपलब्ध कराया गया है। तथापि, आवेदक वार्षिक रिपोर्ट और आंकड़े साझा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है क्योंकि यह तीसरे पक्षकार की सूचना है। चूंकि यह सूचना शुल्क का भुगतान करने पर सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, अतः अन्य हितबद्ध पक्षकार उसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- द. आवेदक ने पेपरबुक नहीं बनाई है परंतु दस्तावेजों के संकलन पर विश्वास किया था। जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया है वे सार्वजनिक पटल पर मौजूद हैं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की आसान पहुंच में हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“ गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को, जहां भी जरूरी था, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सार्वजनिक फाइल में घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन पैरामीटरों और क्षति पैरामीटरों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है। पद्धति के अनुसार, कारोबार संवेदनशील सूचना को गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता।
31. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी दावों पर विचार किया है और इस संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकृति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने का निर्देश दिया है।
32. हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने भारत में मांग, भारत में मांग के संबंध में विषय देशों में क्षमता, भारतीय मांग के संबंध में विषय देशों में निर्यात योग्य क्षमता, भारतीय मांग के संबंध में विषय देशों में निष्क्रिय क्षमता, भारत में मांग के संबंध में भारतीय मूल्यों से कम निर्यात के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि चूंकि आवेदक एकमात्र उत्पादक है, इसलिए मांग के संबंध में मांग, क्षमताओं और निर्यात के प्रकटीकरण से घरेलू बिक्री का खुलासा होगा। इसलिए, प्राधिकारी देश में मांग के संबंध में दावा की गई गोपनीयता को व्यवसाय संवेदनशील गोपनीय जानकारी के रूप में स्वीकार करता है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक ने रूझानों या मांग के रूप में जानकारी का एक गैर-गोपनीय सारांश प्रदान किया है।
33. डी-मर्जर समझौते के प्रकटीकरण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और इसमें व्यवसाय मालिकाना जानकारी शामिल है। इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी सूचना पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।
34. इस आरोप के संबंध में कि आवेदक ने आईएचएस बाजार रिपोर्टों और रशियन कस्टम डाटा के संबंध में अतिशय गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना तृतीय पक्षकार सूचना है, आवेदक जिसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। हालांकि, ट्रेड नोटिस 01/2013 की अनिवार्यताओं के अनुसरण में, आवेदक द्वारा भरोसा की गई सूचना का एक अगोपनीय पाठ साझा किया गया था।
35. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने ईरान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कच्चे माल की कीमत और खपत मानदंडों को साझा नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित किया गया है। चूंकि, घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमत और खपत मानदंड कारोबार संवेदी सूचना है, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना के लिए गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है।
36. डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक देशों से भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के साथ आंकड़ों को साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने सौदावार आयात आंकड़ों की पूरी सूची उपलब्ध कराई है। यह भी नोट किया गया है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआई एंड एस से स्वतंत्र रूप से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपने स्वयं के दावों को दर्ज करा सकते हैं। प्राधिकारी धारित करते हैं कि आयात आंकड़ों को साझा करने और उन्हें अधिप्राप्त करने की प्रक्रिया ट्रेड नोटिस सं. 07/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में दी गई है। यह व्यवस्था की गई है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए क्रमबद्ध

आयात आंकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है, और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआई एंड एस से सौदे से सौदे संबंधी कच्चे आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकारी देने की मांग कर सकते हैं। निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार घोषणा/वचनबंध के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को क्रमबद्ध आयात आंकड़ों को सुलभ कराया गया था। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की गई प्रक्रिया सुसंगत है, सभी पक्षकारों और जांच में एक समान है और सभी पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कराती है।

च. विविध मुद्दे

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. दिनांक 8 अक्तूबर, 2021 के पत्र के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष बल दिया है कि जांच शुरुआत होने के बाद अनुशेष के साथ एक याचिका दायर की गई थी जिसका अर्थ है कि जांच अपर्याप्त सूचना के आधार पर आरंभ की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने याचिका का एक संमेकित अगोपनीय पाठ दायर किया था, जिसमें जांच शुरुआत से पूर्व दायर किया गया एक पत्र शामिल था। जिसका अर्थ है कि अगोपनीय पाठ को गोपनीय पाठ के साथ दायर नहीं किया गया था।
- ख. प्रयोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई से तीन दिन पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तर साथ ही लिखित अनुरोध परिचालित किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ लिखित निवेदनों के अगोपनीय पाठ के परिचालन के लिए समय सीमा के संबंध में कोई अनिवार्य दिशा-निर्देश नहीं हैं।
- ग. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा पांच वर्षों के बाद शुल्क का अन्यथा रूप से अनिवार्य समाप्ति के प्रति एक अपवाद है जो यूएस- कोरोजन-रेसिसटेंट स्टील निर्णायक समीक्षा में और यूएस ऑयल कंट्री टेब्यूलर गुड्स में अपीलीय निकाय की विचारधारा के अनुरूप है।
- घ. इंडोनेशिया को इस आधार पर संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा गया था कि इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं होता।
- ड. आवेदक ने प्राधिकारी को यह विश्वास करने के लिए भ्रमित किया है कि जॉर्जियन, ईरानियन और रशियन मूल का माल सिंगापुर, उजबेकिस्तान, स्विटजरलैंड और यूएई जैसे देशों के जरिए भारत को भेजा जा रहा है। रशियन कस्टम आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और केवल महानिदेशक, रक्षोपाय और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का ही संदर्भ लिया जाना चाहिए।
- च. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये आयात आंकड़े भ्रामक हैं और प्रोफार्मा IV क में उपलब्ध कराए गए संबद्ध देशों की आयात मात्रा और याचिका के आयात विवरण में उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों के बीच विरोधाभास है। इसके अलावा, डीजीसीआई एंड एस के अनुसार आयात आंकड़ों से तुलना किए जाने पर, आवेदक द्वारा दायर किए गए आंकड़ों में विसंगतियां हैं।
- छ. कृपया एक्रॉन को इस जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए क्योंकि इसने ट्रेड नोटिस संख्या 11/2018 में उपलब्ध कराए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी के पास स्वयं को पंजीकृत किया था।
- ज. जांच शुरुआत अधिसूचना दर्शाती है कि प्राधिकारी रिकार्ड पर किसी साक्ष्य के बिना, स्वयं ही जांच शुरुआत के चरण पर पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं।
- झ. आवेदक ने संबद्ध देश से इंडोनेशिया को हटाने के बाद संशोधित आवेदन का अगोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया है।
- ञ. जॉर्जियन उत्पादक के पास कोई अधिशेष/निष्क्रिय क्षमता नहीं है।
- ट. पीओआई और पिछले दो वर्षों के दौरान भारत को जॉर्जिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ था, समान मामला इंडोनेशिया के साथ भी था। जॉर्जियन उत्पादक ने भारत में संबद्ध वस्तुओं को पाटित नहीं किया है।

- ठ. किसी अन्य देश ने जॉर्जिया के विरुद्ध कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं किया है।
- ड. इस तथ्य के बावजूद संबद्ध देशों के दायरे से इंडोनेशिया को संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा गया था कि इंडोनेशियन उत्पादकों के पास 32% के समकक्ष महत्वपूर्ण निष्क्रिय/अधिशेष क्षमता उपलब्ध थी।
- ढ. जॉर्जिया के पास बहुत सीमित क्षमता है, जिसका पहले ही अधिक उपयोग किया जा चुका है। तदनुसार, पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- ण. आवेदक उद्योग ने संभावना के अस्तित्वहीन मामले को सिद्ध करने के लिए अपने आवेदन में जॉर्जियन उत्पादन और मांग के संबंध में विरोधाभासी और भ्रामक दावे किए हैं।
- त. नोवोमोस्कोवस्क पर शून्य शुल्क लगाया गया था, जो एक रूसी उत्पादक है। इसके बावजूद, वे पीओआई के दौरान केवल एक मामूली सी मात्रा का निर्यात कर पाए क्योंकि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

38. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनिवार्यताओं के अनुरूप परिशिष्टों के साथ याचिका का समेकित अगोपनीय पाठ दायर किया था कि हितबद्ध पक्षकारों के अपने हितों की रक्षा करने और अनुरोध करने का अवसर प्राप्त है।
- ख. आवेदक को उसके हितों की रक्षा करने से रोकने के लिए, आयातकों की ओर से एल एंड एल लॉ ऑफिसिस द्वारा उत्तर के अगोपनीय पाठ के परिचालन में जानबूझकर विलंब किया गया। एस विलंब के कारण, आवेदक उत्तरों की जांच करने और सुनवाई के दौरान अर्थपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत करने में असमर्थ था।
- ग. उत्तरों के विलंब से परिचालन प्रयोक्ताओं द्वारा एक जानबूझकर इच्छा से किया गया कार्य था। उत्तर सुनवाई से पूर्व अंतिम कार्य दिवस के अंत में प्रस्तुत किए गए थे।
- घ. समय पर ढंग से अनुरोधों को परिचालित करने की असफलता ऐसे पक्षकारों को जांच में प्रतिभागिता करने से रोक सकती थी और उनके उत्तर को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने चाहिए। यूएस-हॉट-रोलड स्टील, यूएस- कोरोजन- रेसिसटेंट स्टील और यूएस- ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर गुड्स का सहारा लिया गया है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, इंडोनेशिया को संबद्ध देशों से हटा दिया गया था क्योंकि इंडोनेशिया से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं था।
- च. दिनांक 29 नवंबर, 2021 को आयोजित मौखिक सुनवाई निष्फल थी क्योंकि आवेदक को अपने हितों की रक्षा करने और प्राधिकारी के समक्ष उचित मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करने से इंकार कर दिया गया।
- छ. प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क का परिहार करने के लिए किसी भिन्न देश से नौकांतरण (ट्रांसशिपमेंट) के द्वारा भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
- ज. प्राधिकारी से संबद्ध वस्तुओं के नौकांतरण (ट्रांसशिपमेंट) के संबंध में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ("पीईएसओ") और सीमा शुल्क प्राधिकारियों से संगत सूचना की मांग करने का अनुरोध किया गया है।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विवाद के संबंध में, आवेदक ने स्पष्ट किया था कि कोई लिंकिंग त्रुटि थी और सही आंकड़े प्रोफार्मा IV क में थे।

- ज. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने को निश्चित करने का मापदंड संभावना संबंधी मापदंड है न कि उन वर्षों की संख्या, जब वह शुल्क स्थापित किया गया है। बहुत सी जांचों में प्राधिकारी ने अवधि के बावजूद पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है जैसे कास्टिक सोडा, फिनोल, मेलामाइन, पीटीएफई, 1-फिनायल, 3-मिथाइल, 5- पाईराजोलोन, फ्रंट एक्सेल बीम और स्टियरिंग नकल, एक्सीलोनीट्राइल बुटाडीन रबर एनबीआर, एफडीवाई, नाइलॉन, टायर कोर्ड फैब्रिक आदि।
- ट. पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की जांच करने के बाद जांच आरंभ की गई थी। जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(ख) की अनिवार्यताओं के अनुसार वर्तमान जांच आरंभ की गई है।
- ठ. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ जरूरी साक्ष्य समान गुणवत्ता और मात्रा में नहीं हो सकते हैं जैसे शुल्क को अंतिम रूप से लागू करने के लिए अपेक्षित हैं। इस संबंध में मैक्सको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट पर गुएटेमाला निश्चयात्मक पाटनरोधी उपायों पर भरोसा किया गया है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, यह दावा नहीं किया जा सकता कि भारतीय सीमा शुल्क आंकड़े विश्वसनीय हैं किंतु रशियन कस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं।
- ढ. सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने पाया कि उजबेकिस्तान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की गलल घोषणा की गई थी और वे ईरानियन मूल के पाए गए तथा तदनुसार, संग्रहित पाटनरोधी शुल्क इसी पर वसूल किया गया है।
- ण. आवेदक ने, प्राधिकारी द्वारा मामले की पहले ही शुरुआत कर दिए जाने के पश्चात एक संबद्ध देश के रूप में इंडोनेशिया को हटाए जाने के पश्चात कोई नया आवेदन दायर नहीं किया है। पाटनरोधी नियमावली में ऐसे नए आवेदन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

39. इस तर्क के संबंध में कि जांच अपर्याप्त जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने परिशिष्ट पोस्ट दीक्षा के साथ याचिका का गैर-गोपनीय संस्करण दायर किया है, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग ने गोपनीय संस्करण के साथ याचिका का एक गैर-गोपनीय संस्करण दायर किया है। घरेलू उद्योग ने जांच शुरू करने से पहले विभिन्न स्रोतों से आयात के बारे में जानकारी दायर की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हितबद्ध पक्षों के हितों की रक्षा की जाती है और उन्हें आवेदन के बाद दायर की गई अतिरिक्त जानकारी पर टिप्पणी दायर करने की अनुमति दी जाती है, इस तरह की जानकारी को हितबद्ध पक्षों को परिसंचरण के लिए याचिका के लिए एक परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया था।
40. हितबद्ध पक्षों द्वारा जॉर्जिया को विषय देशों के दायरे से बाहर करने के लिए किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर, पीओआई और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान भारत को विषय वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया गया है अर्थात्, कोई डंपिंग और परिणामस्वरूप क्षति नहीं है। पीओआई के दौरान एकमात्र जॉर्जियाई निर्माता के साथ कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है जैसा कि आवेदक के साथ-साथ हितबद्ध पार्टियों द्वारा साक्षा की गई जानकारी से स्पष्ट है। इसके अलावा, पीओआई के बाद छह महीने के दौरान एकमात्र जॉर्जियाई निर्माता के साथ कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि किसी अन्य देश ने जॉर्जिया के खिलाफ कोई एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया गया है कि जॉर्जिया से विषय वस्तुओं के आयात पर समाप्त होने की अनुमति दिए जाने की घटना में डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का कोई सबूत नहीं है। तदनुसार, जॉर्जिया को विषय देशों से बाहर रखा गया है और जांच केवल रूस और ईरान में उत्पन्न होने वाले या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात के संबंध में आयोजित की गई है (इसके बाद "विषय देशों" के रूप में संदर्भित)।
41. इस तर्क के संबंध में कि जॉर्जिया को एक विषय देश के रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक जॉर्जिया में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और पीओआई और पिछले दो वर्षों के दौरान जॉर्जिया से भारत में विषय वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ है।

42. प्राधिकारी के पास रिकार्ड पर दी गई सूचना के अनुसार, निर्यातक की क्षमता पीओआई के दौरान *** मीट्रिक टन और पीओआई के बाद छह महीनों के दौरान *** मीट्रिक टन है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पीओआई के दौरान और पीओआई के बाद के छह महीनों के दौरान उत्पादक/निर्यातक का उत्पादन क्रमशः *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन है।
43. प्राधिकारी ने उपर्युक्त उपबंधित तथ्यों की जांच करने के बाद नोट किया है कि निर्यातक अपनी अधिकतम क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और पीओआई और पीओआई के बाद के छह महीनों के दौरान उसके पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं थी। यह भी नोट किया गया है कि किसी अन्य देश ने जॉर्जिया के खिलाफ कोई एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है। प्राधिकारी नोट करता है कि जॉर्जिया से विषय वस्तुओं के आयात पर समाप्त होने की अनुमति दी गई घटना शुल्क में डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी जॉर्जिया से निर्यात किए गए निर्माता / निर्यात के संबंध में जांच को समाप्त करता है। इस दृढ़ संकल्प के उद्देश्य के लिए विषय देशों में रूस और ईरान शामिल हैं।
44. जहां तक विभिन्न देशों से विषय वस्तुओं के ट्रांसशिपमेंट का संबंध है, प्राधिकारी ने विषय देशों में उत्पन्न होने वाली विषय वस्तुओं के ट्रांसशिपमेंट की कुछ प्रविष्टियों को नोट किया है। चूंकि डीजीसीआई एंड एस डेटा केवल खेप के देश की रिपोर्ट करता है और मूल देश नहीं, प्राधिकारी ने नीचे रूस से निर्यात की मात्रा निर्धारित करने के लिए रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
45. इस तर्क के संबंध में कि डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के अनुसार कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि डीजीसीआई एंड एस डेटा में दी गई सूचना के अनुसार रूस से आयात की मात्रा रूसी सीमा शुल्क आंकड़ों के साथ-साथ भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार निर्यात की मात्रा से बहुत कम है। भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार टी वह डेटा से पता चलता है कि रिपोर्ट की गई मात्रा रूसी सीमा शुल्क डेटा में तुलनीय है।
46. जहां तक लगाए गए शुल्कों की अवधि का संबंध है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल एक समान अवसर सृजित करना और हानिकारक डंपिंग के खिलाफ घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है। वर्तमान जांच ड्यूटी की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए शुरू की गई है। यदि प्राधिकारी को यह पता चलता है कि शुल्कों के अभाव में डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो शुल्क लगाने की अवधि या जांच की संख्या के बावजूद डंपिंग रोधी शुल्कों को बढ़ाया जाएगा।
47. पीजेएससी एक्रॉन के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि पीजेएससी एक्रोन को वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्ष के रूप में पंजीकृत किया गया है और निर्यातक की ओर से किए गए प्रस्तुतियों को रिकार्ड पर लिया गया है। हालांकि, चूंकि निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया है, इसलिए वर्तमान पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
48. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच रिकार्ड पर किसी भी सबूत के बिना शुरू की गई है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक ने कर्तव्यों की अनुपस्थिति में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का दावा करते हुए एक विधिवत प्रमाणित आवेदन प्रदान किया है। जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्कों के संबंध में सूर्यास्त की समीक्षा जांच शुरू करने की आवश्यकता से खुद को संतुष्ट किया, जो वर्तमान कर्तव्यों की समाप्ति की अनुमति दिए जाने पर डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना को स्थापित करता है।
49. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया को हटाने के बाद संशोधित याचिका दायर नहीं की है, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग ने एक विधिवत दस्तावेज याचिका दायर की थी जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी, उसी का गैर-गोपनीय संस्करण सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित किया गया है। एक बार जांच शुरू होने के बाद, जांच शुरू होने के बाद कोई नया आवेदन नहीं हो सकता है। प्राधिकारी ने आंकड़ों के आधार पर नीचे अपनी टिप्पणियां की हैं, जिसमें इंडोनेशिया और जॉर्जिया के लिए विषय देशों के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
50. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में भिन्नता है। प्राधिकारी नोट करता है कि रिकार्ड पर डेटा को प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है और उसके बाद इसके तहत दिए गए विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, आवेदक से डेटा में किसी भी असंगतता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

51. घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि उपयोगकर्ताओं ने उनके द्वारा दायर प्रतिक्रिया के गैर-गोपनीय संस्करण को देर से प्रसारित किया। प्राधिकारी प्रतिक्रियाओं के संचालन में विलंब को अवांछनीय पाता है। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, किसी भी हितबद्ध पार्टी के हितों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने न्याय के हित में लिखित प्रस्तुतियों की तारीख के बाद भी सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

52. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
- क. रूस के लिए अनुमानित सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य में परिवर्तन के लिए समायोजित पिछले वर्षों के डेटा पर आधारित है, जो डंपिंग दिखाने के लिए तिरछे समायोजन को इंगित करता है।
 - ख. रूसी सीमा शुल्क डेटा का उपयोग निर्यात मूल्य पर काम करने के लिए किया गया है क्योंकि इसमें कीमत बहुत कम है और महासागर माल ढुलाई और अंतर्देशीय परिवहन शुल्क के प्रति असामान्य रूप से उच्च समायोजन को कृत्रिम उच्च पाटन मार्जिन पर काम करने के लिए दिखाया गया है।
 - ग. आवेदक ने ईरान से निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए उज्बेकिस्तान डेटा और कुछ डीआरआई जांच डेटा का उपयोग किया, क्योंकि डीजीसीआई एंड एस डेटा कोई डंपिंग नहीं दिखाएगा।
 - घ. वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार आयातित अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें लगभग 650 अमरीकी डालर पीएमटी - 670 पीएमटी हैं, जिसका अर्थ है कि कोई डंपिंग नहीं है।
 - ङ. याचिका में उल्लिखित विशेष बाजार की स्थिति को पाटन मार्जिन के निर्धारण में पहले ही ध्यान में रखा जा चुका है। लेकिन उत्पादन और डंप करने की क्षमता, कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगी जो आवेदक ने स्थापित नहीं की है।
 - च. नियम 23 (1 बी) के संदर्भ में सूर्यास्त की समीक्षा जांच में पहली बार "विशेष बाजार की स्थिति" के अस्तित्व की जांच नहीं की जा सकती है और केवल बदली हुई परिस्थितियों की समीक्षा में जांच की जा सकती थी।
 - छ. सरकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली किसी भी विशेष बाजार स्थिति की जांच केवल एक एंटी-सब्सिडी जांच के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि इंडोनेशिया से अनकोटेड कॉपियर पेपर के मामले में उल्लेख किया गया है।
 - ज. प्राधिकारी ने मूल जांच में गजप्रोम के माध्यम से गैस की खरीद के बारे में आवेदक के तर्क को स्वीकार नहीं किया था, और आवेदक ने अपील में इसे चुनौती नहीं दी थी। इस मुद्दे को अब इस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

53. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं
- क. यूरोकेम समूह द्वारा दायर प्रतिक्रिया के गैर-गोपनीय संस्करण की कमी है क्योंकि इसने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की उचित तुलना के लिए किसी भी समायोजन की सूचना नहीं दी है। यदि गोपनीय प्रतिक्रिया में कोई समायोजन रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो इसे अपूर्ण होने के लिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
 - ख. यूरोकेम ट्रेडिंग जीएमबीएच द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी एक प्रत्यक्ष बिक्री व्यय है क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है और इस प्रकार, निर्यात मूल्य निर्धारित करते समय इसे कम किया जाना चाहिए।

- ग. प्राधिकारी से यह जांचकरने का अनुरोध किया जाता है कि जेएससी अज़ोट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड रूस के जीएएपी के अनुसार हैं या नहीं। यदि रिकॉर्ड GAAP के अनुसार नहीं हैं, तो उत्पादन की लागत को निर्माता के रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- घ. भारत को निर्यात के लिए रॉफर्ट ऑफशोर एसएएल द्वारा प्राप्त कमीशन को निर्यात मूल्य के निर्धारण में समायोजित किया जाना चाहिए।
- ङ. रूस में प्राकृतिक गैस की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित और काफी कम कीमतों पर उत्पादकों के लिए उपलब्ध है जैसा कि परिषद विनियमन 661/2008 में यूरोपीय आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। इसलिए निर्यातकों के घरेलू बाजार में उत्पादन लागत और कीमतें दब जाती हैं। प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों की उत्पादन लागत को अपरिवर्तित कीमतों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।
- च. रूस के लिए सामान्य मूल्य रूस में बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि जांच की अवधि के लिए कीमतें उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पिछले वर्ष की कीमतों को समायोजित किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने दावे का खंडन करने के लिए कोई सबूत प्रदान नहीं किया है।
- छ. डीजीसीआई एंड एस डेटा खेप के देश को दर्शाता है न कि मूल देश इसलिए, आवेदक ने रूस से भारत को कुल निर्यात निर्धारित करने के लिए रूसी सीमा शुल्क डेटा का उपयोग किया है।
- ज. रूसी सीमा शुल्क डेटा शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना करने के लिए एक बेहतर स्रोत है क्योंकि यह एफओबी स्तर पर निर्यात रिकॉर्ड करता है जबकि डीजीसीआई एंड एस डेटा में रिपोर्ट किया गया निर्यात मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर व्यापारी ने भारत में बेचा है। इसलिए, व्यापारी के मार्जिन, साथ ही साथ किए गए खर्चों को डीजीसीआई एंड एस डेटा में रिपोर्ट किए गए मूल्य में जोड़ा जाता है।
- झ. चूंकि विषय वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा रहा है और डीजीसीआई एंड एस डेटा में केवल खेप का देश है, न कि मूल देश, आवेदक ने द्वितीयक स्रोतों के अनुसार मूल देश की पहचान की है।
- ञ. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि अमोनियम नाइट्रेट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य \$ 650-670 प्रति मीट्रिक टन हैं, विषय देशों से भारत में आयात मूल्य \$ 244 प्रति मीट्रिक टन है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण विषय वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है।
- ट. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों के विपरीत, पाटन-रोधी नियम के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित सभी दायित्व सूर्यास्त की समीक्षा जांच पर लागू होते हैं।
- ठ. चूंकि जॉर्जिया और ईरान के उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह जॉर्जिया से आयात पर प्रति-डंपिंग शुल्क की समान मात्रा को जारी रखे और याचिका में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ईरान के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य निर्धारित करे।
- ड. ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है, जो एसजी एंड ए खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।
- ढ. प्राधिकारी याचिका में दायर की गई जानकारी के आधार पर ईरान से आयात के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित कर सकता है जिसमें आवेदक ने आयात डेटा में रिपोर्ट किए गए सीआईएफ मूल्य को लिया है और महासागर माल ढुलाई, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई और कमीशन के लिए समायोजित किया है।
- ण. अन्य हितबद्ध पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कि रूस में एक विशेष बाजार की स्थिति है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए इस पर विचार करे।

- त. चूंकि पीजेएससी एक्रॉन ने विषय वस्तुओं को भारत को निर्यात नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नहीं दिया जा सकता है।
- थ. अन्य हितबद्ध पक्षों के तर्कों के विपरीत, आवेदक ने प्राधिकारी से प्रदान की गई सब्सिडी की प्रतिउत्पादनीयता और मात्रा की जांच करने का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्राकृतिक गैस की राज्य-नियंत्रित कीमतों के कारण रूस में एक विशेष बाजार की स्थिति मौजूद है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

54. अधिनियम की धारा 9ए (1) (सी) के अनुसार, किसी लेख के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, जैसे लेख के लिए जब निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत किया जाता है जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है; नहीं तो
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह की वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा -
- (क) उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; नहीं तो
- (ख) उप-धारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रशासनिक, विक्रय और सामान्य लागतों के लिए और लाभ के लिए उचित परिवर्धन के साथ-साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी है;
- परन्तु मूल देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहाँ वस्तु को केवल निर्यात के देश के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं किया गया है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में उसके मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

55. प्राधिकारी ने विषय देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई। विषय देश से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातों ने निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है:

- क. एज़ोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क)
- ख. सिस्टेक इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड।
- ग. ड्रेमूर फर्टिलाइजर्स ओवरसीज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
- घ. यूरोकेम ट्रेडिंग जीएमबीएच
- ङ. यूरोकेम ट्रेडिंग रूस, एलएलसी
- च. जेएससी अज़ोट, केमेरोवो
- छ. जेएससी नेविन्नोमिस्की एज़ोट नेविन्नोमिस्क
- ज. रॉफर्ट ऑफशोर एसएएल
- झ. राइनो रॉक लिमिटेड
- ञ. एसबीयू नाइट्रोटेड एजी

56. दीक्षा के चरण में रूसी सीमा शुल्क डेटा पर निर्भरता के संबंध में, प्राधिकारी पाता है कि अन्य देशों के माध्यम से रूस से निर्यात किए गए माल के ट्रांसशिपमेंट के कारण, डीजीसीआई एंड एस डेटा ने पूरी मात्रा पर कब्जा नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी पाता है कि रूसी सीमा शुल्क डेटा ने रूस से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए हैं। तथापि, प्राधिकारी ने सहयोग करने वाले उत्पादकों के लिए उनके द्वारा दायर की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।

57. इस तर्क के संबंध में कि प्राकृतिक गैस की राज्य-नियंत्रित कीमतों के कारण रूस में एक विशेष बाजार की स्थिति है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि वर्तमान जांच ईरान, जॉर्जिया और रूस से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा है। पिछली जांच में घरेलू उद्योग ने उसी विवाद को उठाया था जिसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से संबोधित किया गया था। घरेलू उद्योग ने पिछली जांच के बाद से प्राकृतिक गैस की कीमतों के संबंध में परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं दिखाया है।

छ.4 रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

एजोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क), जेएससी नेविन्नोमिस्की एजोट नेविन्नोमिस्क समूह के लिए सामान्य मान

58. रूस के सहकारी उत्पादकों और निर्यातक एजोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क) और जेएससी नेविन्नोमिस्की एजोट द्वारा दायर आंकड़ों से, यह ध्यान दिया जाता है कि उन्होंने असंबंधित ग्राहकों को व्यापारियों के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यातक ने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की बिक्री की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित किया है। यदि लाभ कमाने वाले लेन-देन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादक/निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों को घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा के लिए सामान्य मूल्य पर पहुंचने पर विचार किया गया है। एजोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क) और जेएससी नेविन्नोमिस्की एजोट नेविन्नोमिस्क के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य इतना निर्धारित नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।

जेएससी अज़ोट, केमेरोवो समूह के लिए सामान्य मान

59. रूस के सहकारी निर्माता और निर्यातक जेएससी अज़ोट केमेरोवो द्वारा दायर आंकड़ों से, यह ध्यान दिया जाता है कि इसने असंबंधित ग्राहकों को व्यापारियों के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यातक ने असंबंधित ग्राहकों को घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन की बिक्री की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित किया है। यदि लाभ कमाने वाले लेन-देन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा के लिए सामान्य मूल्य पर पहुंचने पर विचार किया गया है। जेएससी अज़ोट, केमेरोवो के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य तो निर्धारित नीचे तालिका में उल्लेख किया गया है।

रूस से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

60. रूस के गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मान का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.5 रूस के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

एजोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क), जेएससी नेविन्नोमिस्की एजोट नेविन्नोमिस्क Group के लिए निर्यात मूल्य

61. निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया में, उत्पादक / निर्यातक ने कहा कि पीओआई के दौरान उन्होंने व्यापारी के माध्यम से भारत में असंबंधित पार्टियों को *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने पूर्व-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए आगे समायोजन किए हैं। तदनुसार, प्रस्तावित निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है जिसमें पाटन मार्जिन गणना और प्रतिशतता दर्शाई गई है।

जेएससी अज़ोट, केमेरोवो (निर्माता) समूह के लिए निर्यात मूल्य

62. निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया में, निर्माता / निर्यातक ने कहा कि पीओआई के दौरान उन्होंने व्यापारियों के माध्यम से भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने पूर्व-कारखाना स्तर पर निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए आगे समायोजन किए हैं। तदनुसार, प्रस्तावित निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है जिसमें पाटन मार्जिन गणना और प्रतिशतता दर्शाई गई है।

रूस से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

63. रूस के गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.6 ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

64. प्राधिकारी ने नोट किया है कि ईरान के किसी भी उत्पादक / निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर नहीं की हैं। ईरान में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के संदर्भ में सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, उचित रूप से समायोजित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को जोड़ना शामिल है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मान का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.7 ईरान से आयात के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

65. प्राधिकारी ने नोट किया है कि ईरान के किसी भी उत्पादक / निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है। ईरान के उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए, विषय देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्य की गणना डीजीसीआई एंड एस लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। महासागर भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय माल भाड़ा और कमीशन के लिए समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों में आयात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को कम रिपोर्ट किए जाने के संबंध में नोट करता है। ईरान से किसी भी प्रतिक्रिया और अन्य पक्षों से किसी भी जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के रूप में माना है, और इसके आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।

छ.8 पाटन मार्जिन

66. उपर्युक्त के रूप में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, विषय देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और यह नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है। पाटन मार्जिन इस प्रकार निर्धारित सहकारी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए नकारात्मक है। तथापि, विषय देशों में गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन कम से कम होने से ऊपर है।

क्र.सं.	निर्माता का नाम	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निर्यात दाम (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
रूस						
1	एज़ोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क) और जेएससी नेविन्नोमिस्की एज़ोट नेविन्नोमिस्क	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
2	जेएससी अज़ोट, केमेरोवो	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
3	गैर-सहकारी / अवशिष्ट निर्यातकों	***	***	***	***	10-20
ईरान						
1	गैर-सहकारी / अवशिष्ट निर्यातकों	***	***	***	***	70-80

ज. क्षति और कारण लिंक का मूल्यांकन और डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

67. क्षति, कारण लिंक और डंपिंग और क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
- क. जॉर्जिया और इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं है और ईरान से आयात भी कम हो गया है, और केवल रूस से आयात में वृद्धि हुई है।
 - ख. जांच के दौर में रूस से आयात में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन कुल आयात में भारी गिरावट आई है। आवेदक ने दावा किया है कि वास्तविक डेटा प्रदान किए बिना मांग में गिरावट आई है।
 - ग. आवेदक को लाभ के प्रकाश में मूल्य अंडरकटिंग की जांच की जानी चाहिए, जो महामारी के दौरान को छोड़कर सकारात्मक और महत्वपूर्ण रही है।
 - घ. आवेदक अपने उत्पादों को उत्पादन की लागत की तुलना में बहुत अधिक कीमत देने में सक्षम है, इस प्रकार, मूल्य दमन / अवसाद का सवाल नहीं उठता है।
 - ङ. क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई और महामारी के कारण जांच की अवधि के दौरान ही गिरावट आई।
 - च. जांच की अवधि और उसके पूर्ववर्ती वर्ष को छोड़कर जांच अवधि के दौरान आवेदक की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, जो दोनों महामारी से प्रभावित हुए थे। आवेदक ने कथित डंप किए गए आयातों के लिए बाजार हिस्सेदारी नहीं खोई है।
 - छ. आवेदक को जांच की अवधि को छोड़कर इन्वेंट्री के संचय का सामना नहीं करना पड़ा, जो महामारी के कारण था।
 - ज. आवेदक कुशलतापूर्वक अपनी पूंजी को मुनाफे में परिवर्तित कर रहा है और महामारी तक अपनी पूंजी के इष्टतम उपयोग के साथ पर्याप्त वित्तीय लाभ कमा रहा था।
 - झ. यहां तक कि अगर आयात डंप की गई कीमतों पर बढ़ रहे हैं, तो वे एंटी-डंपिंग झूटी द्वारा पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं, और इस प्रकार, क्षति के कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
 - ञ. आवेदक की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में स्वयं के प्रवेश के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट व्यवसाय रिकॉर्ड उच्च प्रदर्शन पर है और इस व्यवसाय के लिए कोई खतरा नहीं है।
 - ट. आवेदक ने विशेष रूप से 2020 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि महामारी के प्रकोप के बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण कई स्थानों पर इसके संचालन को कम कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था।
 - ठ. जबकि बैलेंस शीट से पता चलता है कि तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट के शुद्ध लाभ में सुधार हुआ है, रिकॉर्ड पर डेटा जांच की अवधि के दौरान मुनाफे में गिरावट दिखाता है।
 - ड. अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए, आवेदक ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है जिसके 2024 में उत्पादन में जाने की उम्मीद है।
 - ढ. भारत में आयात की आवश्यकता के लिए एक बड़ा मांग आपूर्ति अंतर है, जो पीईएसओ वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है।
 - ण. घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण होती है, जिसके कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, और प्रति इकाई निश्चित लागत में वृद्धि हुई। प्राधिकारी को निर्यात बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट के कारण घरेलू बिक्री की लागत में समायोजन करना चाहिए।
 - त. क्षति विश्लेषण की अवधि में रोजगार और घरेलू वित्त लागत असामान्य रूप से बढ़ी है, भले ही क्षमता समान रही हो।

- थ. व्याज लागत और मूल्यहास और परिशोधन व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण आवेदक की लाभप्रदता प्रभावित हुई थी।
- द. आवेदक द्वारा प्रदान किया गया आयात डेटा भ्रामक है और प्रोफार्मा आईवीए में प्रदान किए गए विषय देशों की आयात मात्रा और याचिका के आयात विवरण में प्रदान किए गए आयात डेटा के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इसके अलावा, डीजीसीआई एंड एस के अनुसार आयात आंकड़ों की तुलना में आवेदक द्वारा दायर आंकड़ों में विसंगतियां हैं।
- ध. आवेदक ने संभावना दिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जॉर्जिया के लिए उत्पादन और क्षमता के विभिन्न आंकड़ों का उल्लेख किया है।
- न. आवेदक ने स्वीकार किया है कि उन्हें अन्य स्रोतों से आयात के कारण भी क्षति नहीं लगी; और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- प. क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी 'सकारात्मक साक्ष्य' के आधार पर 'उद्देश्य परीक्षा' के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य से रहित है। प्रदान की गई जानकारी पाकिस्तान - बीओपीपी फिल्म के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, क्योंकि यह सट्टा है।
- फ. चूंकि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है, इसलिए भारत एक मूल्य-लेने वाला है, और निर्यातक बाजार में उच्च मूल्य वसूलने में सक्षम होंगे।
- ब. यदि भारत दूसरों की तुलना में अधिक मूल्य आकर्षक बाजार है, तो यह साबित करने के लिए जाता है कि कोई डंपिंग नहीं है और भारतीय बाजार घरेलू उत्पादकों को उच्च कीमत पर बेचने और लाभ कमाने में सक्षम होने की अनुमति देता है।
- भ. केवल अतिरिक्त क्षमताओं का अस्तित्व संभावना नहीं दिखाता है। आवेदक को आसन्न भविष्य में डंपिंग की संभावना स्थापित करने के लिए घरेलू बाजार और बाहरी बाजार में मूल्य रुझानों को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करना चाहिए जो संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकारी और व्हाइट सीमेंट, रबर केमिकल्स, एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी में दृष्टिकोण के साथ संगतता में है। चीन पीआर और PX-13 (6PPD) से चीन पीआर और कोरिया आरपी से. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, विषय देश स्वयं विचाराधीन उत्पाद की कमी का सामना कर रहे हैं।
- म. जॉर्जिया से निर्यात का 100% सामान्य मूल्य स्थापित किए बिना या निर्यात के लिए पूर्ण डेटा प्रदान किए बिना डंप किए जाने का आरोप लगाया गया है।
- य. आवेदन में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान में क्षमता और ईरान में घरेलू मांग पूरी तरह से संतुलित है और कोई निर्यात योग्य अधिशेष नहीं है।
- कक. अनुप्रयोग अधिशेष क्षमताओं के लिए जानकारी के स्रोत को इंगित नहीं करता है।
- खख. आवेदक का दावा है कि हालांकि रूस में उत्पादक पहले से ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता रखते हैं, वे आगे की क्षमता विस्तार की योजना बना रहे हैं। वहीं आवेदक ने एक खबर संलग्न की है जो दिखाता है कि रूस में घरेलू मांग बढ़ रही है।
- गग. जेएससी अज़ोट, केमेरोवो ने विषय वस्तुओं को भारत में डंप नहीं किया है, और इसकी कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।
- घघ. जेएससी रुस्तवी अज़ोट की कोई अधिशेष क्षमता नहीं है, उसने भारत को विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, और डंपिंग में संलग्न नहीं किया है। इसलिए, डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- डड. आवेदक का दावा है कि एक बार शुल्क हटा दिए जाने के बाद विषय देशों से निर्यात करने वाले तीसरे देश को भारत की ओर मोड़ दिया जाएगा जो उसके अपने बयान के विपरीत है कि इस तरह के आयात डंप किए गए मूल्यों पर होंगे।

- चच. आवेदक का दावा है कि रूस से निर्यात करने वाले तीसरे देश का 86% भी इसके लिए कोई डेटा प्रदान किए बिना डंप की गई कीमतों पर है।
- छछ. याचिका में अन्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपायों के कारण व्यापार की संभावित मात्रा और उसके मूल्य के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
- जज. चूंकि आवेदक एक प्रमुख खिलाड़ी है, और आयात, जो एंटी-डंपिंग ड्यूटी का सामना कर रहे थे, को आवेदक के मूल्य स्तर पर समायोजित करना पड़ा। इसलिए, आयात कम कीमत पर थे। तथापि, एक बार शुल्क हटा दिए जाने के बाद, आयात मूल्य में वृद्धि होगी।
- झझ. किसी अन्य देश ने जॉर्जिया के खिलाफ एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है।
- ञञ. ऑस्ट्रेलियाई आयोग ने 20 मई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से रूस के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क वापस ले लिया है, जो रूस से डंपिंग और क्षति की कोई संभावना साबित नहीं करता है।
- टट. अमोनिया की आपूर्ति में 2021 में काफी गिरावट आई है, जबकि कीमतों में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि विषय आयात में और गिरावट की संभावना है।
- ठठ. कई ठंडे देशों में उर्वरक के रूप में उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति की कमी के कारण उत्पाद की कीमतों में वृद्धि हुई है। यदि एंटी-डंपिंग शुल्क रद्द कर दिए जाते हैं, भले ही आयात घरेलू बाजार में प्रवेश कर जाए, वे आवेदक के लिए हानिकारक नहीं होंगे।
- डड. उत्तरी अमेरिका और यूरोप भारत की तुलना में निर्यातकों के लिए बहुत अधिक मूल्य आकर्षक हैं क्योंकि उत्पाद की कमी के कारण कीमतों में बिना किसी गिरावट के वृद्धि देखी गई है।
- ढढ. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान विषय देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के साथ अमोनियम नाइट्रेट की सूची पर चुप्पी साध रखी है।
- णण. आवेदक को अन्य देशों से आयात से क्षति पर अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करना चाहिए, और आगे अन्य सभी हितबद्ध पक्षों को इस पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
- तत. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसने 225 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश किया है और अपनी क्षमता को 1200 मीट्रिक टन प्रति दिन से बढ़ाकर 1320 मीट्रिक टन प्रति दिन कर दिया है, और आगे इसे 1400 मीट्रिक टन प्रति दिन तक बढ़ाने की उम्मीद है।
- थथ. घरेलू उद्योग के मूल्यहासित संयंत्र घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली अक्षमताओं का कारण हैं, जो नकद लाभ में परिलक्षित होता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

68. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, कारण लिंक और डंपिंग और क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. जबकि आधार वर्ष की तुलना में मांग स्थिर रही है, रूस से आयात में 25% की वृद्धि हुई है।
- ख. अन्य हितबद्ध पार्टियों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है कि अमोनियम नाइट्रेट व्यवसाय रिकॉर्ड उच्च पर है। चूंकि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 से संबंधित है, और एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू है, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय आसन्न भविष्य में अमोनियम नाइट्रेट व्यवसाय के लिए कोई खतरा नहीं था।
- ग. जबकि बैलेंस शीट एक पूरे के रूप में कंपनी के मुनाफे को संदर्भित करता है, जांच के लिए प्रस्तुत डेटा केवल विषय वस्तुओं से संबंधित है।
- घ. बुल्गारिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन से विषय वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आयात की कीमत रूस से आयात की कीमत से काफी अधिक है।
- ङ. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, ईरान से आयात पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 10 गुना से अधिक बढ़ गया। जॉर्जिया में उत्पादक भारत में विषय वस्तुओं को उचित कीमतों पर बेचने में

- असमर्थ हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि भले ही उनके पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं, जॉर्जिया से आयात ने शुल्क लगाने के बाद बंद कर दिया है।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, रिकॉर्ड पर डेटा से पता चलता है कि कई आयात लेनदेन घरेलू उद्योग की कीमत से नीचे हैं, यहां तक कि एंटी-डंपिंग झूठी लागू होने के साथ भी। रूस से आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सेदारी खो दी है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में गिरावट आई है।
- छ. यदि आवेदक द्वारा किए गए लाभ के आलोक में मूल्य कटौती का मूल्यांकन किया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि जहां आवेदक ने ***% लाभ अर्जित किया, वहीं जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती ***% थी। डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति के कारण घरेलू उद्योग के लाभ में कमी आने की संभावना है और इससे हानि होने की संभावना है।
- ज. आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2019-20 में महामारी से पहले गिरावट आई थी।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, 2019-20 महामारी से प्रभावित नहीं हुआ था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस अवधि में मांग और आयात में वृद्धि हुई है। 2019-20 में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।
- ञ. अन्य हितबद्ध दलों की प्रस्तुतियों के विपरीत, इन्वेंट्री का संचय महामारी के कारण मांग में गिरावट के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग का उत्पादन देश में मांग की तुलना में बहुत कम था और इसलिए, इन्वेंट्री का संचय केवल विषय आयात के कारण होता है।
- ट. जबकि अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं लगी है, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है कि डंपिंग और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- थ. एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग की योजनाएं क्षति की संभावना की अनुपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। इसके बजाय, यह इंगित करता है कि डंपिंग को रोकने की आवश्यकता है, ताकि नए संयंत्र को ब्रेक-ईवन तक पहुंचने की अनुमति मिल सके।
- ड. अतिरिक्त क्षमताओं को दर्शाने के लिए प्राधिकारी को आईएचएस फॉरेकन नाइट्रेट्स रिपोर्ट प्रदान की गई है। जबकि स्रोत का नाम साक्षा किया गया है, वही तीसरे पक्ष की जानकारी अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ साक्षा नहीं की जा सकती है।
- ढ. अन्य हितबद्ध पक्ष सकारात्मक साक्ष्य की कमी को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं या यह कि प्राधिकारी एक उद्देश्य परीक्षा करने में असमर्थ है।
- ण. विषय देशों में उत्पादकों ने लागू एंटी-डंपिंग शुल्कों के बावजूद विषय वस्तुओं को डंप करना जारी रखा है।
- त. जॉर्जिया और रूस में उत्पादक डंप और हानिकारक कीमतों पर अन्य देशों को विचाराधीन उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। जॉर्जिया से ***% निर्यात और रूस से ***% निर्यात डंप की गई कीमतों पर हैं।
- थ. रूस से विषय आयात मांग में कमी में वृद्धि हुई है। लागू एंटी-डंपिंग झूठी के अभाव में निर्यात में और वृद्धि होने और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी छीनने की संभावना है।
- द. उक्त देशों में क्षमताएं और उत्पादन मांग से अधिक हैं जो उत्पादकों को अत्यधिक निर्यात उन्मुख बनाते हैं। ईरान और रूस में उत्पादकों के पास निष्क्रिय क्षमता है जो भारत में मांग का 5 गुना है।
- ध. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक ने मूल्य प्रवृत्तियों के साथ-साथ भारत में निरंतर डंपिंग, जॉर्जिया और रूस में उत्पादकों द्वारा अन्य देशों को डंप किए गए और हानिकारक आयात के संबंध में जानकारी प्रदान की है, भारत एक मूल्य आकर्षक बाजार होने के साथ-साथ वर्तमान कीमतों पर आयात के मामले में संभावित क्षति भी है।
- न. अन्य हितबद्ध पार्टियों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक ने जॉर्जिया से प्राधिकारी को अन्य देशों में निर्यात डेटा प्रदान किया है। जॉर्जिया के उत्पादन की लागत एसजी एंड ए खर्चों और उचित मुनाफे के लिए

समायोजित घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। जॉर्जिया से अन्य देशों को निर्यात उत्पादन की अनुमानित लागत से कम है।

- प. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह जॉर्जिया से अन्य सभी देशों को डंप किए गए और हानिकारक लेन-देन के औसत निर्यात मूल्य पर विचार करे ताकि भारत को संभावित निर्यात मूल्य निर्धारित किया जा सके जैसा कि प्राधिकारी द्वारा चीन पीआर से नमनीय आयरन पाइपों के आयात पर सूर्यास्त समीक्षा जांच में पहले किया गया था।
- फ. अन्य हितबद्ध पार्टियों की प्रस्तुतियों के विपरीत, लेख केवल सामान्य मूल्य दिखाता है। जबकि लेख 2019 से संबंधित है, आवेदक ने 2020 के लिए डेटा प्रदान किया है जो मांग में वृद्धि के बावजूद अधिशेष क्षमताओं को दर्शाता है।
- ब. भारत विषय देशों में उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है क्योंकि भारत को निर्यात ईरान से कुल निर्यात का 75%, जॉर्जिया से कुल निर्यात का 30% और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से पहले रूस से कुल निर्यात का 7% था।
- भ. रूसी उत्पादकों ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और यूक्रेन में रूस से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के कारण बाजार खो दिया है।
- म. ऑस्ट्रेलियाई आयोग द्वारा जारी अंतिम रिपोर्ट से पता चलता है कि उक्त जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक था जो साबित करता है कि रूस में उत्पादक अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगे हुए हैं।
- य. केवल तथ्य यह है कि किसी अन्य देश ने जॉर्जिया से आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया है, यह इंगित नहीं करता है कि डंपिंग और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- कक. भारत एक अधिक मूल्य आकर्षक बाजार है क्योंकि जॉर्जिया और रूस से अन्य देशों को महत्वपूर्ण निर्यात भारत में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर है।
- खख. भारत के मूल्य आकर्षण से पता चलता है कि निर्यातकों के पास अपने निर्यात को भारत में मोड़ने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है क्योंकि वे अन्य देशों को निर्यात की तुलना में भारत में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। डंपिंग की संभावना का विश्लेषण सामान्य मूल्य के संबंध में किया जाना चाहिए न कि तीसरे देश की कीमतों के संबंध में।
- गग. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में आयातों से घरेलू उद्योग के मूल्यों को दबाने और कम करने की संभावना है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विषय आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों में कमी कर रहे हैं, भले ही पाटनरोधी शुल्क लागू है।
- घघ. घरेलू उद्योग लागू एंटी-डंपिंग झूठी के कारण ही मुनाफा कमाने में सक्षम रहा है। डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में, घरेलू उद्योग को आयात मूल्यों से मेल खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रकार, मूल्य दमन / अवसाद की संभावना है।
- ड.ड.. विषय आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। शुल्कों की समाप्ति के मामले में, कीमतों में और गिरावट की संभावना है।
- चच. प्राकृतिक गैस की कम कीमतों के कारण, रूस में उत्पादक भारतीय बाजार के लिए उचित मूल्य की तुलना में काफी कम कीमतों पर विषय वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम हैं।
- छछ. डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में विषय देशों में पर्याप्त क्षमता भारतीय उद्योग को बाजार से मिटाने के लिए पर्याप्त है। घरेलू उद्योग को बाजार में बनाए रखने के लिए कीमतों को कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा और ऐसे परिदृश्य में नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न रिकॉर्ड करने की संभावना है।

- जज. रूस में उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार, भारत उनके लिए एक छोटा बाजार है। इसके बावजूद, रूस से निर्यात भारत में मांग के 20% से अधिक के लिए लेखांकन कर रहे हैं, यहां तक कि लागू कर्तव्यों के साथ भी जो स्पष्ट रूप से रूस में उत्पादकों द्वारा आयोजित अधिशेष क्षमताओं को दर्शाता है।
- झझ. वर्तमान जांच में एक नए शिपर की भागीदारी स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार में उत्पादकों की रुचि को दर्शाती है।
- ञञ. अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
- टट. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक को निर्यात की मात्रा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है जिसे भारत में डायवर्ट किया जा सकता है। रूस से निर्यात रूस में उत्पादन के समान गति से नहीं बढ़ रहा है।
- ठठ. भारतीय बाजार मूल्य लेने वाला नहीं है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि शुल्क लगाने से पहले मांग और आपूर्ति के अंतर के बावजूद, निर्यातकों को उत्पाद बेचने के लिए डंपिंग का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा, विषय वस्तुओं की वैश्विक क्षमताएं वैश्विक मांग से अधिक हैं जो अधिशेष पैदा करती हैं।
- डड. संभावना विश्लेषण एक पूरे देश के लिए आयोजित किया जाना आवश्यक है, न कि व्यक्तिगत उत्पादकों के रूप में। यदि प्राधिकारी जेएससी अज़ोट, केमेरोवो द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर भरोसा करने का फैसला करता है, तो इसे पहले घरेलू उद्योग को बताया जाना चाहिए। निर्यातक ने सभी प्रासंगिक जानकारी गोपनीय होने का दावा किया है जिसके कारण आवेदक अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है।
- ढढ. जेएससी रूस्तवी अज़ोट ने वर्तमान जांच में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। चूंकि प्रश्नावली के भाग-II में निर्यातक द्वारा संभावित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए प्राधिकारी कृपया उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा कर सकता है जैसा कि शुद्ध टेरेफ्थालिक एसिड के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच में आयोजित किया गया है।
- णण. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, उर्वरक एक मौसमी उत्पाद हैं और उर्वरकों की मांग में वृद्धि प्रकृति में अस्थायी है।
- तत. चूंकि भारत में क्षति विश्लेषण की अवधि में रूसी आयात में वृद्धि हुई है, इसलिए यह स्पष्ट है कि रूसी उत्पादकों को उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में बाजार की अधिक आवश्यकता है।
- थथ. आवेदक ने डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में इसे उपलब्ध सभी जानकारी प्रदान की है। प्राधिकारी उनके द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार विषय देशों में उत्पादकों के साथ विचाराधीन उत्पाद की सूची का विश्लेषण कर सकता है। संभावना दिखाने के लिए अनुलग्नक - II में सूचीबद्ध प्रत्येक पैरामीटर को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- दद. घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को अलग-अलग किया गया है। आवेदक द्वारा निर्यात क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान नगण्य रहा है और आवेदक को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।
- धध. अन्य देशों से आयात के लिए क्षति के लिए अलग-अलग डेटा अप्रासंगिक है क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं लगी है।
- नन. यह कहते हुए कि डंपिंग-रोधी शुल्क से पीड़ित आयातों को आवेदक के मूल्य स्तर पर समायोजित करना था, अन्य हितबद्ध पक्षों ने स्वीकार किया है कि निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क को अवशोषित कर लिया है। ऐसे में ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए। रूसी उत्पादक सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के कारण कीमत में हेरफेर करने में सक्षम हैं।
- पप. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त की समीक्षा होने के नाते, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलीय निकाय द्वारा देखे गए संभावित डंपिंग और संभावित क्षति के बीच एक कारण लिंक स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है -

- मेक्सिको से OCTG पर एंटीडम्पिंग उपाय। फिर भी, किसी भी अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना नहीं है।
- फफ. रोजगार और वित्त लागत में वृद्धि अप्रासंगिक है क्योंकि आवेदक ने क्षति का दावा नहीं किया है। जांच की अवधि में ब्याज लागत के साथ-साथ लाभप्रदता में भी गिरावट आई है।
- बब. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक ने उच्च लाभ अर्जित किया क्योंकि इसके पौधों का मूल्यह्रास होता है, इस प्रकार यह अक्षमता का कारण नहीं हो सकता है।
- भभ. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदक के अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र को महामारी के कारण किसी भी बंद का सामना नहीं करना पड़ा।
- मम. गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए अमूर्त परिसंपत्तियों को बाहर नहीं रखा जा सकता है जैसा कि अनुबंध-III के प्रावधानों से स्पष्ट है कि पाटनरोधी नियमों और व्यापार उपचारात्मक जांच के लिए प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के लिए।
- यय. यहां तक कि अगर अमूर्त परिसंपत्तियों को गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए बाहर रखा जाता है, तो उन्हें क्षति के निर्धारण के लिए बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

69. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के संबंध में हितबद्ध पक्षों के तर्कों और जवाबी तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।
70. इसके अनुलग्नक-II के साथ पठित नियमों के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... डंप किए गए आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस तरह के आयात के परिणामस्वरूप प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।
71. नियमों के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में म्यूटेटिस म्यूटांडिस लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग के निष्पादन से पता चलता है कि वर्तमान क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान उसे क्षति नहीं लगी है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं।
72. इस विवाद के संबंध में कि आवेदक के वित्तीय विवरण एक बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं, प्राधिकारी नोट करता है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से कंपनी से संबंधित हैं। पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II के पैरा (vi) के उपबंधों के अनुसार, घरेलू उद्योग के पैरामीटरों पर आयात के प्रभाव का मूल्यांकन केवल इसी अनुच्छेद के संबंध में किया जाएगा।
- "(vi) डंप किए गए आयात के प्रभाव का मूल्यांकन इसी तरह की वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाएगा जब उपलब्ध डेटा उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों की बिक्री और मुनाफे जैसे मानदंडों के आधार पर उस उत्पादन की अलग-अलग पहचान की अनुमति देता है। यदि उस उत्पादन की ऐसी अलग पहचान संभव नहीं है, तो डंप किए गए आयातों के प्रभावों का आकलन सबसे संकीर्ण समूह या उत्पादों की श्रेणी के उत्पादन की परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद शामिल है, जिसके लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सकती है।"*
73. इसलिए, डंप किए गए आयातों के प्रभाव का विश्लेषण समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाना आवश्यक है जहां अलग-अलग डेटा इस तरह की परीक्षा की अनुमति देता है। केवल उन मामलों में जहां सामूहिक आंकड़ों के कारण ऐसी परीक्षा संभव नहीं है, प्राधिकारी को सबसे संकीर्ण समूह या उत्पादों की श्रेणी के उत्पादन की जांच करने की आवश्यकता होती है जिसमें घरेलू उत्पाद शामिल हैं। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता के संदर्भ में प्रदर्शन के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रदान किए गए हैं। चूंकि इस तरह के अलग-अलग आंकड़े रिकॉर्ड पर हैं, और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हैं, इसलिए यह उपरोक्त पैरा (vii) के प्रावधानों के अनुसार, क्षति विश्लेषण का आधार होगा। तदनुसार, अपने कुल संचालन में आवेदक का प्रदर्शन प्रासंगिक नहीं है।

74. प्राधिकारी ने विषय देशों से आयात के कारण डंपिंग और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या आयात में, निरपेक्ष रूप से या उत्पादन या खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांचना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्य कम किया गया है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हुआ होता, एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, डंपिंग के परिमाण और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर नियमों के अनुलग्नक-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों की विभिन्न प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। इसके तहत प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।

I. मांग का आकलन / स्पष्ट खपत

75. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान जांच, मांग या स्पष्ट खपत के उद्देश्य से घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	99	95
विषय आयात	मीट्रिक टन	1,36,168	80,513	75,396	1,10,339
अन्य आयात	मीट्रिक टन	68,428	1,49,896	2,02,905	1,06,596
मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	114	100

76. यह देखा गया है कि विषय वस्तुओं की मांग 2019-20 तक बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट लंबे समय तक मानसून, सरकार में बदलाव के कारण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कम मांग और कोविड -19 महामारी के प्रभाव के कारण है जो अस्थायी है। यह अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

II. डंप किए गए आयातों का वॉल्यूम प्रभाव

77. डंप किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या डंप किए गए आयातों में या तो निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त लेनदेन-वार आयात डेटा, रूसी सीमा शुल्क डेटा और माल के ट्रांसशिपमेंट के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर भरोसा किया है। विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा और क्षति विश्लेषण की अवधि और जांच की अवधि के दौरान डंप किए गए आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
विषय आयात	मीट्रिक टन	1,36,168	80,513	75,396	1,10,339
ईरान	मीट्रिक टन	56,512	21,555	979	10,388
रूस	मीट्रिक टन	79,656	58,958	74,417	99,951
अन्य आयात	मीट्रिक टन	68,428	1,49,896	2,02,905	1,06,596
कुल	मीट्रिक टन	2,04,596	2,30,409	2,78,301	2,16,935

विषय देशों के संबंध में आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	44	46	74
खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	47	41	72
कुल आयात	%	77%	35%	27%	51%

78. यह देखा गया है कि:

- 2019-20 तक विषय आयात की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
- घरेलू उत्पादन के संबंध में विषय आयात में 2018-19 में गिरावट आई, और उसके बाद जांच की अवधि तक वृद्धि हुई।
- खपत के संबंध में विषय आयात में 2019-20 तक गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में वृद्धि हुई। कुल आयात में विषय आयात का हिस्सा भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण करता है।

III. डंप किए गए आयात का मूल्य प्रभाव

79. नियमों के अनुलग्नक II (ii) के अनुसार, कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्य में कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा हुआ होता, एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए। इस संबंध में, विषय वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ विषय देशों से आयात के अवतरित मूल्य के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत कम करना

80. मूल्य अंडरकटिंग निर्धारित करने के लिए, उत्पाद के लैंडेड मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों के शुद्ध के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें पूर्व-कारखाने के स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
1	आयात मात्रा	मीट्रिक टन	1,10,339
2	आयात मान	₹ लाख	20,046
3	सीआईएफ मूल्य	₹/ मीट्रिक टन	18,168
4	कस्टम शुल्क	%	8%
5	कस्टम शुल्क राशि	₹/ मीट्रिक टन	1,363
6	सीमा शुल्क पर उपकर	₹/ मीट्रिक टन	136
7	अवतरित मूल्य	₹/ मीट्रिक टन	19,667
8	निवल विक्रय मूल्य	₹/ मीट्रिक टन	***
9	कीमत कम करना	₹/ मीट्रिक टन	***
10	कीमत कम करना	%	***
11	कीमत कम करना	श्रेणी	10-20

81. यह ध्यान दिया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मूल्य कम करना विषय देशों के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाया है कि भारतीय बाजार को मूल्य-लेने वाला नहीं माना जा सकता है। मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद आयात कम कीमतों पर दर्ज हुआ है।
82. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मुनाफे के प्रकाश में मूल्य अंडरकटिंग का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि जबकि मूल्य में कमी केवल जांच की अवधि के लिए देखी जाती है, इस अवधि में लाभप्रदता के रुझान देखे जाते हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि चूंकि मूल्य में कमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, इसलिए डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को आयात मूल्यों से मेल खाने के लिए मजबूर होने की संभावना है। ऐसे में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ख. मूल्य दमन / अवसाद

83. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करता है या मूल्य वृद्धि को रोकता है जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होता, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	112
विक्रय मूल्य	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	107

84. यह ध्यान दिया जाता है कि बिक्री की लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री मूल्य में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

85. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, नियोजित पूंजी पर वापसी या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, डंपिंग के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

86. क्षति विश्लेषण की अवधि में क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
कुल उत्पादन (पीयूसी)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	102	95
क्षमता उपयोग: संयंत्र	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	107	96

घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	99	95

87. प्राधिकारी ने नोट किया है कि:

- घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति विश्लेषण की अवधि में स्थिर रही है।
- 2018-19 तक घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई, लेकिन इसके बाद गिरावट आई।
- तथापि, चूंकि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्वयं ही कमी आई थी, इसलिए जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में आई गिरावट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ख. बाजार हिस्सेदारी

88. डंप किए गए आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की जांच निम्नानुसार की गई है

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	86	95
विषय आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	42	70
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	286	379	229

89. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 में कम हो गई लेकिन जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई। इसी तरह, 2019-20 तक विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई। हालांकि, अन्य देशों से आयात ने 2019-20 तक बाजार में वृद्धि की।

ग. सूची

90. क्षति विश्लेषण की अवधि में घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	13	18	103

91. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की सूची में 2018-19 में गिरावट आई, लेकिन 2019-20 में वृद्धि हुई। इसके बाद, जांच की अवधि में इन्वेंट्री में वृद्धि हुई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी

92. क्षति विश्लेषण की अवधि में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और रिटर्न नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	112
विक्रय मूल्य	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	107
लाभ / हानि (हानि)	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	85	79
लाभ / हानि (हानि)	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	84	75
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	88	81
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	108	110

93. प्राधिकारी ने नोट किया है कि:

- 2019-20 और पीओआई में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2018-19 में बढ़ा है लेकिन 2019-20 में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
ब्याज से पहले लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	101	83
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	95	77
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	106	108

94. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी ध्यान दिया है कि वित्त और मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की ईबीआईडीटीए की प्रवृत्ति की जांच की है। प्राधिकारी नोट करता है कि कंपनी के ईबीआईडीटीए ने ऊपर दिए गए ब्याज से पहले लाभ के समान रुझानों का पालन किया है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
ईबीआईडीटीए	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	102	87

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

95. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कर्मचारियों	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	149	149
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/ प्रतिदिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	102	95
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/ संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	69	63
वेतन	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	111	127

96. यह ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए वेतन में क्षति विश्लेषण की अवधि में वृद्धि हुई है। उत्पादन में गिरावट के साथ जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कमी आई है।

च. वृद्धि

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	16	(12)	(8)
घरेलू बिक्री	%	-	12	(11)	(4)
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	%	-	2	(17)	(6)
नकद लाभ	%	-	10	(20)	(8)
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	-	72	(37)	2

97. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों ने 2018-19 में सुधार दिखाया, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। हालांकि, जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर रिटर्न में वृद्धि हुई है।

छ. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

98. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग भारत में विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए और निवेश कर रहा है। मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने के कारण घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है।

ज. डंपिंग का परिमाण

99. यह देखा गया है कि सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों से कोई डंपिंग नहीं की गई है, तथापि, गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों से डंपिंग सकारात्मक पाई गई है।

झ. डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

100. प्राधिकारी का मानना है कि यह एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, इस जांच का ध्यान निरंतर डंपिंग और परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है यदि एंटी-डंपिंग शुल्कों को समाप्त होने की अनुमति दी जाती है, भले ही कोई वर्तमान क्षति न हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क हानिकारक डंपिंग को समाप्त करने के इच्छित उद्देश्य की सेवा कर रहा है। इस संबंध में, इसी में डब्ल्यूटीओ पैनेल - फुटवियर ने पाया कि -

"मूल एंटी-डंपिंग जांच में, जांच अधिकारियों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या किसी सदस्य का घरेलू उद्योग डंप किए गए आयात से भौतिक रूप से घायल हो गया है। इस स्तर पर, दृढ़ संकल्प के समय "भौतिक क्षति" के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह निर्धारण अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, जो कुछ पिछली अवधि के लिए आवश्यक और प्रासंगिक कारकों से संबंधित जानकारी के आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, एक समाप्ति समीक्षा में, एक एंटी-डंपिंग उपाय कुछ समय के लिए जगह में रहा है, और जांच अधिकारियों को एक ताजा विश्लेषण के आधार पर, यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या उस उपाय की समाप्ति से क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।"

101. इस प्रकार, एक सूर्यास्त की समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी उपाय को रद्द करने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जो मूल जांच में क्षति के निर्धारण के विपरीत है। पी.टी. असाहिमास केमिकल्स बनाम नामित प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय [2015 (328) ई.एल.टी. 417 (ट्रिब्यूनल - डेल्ही)] के निर्णय में माननीय सेस्टेट द्वारा एक समान दृष्टिकोण लिया गया था, जिसमें यह आयोजित किया गया था -

"10. क्षति के निर्धारण के संबंध में, यदि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का वांछित प्रभाव पड़ता है, तो डंपिंग रोधी शुल्क प्रभावी होने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद की जाएगी। इसलिए, मूल्यांकन कि क्या क्षति जारी रहेगी, या पुनरावृत्ति, डंप किए गए आयात, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के अनुमानित स्तरों के आधार पर भविष्य की घटनाओं का एक काउंटर-तथ्यात्मक विश्लेषण शामिल होगा। इस प्रकार डीए को इस सवाल को संबोधित करना होगा कि क्या घरेलू उद्योग को फिर से भौतिक रूप से घायल होने की संभावना है, यदि कर्तव्यों को हटा दिया जाता है।"

11. उपर्युक्त कानूनी स्थिति के प्रकाश में, हमारा विचार है कि जिस प्रश्न को संबोधित किया जाना है वह यह नहीं है कि वर्तमान डंपिंग है या नहीं, लेकिन क्या शुल्क को रद्द करने के परिणामस्वरूप डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।"

102. इसलिए, सूर्यास्त की समीक्षा जांच के मामले में, घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति का अस्तित्व यह जांचने के लिए प्रासंगिक नहीं है कि कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता है या नहीं। एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि क्या मौजूदा उपायों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना मौजूद है।
103. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
104. इस तरह के एक संभावना विश्लेषण का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट तरीके उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमों के अनुलग्नक II के पैरा (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान किया गया है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, अर्थात्
- भारत में डंप किए गए आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

- ii. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में डंप किए गए निर्यातों में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;
- iii. चाहे आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हों जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक या दबाने वाला प्रभाव होगा, और संभवतः आगे के आयात के लिए मांग में वृद्धि होगी; और
- iv. लेख की सूची की जांच की जा रही है।

105. आयातकों ने तर्क दिया है कि आयात की कीमत कम है क्योंकि उन्हें एंटी-डंपिंग शुल्क और आवेदक की कीमतों के अनुसार अपनी कीमतों को समायोजित करना था। आयातकों ने आगे तर्क दिया है कि शुल्कों के अभाव में कीमतें बढ़ेंगी। तथापि, यह सुझाव नहीं देता है कि आयातों के डंप किए जाने या शुल्कों के अभाव में घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना नहीं है।
106. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जिनका डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना पर प्रभाव पड़ता है। संभावना के मापदंडों की परीक्षा निम्नानुसार है।

क. एंटी-डंपिंग झूटी के अस्तित्व के बावजूद डंपिंग जारी

107. प्राधिकारी ने नोट किया है कि लागू कर्तव्यों के बावजूद रूस और ईरान से विषय वस्तुओं का निरंतर और महत्वपूर्ण डंपिंग है। शुल्कों के अस्तित्व के दौरान निरंतर डंपिंग से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग के जारी रहने की संभावना का संकेत मिलता है।

ख. मांग में कमी और एंटी-डंपिंग झूटी लागू होने के बावजूद आयात में वृद्धि

108. यह ध्यान दिया जाता है कि 2018-19 में गिरावट के बाद, शेष क्षति की अवधि में विषय देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई, इसके बाद मांग में गिरावट के बावजूद। शुल्कों के बावजूद आयात में इस प्रकार की वृद्धि से पता चलता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में विषय आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।

विवरण	इकाइयों	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
रूस	मीट्रिक टन	79,656	58,958	74,417	99,951
ईरान	मीट्रिक टन	56,512	21,555	979	10,388
विषय आयात	मीट्रिक टन	1,36,168	80,513	75,396	1,10,339
मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	114	100

ग. तीसरे देश की डंपिंग

109. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय देशों में उत्पादक/निर्यातक भारत के अलावा तीसरे देशों में भी विषय वस्तुएं डंप कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर डेटा से पता चलता है कि रूस से तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात डंप की गई कीमतों पर हैं।

विवरण	जॉर्जिया	रूस	कुल
कुल निर्यात	4,29,433	78,82,381	83,11,814
डंप किए गए मूल्यों पर निर्यात	4,29,433	68,06,500	72,35,933
डंप किए गए मूल्यों पर निर्यात	100%	86%	87%
भारत में मांग के संबंध में डंप किए गए मूल्यों पर निर्यात	***	***	***
श्रेणी	90-100%	1300-1500%	1400-1600%
हानिकारक कीमतों पर निर्यात	424,259	7,185,514	7,609,773
हानिकारक कीमतों पर निर्यात	99%	91%	91%
भारत में मांग के संबंध में हानिकारक कीमतों पर निर्यात	***	***	***
श्रेणी	80-90%	1400-1500%	1500-1600%

स्रोत: व्यापार मानचित्र डेटा

घ. विषय देशों में उत्पादकों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएं

110. घरेलू उद्योग ने आईएचएस फर्टेकॉन नाइट्रेट्स रिपोर्ट नामक एक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट प्रदान की है जिसमें संबद्ध देशों में क्षमता, उत्पादन और मांग के संबंध में जानकारी शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास घरेलू मांग से अधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। उत्पादकों का उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनके पास महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएं रह जाती हैं।
111. घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जेएससी अजोट, केमेरोवो ने हाल ही में अपनी क्षमता का विस्तार 250 केटी तक किया है और आगे 790 केटी की क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है जिसे 2022 तक शुरू करने की योजना है और वर्तमान में स्थापित क्षमताओं के अलावा 1,140 केटी की कुल नई क्षमता को 2026 तक शुरू करने की योजना है।

हजार टन में आंकड़े

विवरण	जॉर्जिया	ईरान	रूस	कुल
क्षमता	450	221	11,306	11,977
उत्पादन	456	188	8,816	9,460
मांग	89	133	5,799	6,021
निष्क्रिय क्षमताएं	0	33	2,490	2,523
भारत में मांग	-	-	-	486
भारतीय मांग के संबंध में निष्क्रिय क्षमता	***	***	***	***
श्रेणी	शून्य	5-15%	500-550%	500-550%

स्रोत: बाजार अनुसंधान रिपोर्ट

ङ. उत्पादकों/निर्यातकों का निर्यात अभिविन्यास

112. आवेदक ने दावा किया है कि जॉर्जिया और रूस में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन संबंधित देशों में मांग से काफी अधिक है।

'000 मीट्रिक टन में आंकड़े

विवरण	जॉर्जिया	रूस	कुल
उत्पादन	456	8816	9272
मांग	89	5799	5888
निर्यात के लिए उत्पादन	367	3017	3384
निर्यात के लिए उत्पादन का हिस्सा	80%	34%	36%

स्रोत: बाजार अनुसंधान रिपोर्ट

च. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय

113. आवेदक ने दावा किया है कि रूसी उत्पादकों को यूरोपीय संघ और यूक्रेन में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ इस तरह के उपायों को लागू करने के कारण रूसी उत्पादकों के लिए एक अनाकर्षक बाजार बन सकता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में भी रूस से निर्यात के खिलाफ एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे केवल 2021 में रद्द कर दिया गया है। यह रेखांकित करता है कि रूस में निर्यातक अन्य देशों में भी डंपिंग प्रथाओं में संलग्न हैं।

छ. एक बाजार के रूप में भारत की कीमत आकर्षण

114. आवेदक ने दावा किया है कि जॉर्जिया और रूस में उत्पादकों के लिए अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार एक अधिक कीमत आकर्षक बाजार है क्योंकि उक्त देशों से महत्वपूर्ण निर्यात भारत में प्रचलित कीमतों से नीचे की कीमतों पर हैं।

विवरण	रुस
कुल निर्यात	78,82,381
भारतीय कीमतों से कम निर्यात	72,03,348
भारतीय कीमतों से कम निर्यात	91%
भारत में मांग के संबंध में भारतीय कीमतों से कम निर्यात	***
श्रेणी	1400-1600%

स्रोत: व्यापार मानचित्र डेटा

ज. संभावित मूल्य दमन या अवसाद

115. प्राधिकारी ने नोट किया है कि विषय आयात का उतरा हुआ मूल्य घरेलू बिक्री मूल्य में कमी कर रहा है। इसके अलावा, विषय आयात का अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से काफी नीचे रहा है। शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, ऐसी कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पैदा होने की संभावना है, और इसे अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए, विषय आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

झ. बिक्री की लागत से कम भारत में प्रवेश करने वाला आयात

116. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय आयात पहले से ही घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर देश में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के परिणामस्वरूप इस तरह के आयातों को देश में और भी कम कीमतों पर प्रवेश करना होगा, जिससे घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आएगी। इसके अलावा, आयात ने हानिकारक कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश किया है।

विवरण	इकाई	वास्तविक	सम्भव	परिवर्तन
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	-
विक्रय मूल्य	रु./मी.टन	***	***	-17%
लाभ / हानि	रु./मी.टन	***	(***)	-128%
लाभ / हानि	रु लाख	***	(***)	-129%
लाभ मार्जिन (लागत पर)	%	***	(***)	-129%
नकद लाभ	रु लाख	***	***	-98%
निवेश पर वापसी	%	***	(***)	-107%

ञ. हानिकारक कीमतों पर आयात

117. आवेदक ने दावा किया है कि विषय आयात ने भारतीय बाजार में हानिकारक कीमतों पर और घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम पर प्रवेश किया है, हालांकि शुल्क लागू होने के बावजूद।

अति मार्जिन का परिमाण

118. प्राधिकारी ने यथासंशोधित, अनुलग्नक III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विषय वस्तुओं का गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य को अति मार्जिन की गणना के लिए विषय देशों से लैंडेड मूल्य की तुलना करने के लिए माना गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के

लिए, क्षति विश्लेषण की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ एक ही उपचार किया गया है। क्षति विश्लेषण की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लिया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल आस्तियों और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित प्रतिफल (22% की दर से कर पूर्व) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा था।

119. उपर्युक्त के रूप में निर्धारित भूमि मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	निर्माता का नाम	गैर-हानिकारक कीमत	भू दाम	क्षति हाशिया	क्षति हाशिया	क्षति हाशिया
		(यूएस\$/एमटी)	(यूएस\$/एमटी)	(यूएस\$/एमटी)	(%)	(रेंज%)
रूस						
1	एज़ोट, जेएससी (नोवोमोस्कोवस्क) और जेएससी नेविन्नोमिस्की एज़ोट नेविन्नोमिस्क	***	***	***	***	0-10
2	जेएससी अज़ोट, केमेरोवो	***	***	(***)	(***)	नेगटिव
3	गैर-सहकारी / अवशिष्ट निर्यातकों	***	***	***	***	0-10
ईरान						
1	गैर-सहकारी / अवशिष्ट निर्यातकों	***	***	***	***	10-20

घ. कारण लिंक और गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

120. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ डंप किए गए आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता होती है जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को डंप किए गए आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, डंप किए गए मूल्यों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। यह नीचे जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान दिया हो सकता है:

क. मात्रा और तीसरे देशों से आयात की कीमतें

121. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय आयात के अलावा, बुल्गारिया, तुर्की और यूक्रेन आयात हैं। तथापि, आयात का मूल्य विषय देशों से आयात के मूल्य से काफी अधिक है।

ख. मांग में संकुचन

122. प्राधिकारी ने नोट किया कि क्षति की अवधि के दौरान विषय वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। भले ही मांग में कमी आई है, लेकिन विषय आयात में वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना नहीं है।

ग. खपत का पैटर्न

123. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय वस्तुओं के पैटर्न खपत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने की आशंका है।

घ. प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तें

124. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच से यह नहीं पता चला है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियां घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

125. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए, घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना नहीं है।

च. उत्पादकता

126. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति विश्लेषण की अवधि में स्थिर रही है और घरेलू उद्योग को क्षति लगने का संभावित कारण नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

127. प्राधिकारी ने नोट किया है कि इसके ऊपर जांच की गई क्षति की जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा होने वाली संभावित क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
128. हितबद्ध कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हुई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग मुख्य रूप से केवल घरेलू बाजार में बिक्री में शामिल है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात क्षति की अवधि में नगण्य था। इस प्रकार, निर्यात में किसी भी गिरावट से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हो सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

129. प्राधिकारी ने केवल विषय वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को क्षति लगने का एक संभावित कारण नहीं है।

झ. कोविड-19

130. हितबद्ध कुछ पक्षों ने दावा किया है कि 2019-20 के दौरान बिक्री में गिरावट और जांच की अवधि के संदर्भ में घरेलू उद्योग को क्षति कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट आई थी। तथापि, शेष मांग फिर भी घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमता के उपयोग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी आयात में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि आवेदक को कोविड - 19 के कारण जांच की अवधि के दौरान किसी भी शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ा।

ट. भारतीय उद्योग की रुचि**ट.1 अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ**

131. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं-

- क. आवेदक उपयोगकर्ता उद्योगों की हानि के लिए बाजार में एक प्रमुख स्थिति में खुद को स्थापित करने में सक्षम है।
- ख. विस्फोटक निर्माता एक बहुत ही पतले मार्जिन पर काम करते हैं और अपने महत्वपूर्ण कच्चे माल यानी अमोनियम नाइट्रेट की कीमत में वृद्धि को डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग को पारित करने के लिए बाध्य हैं और यह सभी स्तरों पर एक कैस्केडिंग प्रभाव पैदा करेगा और बड़े पैमाने पर आम जनता को प्रभावित करेगा। तुलनात्मक रूप से, एकमात्र निर्माता सुंदर मुनाफे का आनंद ले रहा है।
- ग. जबकि आवेदक शुल्क लगाने के बाद सुंदर लाभ कमा रहा है, उपयोगकर्ता उद्योग उच्च मूल्य और आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों के सूखने के कारण पीड़ित है।

- घ. एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य वर्तमान निवेश की रक्षा करना है, न कि भविष्य के निवेश की।
- ङ. बढ़ती माल हुलाई लागत और कंटेनरों की कमी के कारण आयात गतिविधियों को रोक दिया गया है, जिससे कीमतों में और वृद्धि हुई है। उच्च कीमतों के कारण, कुछ पार्टियों ने नवंबर 2021 के बाद से आयात बुक नहीं किया है।
- च. अमोनियम नाइट्रेट की भारी कमी के कारण रूस के किसान प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार, उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, रूसी वित्त मंत्रालयने 1 दिसंबर 2021 से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला किया।
- छ. आवेदक ने उपयोगकर्ता उद्योग पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव को कम करके आंका है।
- ज. आवेदक अपनी एकाधिकार स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आवेदक स्वयं एक ठोस के लिए एकाधिकार के निर्माण की घोषणा कर रहा है।
- झ. कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड, एनएमडीसी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित सभी खनन कंपनियों को जांच की अवधि के दौरान चार महीने तक विस्फोटकों की कमी का सामना करना पड़ा।
- ञ. बाजार में मांग-आपूर्ति का बड़ा अंतर है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6 केटी का घाटा है। महामारी से पहले की अवधि में, 103 केटी की कमी थी। महामारी और लॉकडाउन के कारण उपयोगकर्ताओं को कमी का सामना करना पड़ा, बेरूत में विस्फोट हुआ और इसके बाद विशाखापट्टनम में सतर्कता उपाय किए गए।
- ट. देश में अमोनियम नाइट्रेट की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। उपयोगकर्ता उद्योग को कम आपूर्ति के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आवेदक सीमित क्षमता के साथ एकमात्र निर्माता है।
- ठ. शुल्क के विस्तार से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की व्यवहार्यता को खतरा होगा और समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर डोमिनोज़ प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अमोनियम नाइट्रेट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पहले से ही सर्वकालिक चरम पर हैं, इसलिए कोयले की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिससे बिजली की लागत में वृद्धि होगी, जिससे विनिर्माण महंगा हो जाएगा, जिससे अंततः अंतिम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए बढ़ी हुई कीमतें होंगी। भारत ने अक्टूबर 2021 में 1,201 मिलियन यूनिट की बिजली आपूर्ति की कमी दर्ज की, जो थर्मल प्लांटों के पास उपलब्ध कोयले के स्टॉक में कमी के कारण 5.5 वर्षों में सबसे अधिक थी।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

132. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं-

- क. सार्वजनिक हित पर पाटनरोधी उपायों के प्रभाव का अध्ययन विभिन्न दलों के हितों के परिप्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए - (क) विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक, (ख) विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादक और उपभोग करने वाले दोनों उद्योग में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, (घ) आम जनता और (ई) पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य/उद्देश्य।
- ख. पिछले पांच वर्षों में विषय वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहने से यूजर इंडस्ट्री पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- ग. भारत में प्रमुख उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता में 2019-2020 तक काफी वृद्धि हुई है, इसलिए, उपयोगकर्ता उद्योग को वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्कों से पीड़ित नहीं किया गया था और वर्तमान कर्तव्यों की निरंतरता के कारण नुकसान होने की संभावना नहीं है।
- घ. प्रयोक्ता उद्योग विषय वस्तुओं के मूल्य में किसी भी उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि खनन क्षेत्र के उद्योगों के साथ उनके द्वारा किए गए अनुबंधों में एक मूल्य भिन्नता सूत्र होता है जो विषय वस्तुओं की कीमतों में किसी भी उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखता है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने 2020-21 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि यह लागत वृद्धि को ग्राहकों तक पहुंचाता है।

- ड. अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण होने वाली क्षति को खत्म करना है। आयात के अवतरित मूल्य और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तावित निवेश की रक्षा के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए।
- च. प्रयोक्ता उद्योग पहले से ही मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों पर विषय देशों से आयात पर 25% के रियायती मूल सीमा शुल्क का आनंद ले रहा है।
- छ. खनन क्षेत्र पर डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव केवल 0.84% तक होगा। शुल्क का प्रभाव खनन क्षेत्र से परे कम हो जाएगा।
- ज. जबकि अन्य हितबद्ध दलों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव के बारे में बयान दिए हैं, वे इसके प्रभाव को मापने में विफल रहे हैं।
- झ. वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से भारतीय उद्योग की बीमारी हो सकती है और यहां तक कि उत्पादकों को बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे भारत पूरी तरह से आयात निर्भर बाजार बन सकता है।
- ञ. विषय वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक घोल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग कोयले के खनन में किया जाता है, और यह देश की बिजली की आवश्यकता का 65% पूरा करता है। इसलिए देश के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर होना फायदेमंद नहीं होगा।
- ट. शुल्कों का अधिरोपण उपभोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि निर्यात निर्भरता की उच्च डिग्री का मतलब होगा कि उपभोक्ता निर्यातकों की दया पर हैं।
- ठ. घरेलू उद्योग से खरीद के परिणामस्वरूप बाजार में उचित मूल्य की स्थिरता, निर्बाध आपूर्ति, डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि और उपयोगकर्ताओं के लिए एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार होगा, जबकि उन्हें कम इन्वेंट्री रखने की अनुमति मिलेगी।
- ड. डंपिंग-रोधी शुल्क विषय देशों से आयात पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बजाय, शुल्क केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्यों पर बाजार में प्रवेश करेगा।
- ढ. आवेदक के पास भारत में 85% से अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता है। बाकी की मांग को दूसरे देशों से आयात करके पूरा किया जा सकता है। चूंकि विषय वस्तुओं को पहले पिघले हुए रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए एएन को पिघले हुए रूप में शामिल करने के बाद मांग-आपूर्ति अंतर पर विचार किया जाना चाहिए, जो दिखाएगा कि भारत की क्षमता मांग के बराबर है।
- ण. मांग-आपूर्ति अंतर नोसिल लिमिटेड बनाम भारत सरकार और डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड वी नामित प्राधिकारी में आयोजित प्रतिपादन शुल्क को लागू न किए जाने का आधार नहीं है। प्राधिकारी ने कई मामलों में डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है जहां भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर था।
- त. घरेलू उद्योग ने भारतीय मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। यदि सस्ते अनुचित मूल्य वाले आयातों को नहीं रोका जाता है, तो घरेलू उत्पादकों द्वारा नियोजित निवेश खतरे में पड़ जाएगा।
- थ. विचाराधीन उत्पाद के साथ सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आयातों को गलत तरीके से संभाला जा सकता है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विजाग बंदरगाह पर गोदामों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
- द. घरेलू उद्योग और निर्यातकों की विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। इस प्रकार, आयात पर इतनी अधिक निर्भरता की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ध. न केवल विषय देशों के उत्पादक डंपिंग के अनुचित व्यापार अभ्यास में शामिल हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क को दरकिनार करने में भी संलग्न हैं।
- न. यदि एंटी-डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया जाता है, तो शुल्क से देश में अमोनियम नाइट्रेट की और अधिक डंपिंग हो जाएगी और आवेदक द्वारा किए गए निवेश को जोखिम में डालने की संभावना है।

- प. यदि डंपिंग को बाजार में प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उत्पाद में भविष्य के निवेश को हतोत्साहित करेगा और मांग-आपूर्ति का अंतर केवल बढ़ेगा।
- फ. अन्य हितबद्ध पक्षों के दावे के विपरीत, कैस्केडिंग प्रभावों के बजाय, डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की निरंतरता के प्रभावों में काफी कमी आएगी।
- ब. यह उपयोगकर्ताओं के हित में होगा कि वे विषय वस्तुओं की स्थानीय उपलब्धता रखें, ताकि भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला के लिए बेरूत विस्फोट जैसे किसी भी व्यवधान से बचा जा सके।
- भ. देश में विद्युत संकट उद्योगों द्वारा कोयले का आयात करने में असमर्थता के कारण था क्योंकि कोयले की मांग में काफी वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक कमी और अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, बारिश के कारण कोयला खानों में बाढ़ के कारण भी कमी थी।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

133. प्राधिकारी नोट करता है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करना/जारी रखना किसी भी तरह से विषय देशों से आयात को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य नहीं है। प्राधिकारी मानता है कि एंटी-डंपिंग शुल्कों की निरंतरता भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर को प्रभावित कर सकती है। तथापि, पाटनरोधी उपायों की निरंतरता से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन-रोधी उपायों को जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि डंपिंग अभ्यास से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सके और विषय वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सके।
134. अन्य हितबद्ध दलों ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक हित को उपयोगकर्ता उद्योग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करता है कि परीक्षा बड़े पैमाने पर जनता पर कर्तव्यों के प्रभाव के संबंध में है, और यह उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है। इसलिए, सार्वजनिक हित की जांच में सभी हितधारकों के हितों पर विचार किया जाना चाहिए। जबकि सार्वजनिक हित के मुद्दे की जांच उपयोगकर्ता उद्योग पर ध्यान देने के साथ की जानी चाहिए, हालांकि भारतीय उद्योग के महत्वपूर्ण तत्वों के हितों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जिसमें घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, अपस्ट्रीम आपूर्ति उद्योग, अंतिम उपभोक्ता और बड़े पैमाने पर आम जनता शामिल हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, न्यूजीलैंड, आदि जैसे विभिन्न न्यायालयों में जांच अधिकारी भी अपने सार्वजनिक हित परीक्षा में अन्य हितधारकों के हितों के साथ घरेलू उद्योग के हितों की जांच करते हैं। इस प्रकार, भारतीय उद्योग के समग्र सार्वजनिक हित की जांच करने के लिए, प्राधिकारी को सभी हितधारकों के हितों पर विचार करके एक पूर्णवादी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
135. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या डंपिंग रोधी लगाने से जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में माल की उपलब्धता पर शुल्क लगाने के प्रभाव, उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर आम जनता पर प्रभाव को तौला। यह निर्धारण वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत प्रस्तुतियों और सबूतों पर आधारित है।
136. प्राधिकारी ने शुरुआती अधिसूचना जारी की है जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी संभावित प्रभाव शामिल हैं। जबकि प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं ने डंपिंग-रोधी शुल्क की निरंतरता के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में प्रस्तुतियां दायर की हैं, वे इसे मापने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि विषय वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से घोल के निर्माण के लिए किया जाता है जिसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। रिकार्ड पर साक्ष्य के अनुसार डाउनस्ट्रीम उद्योग एक पास-श्रु उद्योग है और विषय वस्तुओं की कीमतों में किसी भी उतार-चढ़ाव को आगे डाउनस्ट्रीम उद्योग को पारित किया जाता है।
137. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर डंपिंग-रोधी शुल्कों की निरंतरता के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि आम जनता पर कोई कैस्केडिंग प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा निर्मित विस्फोटकों का उपयोग मुख्य रूप से भारत में खनन क्षेत्र में किया जाता है, और खनन क्षेत्र पर अधिकतम प्रभाव केवल 0.84% होगा।

विशेष	इकाई	घरेलू उद्योग की कीमतें उच्चतम लाभप्रदता पर	आयात मूल्य पर विचार
वर्तमान मूल्य	रु./मी.टन	***	***
अंतर	रु./मी.टन	***	
% वृद्धि	%	***	
खनन के लिए एएन की लागत	%	4.40%	
खनन क्षेत्र के लिए लागत में वृद्धि	%	0.84%	

138. घरेलू उद्योग द्वारा परिमाणित उपर्युक्त प्रभाव को अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा ठोस सबूत या जानकारी के साथ विवादित नहीं किया गया है।
139. उपयोगकर्ता उद्योग के प्रदर्शन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि उपयोगकर्ता उद्योगों ने क्षति विश्लेषण की अवधि में अपनी लाभप्रदता बनाए रखना जारी रखा है, यहां तक कि वर्तमान एंटी-डंपिंग कर्तव्यों के कारण भी। इसलिए, उपयोगकर्ता उद्योग के प्रदर्शन पर कोई संभावित हानिकारक प्रभाव नहीं है क्योंकि क्षति विश्लेषण की अवधि में उपयोगकर्ताओं के राजस्व और मुनाफे में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व	रु लाख	2,05,443	2,24,050	2,72,745	2,54,176
कर से पहले लाभ	रु लाख	23,386	23,101	31,282	24,923
राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाभ	%	11	10	11	10

स्रोत: उपयोगकर्ताओं के वित्तीय विवरण *

उपर्युक्त विश्लेषण में निम्न उपयोगकर्ताओं का प्रदर्शन शामिल है:

- आदर्श उद्योग विस्फोटक लिमिटेड
- सौर उद्योग लिमिटेड
- प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड
- राजस्थान विस्फोटक रसायन लिमिटेड
- नल्लाबोलु इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- एकेएस एक्सपो-केम प्राइवेट लिमिटेड
- एम्बल्स एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड
- रेगेनेसिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- श्री विष्णु विस्फोटक प्राइवेट लिमिटेड
- बीजासन एक्सप्लोटेक प्राइवेट लिमिटेड
- भारत विस्फोटक लिमिटेड

140. यह भी नोट किया गया है कि प्रयोक्ता उद्योग के पास एक मूल्य भिन्नता फार्मूला है जो विचाराधीन उत्पाद के मूल्यों में किसी भी उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखता है, जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी खरीद निविदा से स्पष्ट है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी मूल्य वृद्धि को उपयोगकर्ताओं द्वारा पारित किया जाएगा।
141. प्राधिकारी ने आगे कहा कि कोल इंडिया जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं को कर्तव्यों से काफी प्रभावित होने के रूप में नहीं माना जा सकता है। रिकार्ड पर दी गई सूचना के अनुसार, अमोनियम नाइट्रेट कोल इंडिया की लागत और राजस्व का 2% से भी कम है। ऐसी स्थिति में, लागत के इतने छोटे घटक पर शुल्क का प्रभाव उपयोगकर्ता के समग्र संचालन में कम से कम होगा।

	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21
कोल इंडिया का कुल राजस्व	रु. लाख	99,586	96,080	90,026
कोल इंडिया का कुल खर्च	रु. लाख	78,294	78,453	75,806
विस्फोटकों की कीमत का उपभोग किया गया	रु. लाख	1,886	1,793	2,008
AN* की लागत	रु. लाख	1,132	1,076	1,205
कुल राजस्व में विस्फोटकों की लागत का हिस्सा	%	1.89%	1.87%	2.23%
कुल खर्च में विस्फोटकों की लागत का हिस्सा	%	2.41%	2.29%	2.65%
कुल राजस्व में एक लागत का हिस्सा	%	1.14%	1.12%	1.34%
कुल खर्च में एक लागत का हिस्सा	%	1.45%	1.37%	1.59%

साँचा: कोल इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट

*सीआईएल के ब्लक रेट कॉन्ट्रैक्ट में मूल्य भिन्नता खंड के आधार पर निर्धारित एएन की लागत, जिसमें विस्फोटकों की खरीद अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य के लिए 60% पर बेंचमार्क की जाती है।

142. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि आयात मूल्य में पाटनरोधी शुल्क के भारित औसत घटक में इस अवधि के दौरान कमी आई है, अर्थात् कम या शून्य शुल्क के भुगतान पर अधिक आयात किया जा रहा है।

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल आयात (मी.टन)		205	259	276	242
मी.टन में पाटनरोधी शुल्क	शून्य	145	156	248	152
	यूएसडी 11.42	14	60	28	90
	यूएसडी 25	-	24	-	-
	यूएसडी 26.07	8	-	-	-
	यूएसडी 53.99	-	-	-	-
	यूएसडी 60.35	39	19	-	-
पाटनरोधी शुल्क वॉल्यूम का हिस्सा		30%	40%	10%	37%
गैर-पाटनरोधी शुल्क वॉल्यूम का हिस्सा		70%	60%	90%	63%
भारित औसत जोड़े (\$/मी.टन)		13.3	9.3	1.2	4.2

143. प्राधिकारी ने नोट किया कि 2017-18 में भारित औसत शुल्क 13.3 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन था, लेकिन जांच की अवधि में यह घटकर 4.2 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन हो गया है, अर्थात्, आयात मूल्य का केवल 1.87%। इसके अलावा, किए गए आयातों का 63% डंपिंग-रोधी शुल्कों के अधीन नहीं था। इसलिए, शुल्क को बाजार में एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि का कारण नहीं माना जा सकता है।
144. कुछ हितबद्ध दलों ने तर्क दिया है कि आवेदक ने उपयोगकर्ता उद्योग की हानि पर खुद को एक प्रमुख स्थिति में स्थापित किया है और भारत में एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उपयोगकर्ता क्षति विश्लेषण की अवधि में अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रहे हैं, और लागू होने पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। यद्यपि आवेदक भारत में ठोस रूप में अमोनियम नाइट्रेट का एकमात्र उत्पादक है, विषय वस्तुओं का उपयोग

अंततः केवल पिघले हुए रूप में किया जाता है। इस प्रकार, आवेदक सीधे अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादकों के साथ पिघले हुए रूप में प्रतिस्पर्धा करता है और भारत में एकाधिकार पैदा नहीं कर सकता है। आवेदक विषय देशों के साथ-साथ गैर-विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए, यह संभव नहीं है कि आवेदक भारत में एकाधिकार बनाने में सक्षम हो।

145. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण आयात अपरिहार्य है। प्राधिकारी नोट करता है कि मांग और आपूर्ति अंतर भारत में डंपिंग का औचित्य नहीं है। देश में मांग-आपूर्ति का अंतर होने पर भी यह जरूरी है कि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। एंटी-डंपिंग ड्यूटी जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता बाधित नहीं होगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि यह उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की फिर से स्थापना आगे के निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, जो मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद करेगी।
146. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि हालांकि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है, वर्तमान में आयात इस अंतर से कहीं अधिक है। कि विचाराधीन उत्पाद को बुल्गारिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन जैसे अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बल्गारिया	मीट्रिक टन	14,500	1,05,109	76,123	38,618
मिस्र	मीट्रिक टन	-	-	44	-
जापान	मीट्रिक टन	-	-	19	-
कज़ाकस्तान	मीट्रिक टन	-	-	15,798	-
कोरिया RP	मीट्रिक टन	3,398	660	500	-
तुर्कस्तान	मीट्रिक टन	-	38,100	1,05,926	52,500
संयुक्त अरब अमीरात	मीट्रिक टन	20,910	1,234	-	-
उज़्बेकिस्तान	मीट्रिक टन	-	4,793	4,495	-
यूक्रेन	मीट्रिक टन	-	-	-	15,200
इराक	मीट्रिक टन	-	-	-	278

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस डेटा

147. इन देशों से किए गए आयात की मात्रा मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। प्राधिकारी नोट करता है कि देश में मांग और आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है। जबकि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से आयात को रोका नहीं जा सकेगा, किसी भी मामले में, उपयोगकर्ता अन्य देशों से विषय वस्तुओं का स्रोत जारी रख सकते हैं।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
मांग	488,020	547,197	558,768	486,152
भारत में क्षमता	483,600	483,600	483,600	483,600
अन्य आयात	46,808	149,896	202,905	106,596
घरेलू उद्योग की क्षमता + अन्य आयात	530,408	633,496	686,505	590,196
मांग से अधिक आपूर्ति	42,387	86,299	127,737	104,044

148. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि जबकि एएन पिघल आयातित माल के लिए लेख की तरह नहीं है, फिर भी यह एक सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद है। इसलिए, मांग-आपूर्ति की स्थिति को समान लेख और एएन पिघल दोनों के लिए मांग और क्षमता पर विचार करने के बाद बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
मांग (डीजीसीआईएंडएस)	***	***	***	***
भारत में क्षमता*	***	***	***	***
अन्य आयात (डीजीसीआई एंडएस)	53,308	1,53,412	2,14,454	1,18,304
घरेलू उद्योग की क्षमता + अन्य आयात	***	***	***	***
मांग से अधिक आपूर्ति	***	***	***	***

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि विषय देशों से आयात को बाहर करने के बाद भी, भारतीय बाजार में विषय वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति थी।

149. मांग और आपूर्ति के अंतर के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों द्वारा योजनाबद्ध की जा रही महत्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि पर भी ध्यान देता है। अमोनियम नाइट्रेट के विभिन्न उत्पादित द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के अनुसार, सभी रूपों में आवेदक, चंबल उर्वरक, जीएनएफसी, आरसीएफ और एनएफएल सभी क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। इनमें वर्तमान क्षमता का विस्तार, ब्राउनफील्ड संयंत्रों के साथ-साथ ग्रीनफील्ड संयंत्र भी शामिल हैं। इस तरह के क्षमता विस्तार से देश में कुल क्षमता में 9 लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। प्राधिकारी ने नोट किया है कि इस तरह की क्षमता वृद्धि से देश में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। तथापि, यदि बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थितियों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो नियोजित क्षमता अभिवृद्धि की व्यवहार्यता खतरे में पड़ सकती है।
150. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि कोयला विनिर्माण कंपनियां भारत में विषय वस्तुओं की कमी के कारण पीड़ित थीं। प्राधिकारी नोट करता है कि विषय वस्तुओं का उपयोग कोयला निर्माता कंपनियों द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। ये कंपनियां विषय वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित विस्फोटकों का उपयोग करती हैं। विस्फोटक विनिर्माताओं ने यह तर्क नहीं दिया है कि भारत में विषय वस्तुओं की कमी थी। क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और इन्वेंट्री में वृद्धि हुई है। भारत में विषय वस्तुओं की कमी के मामले में, कोई संचित सूची नहीं होनी चाहिए थी।
151. यह उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है कि रूसी प्रतिबंध, कुछ बंदरगाहों पर प्रतिबंधों और बेरूत विस्फोट के कारण, विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता देश में प्रभावित हुई थी। प्राधिकारी को इन घटनाओं और शुल्क लगाने के बीच कोई साठगांठ नहीं मिलती है। इसके विपरीत, इस तरह की घटनाओं ने आपूर्ति को बाधित किया होगा, यहां तक कि डंपिंग-रोधी शुल्कों की अनुपस्थिति में भी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति व्यवधान घरेलू विनिर्माण के महत्व को रेखांकित करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी को यह नहीं पता चलता है कि शुल्क लगाने से मांग-आपूर्ति की स्थिति और बढ़ेगी। प्राधिकारी यह भी मानता है कि घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय उपभोक्ता आयात पर निर्भर न हों, और आपूर्ति को बाधित करने वाले किसी भी प्रतिबंध या अन्य अंतरराष्ट्रीय कारकों के बावजूद भी विषय वस्तुओं का स्रोत बनाने की स्थिति में हों।

ठ. प्रकटीकरण के बाद के बयान प्रस्तुतियाँ

152. पोस्ट प्रकटीकरण प्रस्तुतियां हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग से प्राप्त हुई हैं, और यह ध्यान दिया जाता है कि उठाए गए अधिकांश मुद्दे पुनरावृत्ति हैं और पहले से ही उठाए जा चुके हैं और उचित रूप से संबोधित भी किए गए हैं। अतिरिक्त प्रस्तुतियों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

ठ.1 अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

153. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित पोस्ट-डिस्कलोजर सबमिशन किए गए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षों ने लेख और घरेलू उद्योग जैसे दायरे, सामान्य मूल्य का निर्धारण, क्षति की अनुपस्थिति, डंपिंग और क्षति की निरंतरता की संभावना की अनुपस्थिति, कारण लिंक की अनुपस्थिति, आंकड़ों में विसंगतियों, बेरुत में विस्फोट का प्रभाव और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर उपायों, मांग-आपत अंतर के अस्तित्व, रूस द्वारा प्रतिबंध और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया है।
- i. जबकि प्राधिकारी को जांच करने में पूरा एक साल लगा है, हितबद्ध पक्षों को टिप्पणी देने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी के पास टिप्पणियों पर विचार करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय होगा।
 - ii. पूरी संभावना विश्लेषण केवल जॉर्जिया और रूस से संबंधित है और ईरान को कवर नहीं करता है।
 - iii. चूंकि रूस के सहकारी उत्पादकों के पास नकारात्मक पाटन मार्जिन है, इसलिए भारत में रूस की पूरी मात्रा को अन-डंप किया गया है।
 - iv. कम घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट को विशेष रूप से शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - v. अवशिष्ट पाटन मार्जिन के निर्धारण की पद्धति और नियमों के नियम 6(8) का केवल संदर्भ पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, ईरान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
 - vi. प्रकटीकरण कथन यह भी रिकॉर्ड नहीं करता है कि संचयी मूल्यांकन के लिए नियमों के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं।
 - vii. तीसरे देश की डंपिंग के लिए सूचना के किसी स्रोत की पहचान नहीं की गई है।
 - viii. देश में उच्च मांग आपत अंतर के अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतों से भारी विस्फोटक विनिर्माण और खनन क्षेत्र के लिए विस्फोटक की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
 - ix. घरेलू उद्योग अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया के उत्पादन के लिए नए सिरे से निवेश कर रहा है।
 - x. देश में मांग और आपत में भारी अंतर है और इस अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।
 - xi. अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, जहां किसी निर्यातक को मूल जांच में डंपिंग नहीं करते हुए पाया गया था, ऐसे निर्यातक के खिलाफ तत्काल समाप्ति होनी चाहिए।
 - xii. भारत रूस में निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार नहीं है।
 - xiii. सहकारी उत्पादकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, जो डंपिंग नहीं करते पाए गए हैं।
 - xiv. वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि हुई है, जैसे कि 2021 में यूरोप, रूस और उत्तरी अमेरिका के देश।
 - xv. तीसरे देशों से आयात की कीमत गैर-हानिकारक मूल्य से कम है।
 - xvi. कोल इंडिया निविदाओं का मूल्य संशोधन फार्मूला वास्तविक समय में बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यदि एंटी-डंपिंग झूठी बढ़ाई जाती है, तो विस्फोटक निर्माता वसूली करने में सक्षम नहीं होंगे।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

154. घरेलू उद्योग ने जॉर्जिया से डंपिंग और क्षति की संभावना के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया, और गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण में अमूर्त संपत्ति पर विचार किया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
- क. जॉर्जिया के निर्यातकों को तीसरे देश के निर्यात के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाना चाहिए था।

- ख. चूंकि वर्तमान जांच डंपिंग और क्षति की संभावना पर आधारित है, न कि वर्तमान क्षति की, इसलिए एक ही एंटी-डंपिंग झूटी जारी रहनी चाहिए।
- ग. सीआईएल ने मुनाफे में भारी वृद्धि का अनुभव किया है, साथ ही जीओसीएल जो अमोनियम नाइट्रेट का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

155. प्राधिकारी ने नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां पुनरावृत्तियां हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों की जांच की है।
156. प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग ने एनआईपी के निर्धारण में अमूर्त आस्तियों पर विचार करने का दावा किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अमूर्त संपत्ति सद्भावना के रूप में है और एनआईपी के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
157. जैसा कि इस अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में प्रदान किया गया है, जॉर्जिया को वर्तमान एंटी-डंपिंग झूटी की समाप्ति के कारण डंपिंग और क्षति की संभावना के सबूत की कमी के कारण एक विषय देश के रूप में बाहर रखा गया है।
158. प्रकटीकरण बयान 7 जून 2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पार्टियों को 8 जून 2022 तक टिप्पणी दर्ज करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षों ने प्रकटीकरण बयान पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए केवल एक दिन प्रदान किए जाने के साथ शिकायत व्यक्त की है। हालांकि, हितबद्ध पक्षों को टिप्पणियां दायर करने के लिए समय प्रदान करने के लिए, प्राधिकारी ने समय सीमा को एक दिन के लिए बढ़ाकर 9 जून 2022 कर दिया था। यह प्राधिकारी जांच समाप्त करने के लिए प्राधिकारी को समय का विस्तार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के इनकार के कारण हितबद्ध पक्षों को टिप्पणियां दायर करने के लिए और समय प्रदान करने से विवश है।
159. ईरान से डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में, प्राधिकारी नोट करता है कि देश से वर्तमान डंपिंग के सबूत हैं। इसके अलावा, 2018-19 तक गिरावट के बाद हाल की अवधि में ईरान से आयात में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों का मूल्य भी घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य में कमी आई है। इसके अलावा, आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और गैर-हानिकारक मूल्य से कम हानिकारक मूल्यों पर प्रवेश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि शुल्कों के अभाव में, डंपिंग जारी रहने की संभावना है, आयात की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है, और घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना है।
160. हितबद्ध पक्षों के दावे के विपरीत, सहकारी उत्पादकों के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन का अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है, क्योंकि प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक देश में उत्पादकों की संपूर्णता का गठन नहीं करते हैं।
161. चूंकि विचाराधीन उत्पाद अमोनियम नाइट्रेट तक सीमित है, जिसका घनत्व 0.83 ग्राम/सीसी से अधिक है, इसलिए कम घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में कोई विशिष्ट बहिष्करण की आवश्यकता नहीं है।
162. गैर-सहकारी उत्पादकों और ईरान के लिए सामान्य मूल्य प्राधिकारी के सुसंगत अभ्यास के अनुसार निर्धारित किया गया है। हितबद्ध पक्षों ने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
163. हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि क्षति का संचयी विश्लेषण इस बात की जांच किए बिना किया गया है कि क्या इसकी आवश्यकताएं संतुष्ट हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि, सूर्यास्त की समीक्षा के मामले में, जबकि क्यूमुलेशन की अनुमति है, उसकी शर्तें लागू नहीं होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में पैनल - अर्जेंटीना से तेल देश ट्यूबलर सामान पर एंटी-डंपिंग उपायों की सूर्यास्त समीक्षा ने एक विचार लिया कि अनुच्छेद 3.3 में निर्धारित शर्तें सूर्यास्त समीक्षाओं पर लागू नहीं होती हैं। इसलिए, प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि संचयी विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले क्यूमुलेशन की सभी शर्तें संतुष्ट हैं या नहीं।

164. जैसा कि पहले से ही वर्तमान निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में खुलासा किया गया है, तीसरे देश के डंपिंग का विश्लेषण ट्रेड मैप डेटा पर आधारित है। हालांकि इस तरह के डेटा की आपूर्ति आवेदक द्वारा याचिका में ही की गई थी, लेकिन जांच के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा सबूतों के साथ इसे भ्रमित नहीं किया गया है।
165. हितबद्ध पक्षों ने मांग-आपूर्ति के अंतर और विस्फोटक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विषय वस्तुओं की उच्च कीमतों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए विस्फोटकों की उपलब्धता पर जोर दिया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने प्रदर्शन कोल इंडिया लिमिटेड और जीओसीएल पर भरोसा किया है, जो दिखाता है कि विस्फोटक निर्माताओं और विस्फोटकों के उपयोगकर्ताओं दोनों ने मुनाफे में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, और कोयले के उठान में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकरण घरेलू उत्पादकों द्वारा योजनाबद्ध महत्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि को नोट करता है। अमोनियम नाइट्रेट के विभिन्न उत्पादों द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी के अनुसार, सभी रूपों में, आवेदक, चंबल उर्वरक, जीएनएफसी, आरसीएफ और एनएफएल सभी क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, प्रति वर्ष कुल 9 लाख टन की वृद्धि। इनमें वर्तमान क्षमता का विस्तार, ब्राउनफील्ड संयंत्रों के साथ-साथ ग्रीनफील्ड संयंत्र भी शामिल हैं। प्राधिकरण ने नोट किया है कि इस तरह की क्षमता वृद्धि से देश में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। किसी भी मामले में, प्राधिकरण नोट करता है कि मांग और आपूर्ति अंतर भारत में डंपिंग के लिए एक औचित्य नहीं है। देश में मांग-आपूर्ति का अंतर होने पर भी यह जरूरी है कि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। एंटी-डंपिंग ड्यूटी जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता बाधित नहीं होगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि यह उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की फिर से स्थापना आगे के निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है, जो मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद करेगी। इसके अलावा, विषय वस्तुओं को बुल्गारिया, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन जैसे अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।
166. जहां तक मूल जांच में डंपिंग नहीं पाए जाने वाले उत्पादकों के खिलाफ जांच की समाप्ति के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि इस तरह की समाप्ति निर्धारित न्यायशास्त्र और इसके अपने अभ्यास के अनुसार नहीं होगी। मूल जांच के दौरान निर्यातक पर शून्य शुल्क लगाया गया था, लेकिन इसके खिलाफ जांच समाप्त नहीं की गई थी। निर्यातक ने भी इस तरह की समाप्ति के लिए नहीं कहा। प्राधिकारी ने लगातार यह विचार रखा है कि वह मूल जांच में शून्य शुल्क वाले निर्यातक के खिलाफ सूर्यास्त की समीक्षा कर सकता है। रॉबिन रिसोर्सेज वी के मामले में। भारत संघ, माननीय सीईएसटीएटी ने भी निम्नानुसार नोट किया है।

"9. हम ध्यान दें कि डीए विचार कर सकते हैं जहां एक निर्यातक को मूल जांच में शून्य शुल्क से सम्मानित किया गया था और अब डंपिंग पाया गया है जो संभवतः डीआई के लिए क्षति का कारण है, तो एडी शुल्क को पाटन मार्जिन और समीक्षा के दौरान स्थापित क्षति मार्जिन के संदर्भ में लागू करने के लिए विचार किया जा सकता है। हम ध्यान दें कि डीए ने एडीए के अनुच्छेद 2 और 3 की आवश्यकताओं और एडी नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया। हम यह भी ध्यान देते हैं कि अपीलकर्ताओं के संबंध में, डीए ने मूल जांच के सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा की है और इसके अलावा जांच की है कि क्या प्रारंभिक अधिसूचना की समाप्ति से डीआई को डंपिंग / क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह एक नई जांच की तरह है क्योंकि अपीलकर्ता का संबंध है और हमें डीए द्वारा इस तरह की कार्रवाई में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं मिलती है।"

167. जहां तक हितबद्ध पक्षों के इस तर्क का संबंध है कि भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार नहीं है, यह ध्यान दिया जाता है कि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान भी, रूस से आयात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ऐसे आयात हानिकारक मूल्यों पर होते हैं, जो घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और बिक्री की लागत से कम होते हैं। रूस के निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमताएं हैं। इसके अलावा, भारत एक मूल्य आकर्षक बाजार है, जो निर्यातकों को भारत में निर्यात को मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसलिए, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि ड्यूटी की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग की निरंतरता और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना है।
168. हितबद्ध पार्टियों ने दावा किया है कि 2021 में विषय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से रूस, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। प्राधिकरण नोट करता है कि रिकॉर्ड पर जानकारी से पता चलता है कि रूस के पास अपनी घरेलू मांग के अलावा एक विशाल अधिशेष क्षमता है। इसके अलावा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने रूस से निर्यात के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बाजार रूस के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

169. हितबद्ध पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि अन्य देशों से आयात की कीमत गैर-हानिकारक मूल्य से कम है। प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि बुल्गारिया, तुर्की और यूक्रेन से महत्वपूर्ण आयात हैं। तथापि, ऐसे आयातों की कीमत गैर-हानिकारक मूल्य से अधिक होती है।
170. कुछ आयातकों और प्रयोक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों ने उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण कठिनाइयों का कारण बना दिया है। हालांकि, उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए सबूतों का खंडन नहीं किया है कि उपयोगकर्ताओं के वित्तीय विवरण प्रदर्शन में गिरावट नहीं दिखाते हैं।

ड. निष्कर्ष

171. उठाए गए विवादों, प्रदान की गई जानकारी, किए गए प्रस्तुतियों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विषय देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए लेख की तरह है।
- ख. पीओआई और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जॉर्जिया से भारत को विषय वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया गया है। पीओआई के दौरान एकमात्र जॉर्जियाई निर्माता के साथ कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है जैसा कि आवेदक के साथ-साथ हितबद्ध पार्टियों द्वारा साक्षात् की गई जानकारी से स्पष्ट है। इसके अलावा, पीओआई के बाद छह महीने के दौरान एकमात्र जॉर्जियाई निर्माता के साथ कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के अनुसार, किसी अन्य देश ने जॉर्जिया से आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है। जॉर्जिया से आयात के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान डंपिंग और क्षति की अनुपस्थिति है और साथ ही जॉर्जिया से आयात के कारण डंपिंग और क्षति की कोई संभावना नहीं है और इस प्रकार, जॉर्जिया को विषय देशों से बाहर रखा गया है।
- ग. रूस और ईरान से डंपिंग जारी है, लागू होने के बावजूद, विषय देशों से एंटी-डंपिंग ड्यूटी के बावजूद। महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं, निर्यात अभिविन्यास, तीसरे देश की डंपिंग, अन्य न्यायालयों द्वारा लगाए गए उपायों के साथ-साथ भारत के मूल्य आकर्षण के साक्ष्य के प्रकाश में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि वर्तमान एंटी-डंपिंग ड्यूटी की समाप्ति के मामले में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है।
- घ. जबकि सहकारी उत्पादकों को डंपिंग नहीं पाया गया है, विषय देशों के गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- ड. पूर्वगामी से, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में ईरान और रूस से आयात द्वारा घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है।

ढ. सिफारिशें

172. प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों को डंपिंग, क्षति, कारण लिंक और डंपिंग और क्षति की संभावना के पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
173. जॉर्जिया से आयात के कारण, वर्तमान डंपिंग या क्षति, या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का कोई सबूत नहीं मिलने के बाद, प्राधिकारी को यह नहीं पता चलता है कि जॉर्जिया से अमोनियम नाइट्रेट के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की निरंतरता आवश्यक है। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि रूस और ईरान के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के सकारात्मक सबूत हैं, प्राधिकारी का विचार है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क रूस और ईरान को आगे भी जारी रखने की जरूरत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार रूस और ईरान से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क को दो (2) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश करना उचित समझता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	31023000	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतिव या कोटिंग के साथ या बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।	रूस	रूस सहित किसी भी देश	जेएससी अज़ोट जेएससी नेविन्नोमिस्की एज़ोट	शून्य	यूएसडॉलर	मी.टन
2	-वही-	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतिव या कोटिंग के साथ या बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।	रूस	रूस सहित किसी भी देश	जेएससी अज़ोट, केमेरोवो	शून्य	यूएसडॉलर	मी.टन
3	-वही-	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतिव या कोटिंग के साथ या बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।	रूस	रूस सहित किसी भी देश	क्र.सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य	16.91	यूएसडॉलर	मी.टन
4	-वही-	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतिव या कोटिंग के साथ या	रूस और इरा के अलावा किसी भी देश n	रूस	कोई	16.91	यूएसडॉलर	मी.टन

		बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।						
5	-वही-	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतित्व या कोटिंग के साथ या बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।	ईरान	ईरान सहित किसी भी देश	कोई	31.24	यूएसडॉलर	मी.टन
6	-वही-	अमोनियम नाइट्रेट "चाहे वह प्रिल, दानेदार, या अन्य ठोस रूप में, पाटनरोधी शुल्कांतित्व या कोटिंग के साथ या बिना, और 0.83 ग्राम / सीसी से अधिक में थोक घनत्व वाला हो।	रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	ईरान	कोई	31.24	यूएसडॉलर	मी.टन

174. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयात का अवतरण मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3, 8बी, 9 और 9ए के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

ण. आगे की प्रक्रिया

175. इन निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 10th June, 2022

[Case No. ADD(SSR)-11/2021]

Subject : Sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of “Ammonium Nitrate” originating in or exported from Russia, Georgia and Iran.

F. No. 7/11/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Smartchem Technologies Limited (hereinafter also referred to as ‘applicant’ or ‘domestic industry’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as ‘Authority’) with request to initiate the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on the imports of Ammonium Nitrate, (hereinafter also referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from Russia, Georgia and Iran (hereinafter referred to as ‘subject countries’).
2. The original investigation was initiated on 5th August, 2016 to examine the nature and the extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to Ammonium Nitrate originating in or exported from Georgia, Indonesia, Iran and Russia. The Authority, vide its Final Findings No. 14/1/2016-DGAD, dated 1st August, 2017, recommended imposition of anti-dumping duties on Georgia, Indonesia, Iran and Russia, which were given effect vide Customs Notification No. 44/2017 – Customs (ADD), dated 12th September, 2017 for a period of five years. The said duties, if not extended, will expire on 11th September, 2022.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. The applicant filed an application dated 29th April, 2021, requesting initiation of the sunset review of anti-dumping duties imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duties against imports of Ammonium Nitrate from Georgia, Indonesia, Iran and Russia. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the product under consideration and consequent injury to the domestic industry.
6. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of the likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 7/11/2021 – DGTR, dated 11th June, 2021 to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from

Georgia, Iran and Russia and to examine whether the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. In respect of Indonesia, the Authority noted that there were neither any imports of the product under consideration from Indonesia during 2018-19, 2019-20 and the period of investigation, nor there was any prima facie evidence of likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of the current anti-dumping duty in force.

B. PROCEDURE

7. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings No. 14/1/2016- DGAD, dated 1st August, 2017, by which imposition of anti-dumping duties on imports of product under consideration originating in or exported from the subject countries had been recommended.
8. The procedure described herein below has been followed in the present investigation:
 - i. The Authority vide Notification No. 7/11/2021-DGTR, dated 11th June, 2021, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
 - ii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Governments of the subject countries, through their Embassies, and to the other interested parties who made a request therefore in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to the other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation to the known producers / exporters in the subject countries, and the other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
 - v. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers/exporters:
 - a. Rustavi Azot LLC, Georgia
 - b. Shiraz Petrochemical Company, Iran
 - c. Eurochem Group, Russia
 - d. JSC Acron (Novgorod), Russia
 - e. Phosagro – Cherepovets, Russia
 - f. Uralchem group – MFP KCCW, Russia
 - g. Uralchem group– JSC Azot (Berezniki), Russia
 - vi. The Government of the subject countries, through their Embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies of the subject countries along with the details of the known producers/ exporters from the respective subject countries.
 - vii. The following producers/exporters from the subject countries filed a response to the exporters' questionnaire:
 - a. Azot, JSC (Novomoskovsk)
 - b. Cistech International Pte. Ltd.

- c. Drey Moor Fertilizers Overseas Pte Ltd, Singapore
 - d. EuroChem Trading GmbH
 - e. EuroChem Trading RUS, LLC
 - f. JSC Azot, Kemerovo
 - g. JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk
 - h. Rawfert Offshore SAL
 - i. Rhino Rock Limited
 - j. SBU Nitrotrade AG
- viii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the known importers/ users of the subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- a. AKS Expo-chem Private Limited
 - b. Ambals Explosives Private Limited
 - c. AP Explosives Private Limited
 - d. Aravali Explosive Chemicals
 - e. Beezaasan Explotech Private Limited
 - f. Bharat Explosives Limited
 - g. Black Diamond Explosives Private Limited
 - h. Blastec India Private Limited
 - i. Boom Buying Private Limited
 - j. Canpex Chemicals Private Limited
 - k. CDET Explosive Industries Private Limited
 - l. Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Limited
 - m. GOCL Corporation Limited
 - n. Gouthami Explosives Private Limited
 - o. Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited
 - p. Ideal Industrial Explosives
 - q. IDL Industries Limited
 - r. Indian Explosives Limited (Orica)
 - s. Indian Oil Corporation Limited
 - t. Indo Gulf Industries Limited
 - u. Intrachem Company
 - v. Kakatiya Chemicals Private Limited
 - w. Karolinska Industries
 - x. Keltech Energies Limited
 - y. Labdhi Chemicals Industries
 - z. LS Chemicals & Pharmaceuticals
 - aa. Mahanadi Metals Chemicals Private Limited
 - bb. Merck Life Science Private Limited
 - cc. Molychem
 - dd. Nallabolu Industries Private Limited

- ee. Orissa Explosives Limited
- ff. Peri Nitrates Private Limited
- gg. Prasad Explosives & Chemicals
- hh. Premier Explosives Limited
- ii. Raja Explosives Private Limited
- jj. Rajasthan Explosive Chemicals Limited
- kk. Regenesi Industries Private Limited
- ll. Salvo Explosives and Chemicals Private Limited
- mm. Sasan Power Limited
- nn. SBL Energy Limited
- oo. Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- pp. Sivasakthi Industrial Explosives Private Limited
- qq. Solar Industries India Limited
- rr. Special Blast Limited
- ss. Sri Amman Chemicals Private Limited
- tt. Sri Krishna Explosives Accessories Company
- uu. Sri Vishnu Explosives Private Limited
- vv. Standard Chemical Corporation
- ww. Thakker International
- xx. The Singareni Collieries Company Limited
- yy. Totem International Limited
- zz. Vetrivel Explosives Private Limited
- aaa. Visu Chemicals
- bbb. Wagesh Energy Equipments Private Limited
- ix. The following importers / users have filed a response to the importer questionnaire:
 - a. Black Diamond Explosives Private Limited
 - b. IDL Explosives Limited
 - c. Solar Industries Limited
 - d. Special Blasts Limited
 - e. Indian Explosives Private Limited
- x. The following interested parties have filed submissions in response to the initiation notification:
 - a. Black Diamond Explosives Private Limited
 - b. Explosives Manufacturers Welfare Association
 - c. Ideal Industries Explosives Limited
 - d. IDL Explosives Limited
 - e. Regenesi Industries Private Limited
 - f. Solar Industries Limited
- xi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020 and the period of investigation.

- xii. Transaction-wise import data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The Authority also notes that the volume of imports from Russia as reported in the DGCI&S data are much less than the volume of exports as per the Russian Customs data as well as the data submitted by the participating producers/exporters. Therefore, the Authority has relied upon the Russian Customs data calculating the volume and value of imports of the product under consideration in India for Russia and data of DGCI&S for other subject-countries.
- xiii. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xiv. The non-injurious price has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove the injury to the domestic industry.
- xv. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 29th November 2021 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by the various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the final findings.
- xviii. A disclosure statement containing essential facts in the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 7th June, 2022. In accordance with the provisions of Rule 23 read with Rule 17, the Authority sought extension of the period of investigation by six months from the Central Government vide letter dated 20th May, 2022. However, vide letter dated 6th June, 2022, the Central Government has not granted extension. As a result of such exigencies, the Authority had been constrained to allow a limited time to the interested parties for filing comments on the disclosure statement, since the investigation would become time barred on 10th June, 2022. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant in the final findings.
- xix. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xx. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final findings notification on the basis of the facts available

- xxii. *** in this final findings notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$ 1= Rs. **74.99**.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“4. The product under consideration (PUC) in this investigation is same as that in the earlier investigation, that is, “Ammonium nitrate whether prilled, granular or in other solid form, with or without additives or coating and having bulk density in excess of 0.83 g cc.”

C.1. Submissions by the other interested parties

10. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of product under consideration and like article.
- Ammonium nitrate (hereinafter also referred to as “AN”) in all forms and all densities should be included in the scope of like product as melt and solid are only different forms of Ammonium Nitrate and all forms are used interchangeably. AN melt is produced and converted into solid form. There is no technical or commercial difference between AN melt and AN in other solid forms.
 - The scope of the product as determined in the original investigation was not appropriate, and must be revisited in the sunset review.
 - There is no basis to put bulk density to describe the product, as all densities can be interchangeably used. LDAN and HDAN are matter of level of concentration only and have no technical differentiation.
 - In the investigation conducted in 2003, the Authority included all forms of Ammonium Nitrate within the scope of the product under consideration in the preliminary findings. However, in the final findings, the Authority took a different view without reference to any technical literature. The European Commission in its Regulation (EU) No. 2020/2100 has also held that both types of AN have the same technical and chemical characteristics, are easily interchangeable.
 - The applicant has the capability to manufacture Ammonium Nitrate only up to the bulk density of 0.87 g/cc. The Authority has, in a number of investigations such as high-speed steel, plain medium density fibre board, viscose filament yarn, etc., restricted the scope of the product under consideration to the extent domestic industry was producing the same.

C.2. Submissions by the domestic industry

11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration or like article.
- The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as was defined in the original investigation.
 - Ammonium Nitrate in melt form is not a commercial substitute for the product under consideration as it involves higher transportation and storage costs and cannot be transported over longer distances.
 - Ammonium Nitrate in melt form is not being imported into India.
 - The domestic industry is producing identical article in the form of solid, and hence, Ammonium Nitrate in melt form cannot be considered a like article.
 - Ammonium Nitrate in melt form can neither be included in the scope of product under consideration or like article as held by the Hon'ble CESTAT in the case of ~~in~~ Solar Industries Limited V. Union of India.
 - The users have themselves admitted that Ammonium Nitrate in melt form is not like article in the previous investigation and are therefore contradicting their own claim.

- g. The other interested parties have relied upon the preliminary findings of the Authority, wherein they have themselves argued for the exclusion of AN melt and LDAN. The Authority accepted these arguments in the final findings.
- h. The Authority has already held in the previous investigation that the applicant has produced Ammonium Nitrate having density above 0.83 g/cc and as high as 0.94 g/cc.
- i. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.

C.3. **Examination by the Authority**

- 12. The product under consideration in the present investigation is Ammonium Nitrate whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc.
- 13. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation. In the original investigation, the product under consideration was defined as follows:

“(i)The product under consideration in the present investigation is “Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc, classified under chapter 31 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub- heading 3102 30 00.

(ii) Ammonium Nitrate, a chemical compound with the formula NH_4NO_3 is composed of nitric acid and salt of ammonia. The nitrogen content exceeds 28% of weight in solid form. In room temperature, ammonium nitrate appears in a white crystalline colourless form. Its melting point is 169.6 degrees Celsius or 337.3 degrees Fahrenheit.

(iii) Ammonium nitrate is produced from ammonia and nitric acid, in various forms, such as melt, prills, flakes, granules, lumps, etc. The subject goods are ammonium nitrate in solid form having density above 0.83 g/cc. Ammonium Nitrate in any form having bulk density upto 0.83 g/cc and Ammonium Nitrate in melt or liquid form in any density is beyond the scope of the product under consideration.

(iv) The subject goods are used in India, predominantly in the manufacture of explosives, such as emulsion explosives, whereas they are used as fertilizers in many other parts of the world. In fact, the interested parties have contended that the product under consideration can be only used for the manufacture of explosives in India.”

- 14. The product under consideration is classified under Chapter 31 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff heading 3102 3000. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of product under consideration.
- 15. With regard to the inclusion of Ammonium Nitrate in melt form in the scope of the product under consideration, the Authority notes that the said issue has already been decided by the Hon'ble CESTAT in the case of Solar Industries Limited V. Union of India. The Hon'ble Tribunal, after examining all the facts, came to a conclusion that since there are no imports of Ammonium Nitrate in melt form and the domestic industry is producing Ammonium Nitrate in solid form having density above 0.83 g/cc, it is inappropriate to consider another article as like article to the imported product under consideration.

“We have heard all the sides and perused the appeal records. We take up the appeals filed by the Indian importer / user of the subject goods. First of all, we note that the status and nature of goods manufactured in Indonesia is not clearly coming out from the information submitted by the interested party of the said subject country. In fact, there is no grievance or appeal by the Indonesian exporter. The point raised by the Indian importer without having a categorical assertion on the correct factual position of nature of goods manufactured in Indonesia cannot be considered. In any case, we note that the DA categorically recorded that the interested parties themselves have contended that Ammonium Nitrate cannot be imported in melt form. Since, there is production and sale of solid Ammonium Nitrate having density above 0.83 it is

inappropriate to consider another article as like article to the imported product under consideration. It is recorded that only in a situation where there was no production of solid Ammonium Nitrate in the country, Ammonium Nitrate melt could be considered as like article to the imported product. With reference to claim of the appellant that Ammonium Nitrate solids converted out of Ammonium Nitrate melt it is seen that none of the interested parties provided any verifiable evidence of such production of solid Ammonium Nitrate from melt. Apparently, the DA was not in a position to take such solid Ammonium Nitrate on part of the DI. Regarding the claim of PT Kaltim Nitrate, Indonesia, we note that they did not file exporters questionnaire response and merely submitted certain arguments. There is no verifiable information with regard to the AD/51864 of 2017 8 goods exported by the company. The DA treated PT Kaltim Nitrate, Indonesia as non-cooperative in view of incomplete exporter response filed by them.

16. The Tribunal has further noted that in case there was no production of identical article, that is, Ammonium Nitrate in the solid form in the country, only then the article which is not alike in all respects and having characteristics closely resembling those of the articles under investigation, that is, Ammonium Nitrate in the melt form, could be considered as like article. The Special Leave Petition filed against the order of the Tribunal has also been dismissed vide order dated 6th August 2018. In view of the settled position, the scope of product under consideration cannot be modified in the present sunset review. Therefore, the scope of product under consideration in the present investigation is the same as that in the previous investigation, in that, Ammonium Nitrate in melt form is excluded from the scope of product under consideration.
17. Some of the interested parties have contended that the Low-Density Ammonium Nitrate should be included within the scope of product under consideration. The Authority notes that the scope of product under consideration cannot be enlarged at the stage of sunset review. Moreover, the interested parties have not substantiated that Low Density Ammonium Nitrate produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. Low Density Ammonium Nitrate is a separate product as compared to the product under consideration in terms of usage, density, price as well as properties. Low Density Ammonium Nitrate is commercially known as Explosive or Industrial Ammonium Nitrate. Due to the oil absorption and retention capacity of Low-Density Ammonium Nitrate, it is detonable and dangerous to use. The product under consideration, on the other hand, is known as Fertilizer Grade Ammonium Nitrate or Technical Grade Ammonium Nitrate. Since the product under consideration is less porous, with less oil absorption, it is safer to use. The international prices of both Low-Density Ammonium Nitrate and product under consideration are quite different. Since Low Density Ammonium Nitrate is a different product, it cannot be included in the scope of the product under consideration for the purpose of the present investigation.
18. Some of the interested parties have contended that the domestic industry does not have the capability to manufacture Ammonium Nitrate above 0.87 g/cc. The Authority notes that this issue has already been addressed during the previous investigation, wherein the Authority verified that the domestic industry has the capability to manufacture Ammonium Nitrate upto 0.94 g/cc.
19. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority notes that the product manufactured by the applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by the other interested parties

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing:

- a. While scope of the product under consideration may include only AN solid with density of more than 0.85 g/cc, the scope of like article should include all forms of AN to determine standing.
- b. The applicant has withheld the information related to other producers of Ammonium Nitrate in the country. It has wrongly claimed to be the sole producer in India. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited, National Fertilizers Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited are also the producers of Ammonium Nitrate in the country, which is evident from the websites of the producers and publicly available information. The standing of the domestic industry should have been determined after including the production of these producers.
- c. Vijay Gas Industries Pvt. Ltd., Sukhdev Chemicals, Mauni Nitrochem, Dalmia Chemicals and Machchar Industries are also producing solid form.
- d. Information regarding the names of manufacturers, and quantity of the product under consideration produced and sold by the applicant and other producers, may also be called by the Authority from the Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO). In recent cases such as PSY and Vitamin C, the Authority called for such information.

D.2 Submissions by the domestic industry

21. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and standing:
 - a. Smartchem Technologies Limited is the sole producer of subject goods in India and is not related to any producer or exporter of the product under consideration in the subject countries or any importer in India and thus, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. Contrary to the claim of the other interested parties the applicant has already disclosed that Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited, National Fertilizers Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited are other producers of Ammonium Nitrate in India. However, none of these producers are manufacturers of Ammonium Nitrate in solid form.
 - c. Consideration of production of those manufacturing AN melt for determination of standing is inconsistent with the Anti-Dumping Rules, past findings of the Authority and the decision by the CESTAT.
 - d. Vijay Gas Industries Pvt. Ltd., Sukhdev Chemicals, Mauni Nitrochem, Dalmia Chemicals and Machchar Industries are converters of AN Melt into AN solids. Therefore, they cannot be considered as producers of the subject goods. The licensed converters are merely “processors” of the subject goods, and therefore, cannot be considered as the “domestic producers” of the like article, as per past practice of the Authority.

D.3 Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
23. The other interested parties have claimed that Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited, National Fertilizers Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited are also manufacturers of the subject goods in India. The Authority notes that the said companies manufacture Ammonium Nitrate in Melt form. Since Ammonium Nitrate in melt form is excluded from the scope of product under consideration, the production of the said companies cannot be considered for determination of total production of like article in India.

24. With regard to the contention of the other interested parties that Vijay Gas Industries Pvt. Ltd., Sukhdev Chemicals, Mauni Nitrochem, Dalmia Chemicals and Machchar Industries are producers of AN in solid form, the Authority notes that the other interested parties have made mere submissions regarding the same but have not provided any evidence. As per the information available to the Authority, the said entities are only converting Ammonium Nitrate Melt into solid form. Therefore, the said entities are converters and not manufacturers of product under consideration and accordingly, cannot be considered as the domestic producers of the like article.
25. Having regard to the information and evidence provided by the domestic industry and the other interested parties, the Authority notes that there is only one producer of the like article in India, that is, the applicant. It is noted that the applicant is not related to any exporter or importer of the subject goods and has not imported the product under consideration. The Authority, therefore, holds that the applicant constitutes the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the other interested parties

26. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
 - a. The applicant has claimed excessive confidentiality regarding demand, production, capacity and capacity utilization; market share of imports, exports at dumped prices, exports at dumped prices in relation to demand, exports at injurious prices in relation to demand, capacity in the subject countries in relation to demand in India, exportable capacity in the subject countries in relation to Indian demand, idle capacity in the subject countries in relation to Indian demand, exports below Indian prices in relation to demand in India.
 - b. The applicant has failed to meet the requirements under Trade Notice 10/2018 as it has not provided any information on volume and value of production of other producers, country wise estimates of normal value and export price, captive consumption, R&D expenses, export price per unit and purchase quantity.
 - c. The applicant has not provided the transaction-wise data to the interested parties which clearly violates the decision of Hon'ble CESTAT in Exotic Decor Pvt Ltd vs Designated Authority.
 - d. For Iran, the applicant has adopted constructed normal value, but the raw material price and consumption norms have been kept confidential, which has been accepted by the Authority.
 - e. The applicant has claimed excessive confidentiality in the petition and has redacted excerpt of de-merger agreement, and store inventory policy.
 - f. The applicant failed to disclose huge investments undertaken by them, which implies that there is no likelihood of injury.
 - g. The Appellate Tribunal has clearly held in Vitrified Tiles case that information provided to the Designated Authority on confidential basis is not required to be treated as confidential merely because it is provided to the Designated Authority on a confidential basis and has further laid down detailed guidelines to examine the claims of confidentiality.
 - h. The applicant has violated the anti-dumping rules and the trade notices and claimed excessive confidentiality, in violation of the decisions in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority, ATMA vs Designated Authority and Reliance Industries Ltd. vs Designated Authority and Ors. It has claimed excessive confidentiality as it has not circulated the paperbook presented at the time of oral hearing, neither the IHS market report which is available in public domain, nor a non-confidential summary has been provided, transaction-wise Russian customs data has also not been provided.

E.2. Submissions by the domestic industry

27. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
 - a. The exporters have failed to disclose relevant information in the non-confidential version of the responses.

- b. The exporters have claimed excessive confidentiality with regard to exports made to India and have contradicted their own statements in the questionnaire response.
- c. The exporters have claimed excessive confidentiality with regard to performance parameters, channels of distribution, adjustments to normal value and export price, purchase of raw material from related parties, country-wide production, demand and exports, corporate structure, list of products produced, accounting practices, ownership, financial links/joint ventures, manufacturing process, product specifications, effect of existing anti-dumping duty, raw material prices, contractual sales and basis of interest cost charged.
- d. The applicant requests the Authority to direct the exporters to make adequate disclosure in the non-confidential version of their response.
- e. Due to excessive confidentiality claimed by the exporters, the applicant has no clarity regarding the completeness of the response filed by the exporters/producers and the Authority may check the same.
- f. Severe prejudice has been caused to the interests of the applicant since no order has been passed by the Authority regarding acceptance or rejection of its submissions on confidentiality.
- g. Owing to the excessive confidentiality claimed by the exporters, the applicant is unable to identify whose products have been exported by Cistech International Pte Limited; Drey Moor Fertilizers Overseas Pte Limited and Rhino Rock Limited.
- h. The non-confidential version of the response filed by EuroChem group is deficient as it has not reported any adjustments for fair comparison of normal value and export price. In case no adjustments are reported in the confidential response, then the same must be rejected for being incomplete.
- i. The exporters have suppressed information regarding imposition of anti-dumping duty on exports by Russian producer to Australia and Ukraine.
- j. Contrary to the claims of the other interested parties, the applicant has provided reasoning for the confidentiality claimed in the non-confidential version of the petition. Since the applicant is a single producer, production, capacity and capacity utilisation has been shared as a trend.
- k. Since applicant is a sole producer, disclosure of demand will lead to disclosure of domestic sales, therefore, demand has not been shared. Accordingly, market share, capacities and exports in relation to demand cannot be shared. De-merger agreement being business proprietary information has not been shared.
- l. The applicant has fulfilled its obligation of providing the import data in PDF format as stated in the Trade Notice 07/2018. No prejudice has been caused to the interests of the other interested parties as they can obtain the import data from DGCI&S directly.
- m. Since the normal value for Iran has been constructed based on cost of production of the domestic industry, the price of raw material and consumption norms cannot be shared as they are business sensitive information.
- n. A comparison between the confidentiality claims of the applicant versus the exporters would show that the applicant has disclosed all relevant information, and the exporters have acted with malafide intentions to conceal all pertinent information.
- o. Installed capacity, captive consumption, R&D expenses, export price per unit are business proprietary information which cannot be disclosed.
- p. There was no format or particular question in the petition which asks for information regarding investments being undertaken. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant did not conceal such information as the same was available in public domain and accessible to all the interested parties.
- q. A non-confidential version summary of both the IHS Markit Report and Russian Customs data has been provided. However, the applicant is not authorized to share the actual report and data as it is third party information. Since such information is available in the public domain upon payment of fee, the other interested parties are free to obtain the same.

- r. The applicant has not made a paperbook but had only relied upon a compilation of documents. All the documents relied upon are present in the public domain and are easily accessible to the other interested parties.

E.3. Examination by the Authority

28. The Authority made available non-confidential version of the information provided by the various interested parties to all the interested parties as per Rule 6(7).
29. With regard to confidentiality of the information, the Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

30. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of the domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
31. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority directed all interested parties to circulate the non-confidential version of evidence submitted by them.
32. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed the information regarding the demand in India, capacity in the subject countries in relation to demand in India, exportable capacity in the subject countries in relation to Indian demand, idle capacity in the subject countries in relation to Indian demand, exports below Indian prices in relation to demand in India. The Authority notes that since the applicant is a sole producer, the disclosure of demand, capacities and exports in relation to demand will lead to disclosure of domestic sales thereof. Therefore, the Authority accepts the confidentiality claimed in respect of demand in the country, as business sensitive confidential information. However, the Authority notes that the applicant has provided a non-confidential summary of the information in the form of trends or demand.
33. With regard to the disclosure of de-merger agreement, the Authority notes that such information is not available in the public domain and contains business proprietary information. Therefore, the Authority has accepted the claims of confidentiality on such information.
34. With regard to contention that the applicant has claimed excessive confidentiality over the IHS market reports and the Russian Customs Data, the Authority notes that such information is third

party information which the applicant is not authorized to disclose. However, a non-confidential summary of the information relied upon was shared by the applicant in line with the requirements of Trade Notice 01/2013.

35. With regard to the contention that the applicant has not shared the raw material price and consumption norms for determination of normal value for Iran, the Authority notes that the normal value for Iran has been constructed based on the cost of production of the domestic industry. Since raw material price and consumption norms of the domestic industry is business sensitive information, the Authority has accepted the confidentiality claims for such information.
36. With regard to the DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to volume and value of the imports from the exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge their own counter claims based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy and (ii) the interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per the prescribed format. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across the parties and the investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by the other interested parties

37. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- a. Vide letter dated 8th October 2021, the interested parties had highlighted that a petition with addendum was filed post initiation, implying that the investigation was initiated based on inadequate information. The Designated Authority clarified that the domestic industry had filed a consolidated non-confidential version of the petition, which included a letter filed pre-initiation. This implies that the non-confidential version was not filed with the confidential version
 - b. The users have circulated the questionnaire response as well as written submission to all the interested parties three days prior to the oral hearing. There are no mandatory guidelines regarding the timeline for circulation of the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
 - c. Sunset reviews for the continuation of anti-dumping duty is an exception to the otherwise mandated expiry of the duty after five years which is consistence in the approach of Appellate Body in US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review and in US-Oil Country Tubular Goods.
 - d. Indonesia was excluded from the scope of the subject countries on the ground that there were no imports of the subject goods from Indonesia.
 - e. The applicant has misguided the Authority to believe that goods of Georgian, Iranian and Russian origin are being shipped to India through countries like Singapore, Uzbekistan, Switzerland and UAE. Russian customs data and secondary data cannot be considered reliable, and reference should only be made to data of the Director General, Safeguards and DGCI&S.
 - f. The import data provided by the applicant is misleading and there are significant contradictions between import volume of the subject countries provided in Proforma IVA and the import data provided in the import statement of the petition. Further, there are discrepancies in the data filed by the applicant when compared to the import data as per DGCI&S.
 - g. Acron may kindly be treated as an interested party in this investigation as it had registered itself with the Authority within the prescribed timelines as per the guidelines provided in Trade Notice No 11/2018.

- h. The initiation notification shows that the Authority has already drawn conclusions at the stage of initiation itself, without any evidence on record.
- i. The applicant has not filed the non-confidential version of the revised application after removing Indonesia from the subject country.
- j. No surplus/idle capacity is available with the Georgian producer.
- k. There were no exports of subject goods from Georgia to India during the POI and last two years as was the case with Indonesia. Georgian producer has not dumped the subject goods into India.
- l. No other country has imposed any anti-dumping duty against Georgia.
- m. Indonesia was excluded from the scope of the subject countries despite the fact that significant idle / surplus capacity to the tune of 32% was available with the Indonesian producers.
- n. Georgia has a very limited capacity, which is already over-utilised. Accordingly, there is no likelihood of dumping and injury.
- o. The applicant industry has made contradictory and misleading claims regarding Georgian production and demand in its application to prove non-existent case of likelihood.
- p. NIL duty was imposed on Novomoskovsk, which is a Russian producer. Despite the same, they were able to export only a miniscule quantity during the POI as India is not a price attractive market.

F.2. Submissions by the domestic industry

38. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- a. The applicant filed the consolidated non-confidential version of the petition with addendum in line with the requirements prescribed by the Authority to ensure that the interested parties have an opportunity to defend their interests and make submissions.
 - b. The circulation of the non-confidential versions of the response by L&L Law offices on behalf of the importers was deliberately delayed, preventing the applicant from defending its interests. Due to such delay, the applicant was unable to examine the responses and offer meaningful comments during the hearing.
 - c. The delayed circulation of the responses was a deliberate and wilful act by the users. The responses were submitted at the end of the last working day prior to the hearing.
 - d. Failure to circulate the submissions in a timely manner should prevent such parties from participating in the investigations and their response should be rejected by the Authority. Reliance is placed on US – Hot-Rolled Steel, US – Corrosion-Resistant Steel and US – Oil Country Tubular Goods.
 - e. Contrary to the claims of the other interested parties, Indonesia was dropped from the subject countries as there was no prima facie evidence of likelihood of dumping and injury due to imports from Indonesia.
 - f. The oral hearing held on 29th November 2021 was ineffective as the applicant was denied an opportunity to defend its interests and raise pertinent issues before the Authority.
 - g. The Authority is requested to examine whether producers have also exported the subject goods to India by way of transshipment from a different country to avoid anti-dumping duty.
 - h. The Authority is requested to call for relevant information from Petroleum and Explosives Safety Organization (“PESO”) and customs authorities regarding the transshipment of the subject goods.
 - i. With regard to the contention of the other interested parties, the applicant had clarified that there was a linking error and the correct figures were in Proforma IVA.

- j. Contrary to the submissions of the other interested parties, the criteria to determine continuation of anti-dumping duty is analysis of likelihood parameters and not the number of years that the duty has been in place. The Authority has recommended continuation of the anti-dumping duty irrespective of duration in a number of investigations such as that on Caustic Soda, Phenol, Melamine, PTFE, 1-Phenyl 3-Methyl 5-Pyrazolone, Front Axle Beam and Steering Knuckle, Acrylonitrile Butadiene Rubber NBR, FDY, Nylon Tyre Cord Fabric etc.
- k. The investigation was initiated after examining the prima facie evidence of dumping, injury and causal link has initiated the present investigation as per the requirements of Rule 5(3)(b) of the Anti-Dumping Rules.
- l. The evidence required for the purpose of initiation may not be of the same quality and quantity as that required for final imposition of duty. Reliance is placed on Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico.
- m. Contrary to the claims of the other interested parties, it cannot be claimed that Indian customs data is reliable, but the data provided by Russian customs is unreliable.
- n. The Customs Authority found that imports of subject goods from Uzbekistan was mis-declared and were found to be of the Iranian origin and accordingly, collected anti-dumping duty on the same.
- o. The applicant could not have filed a fresh application after removing Indonesia as a subject country after the Authority had already initiated the case. The Anti-Dumping Rules do not provide for such a fresh application.

F.3. Examination by the Authority

- 39. With regard to the contention that the investigation was initiated based on inadequate information as the domestic industry has filed the non-confidential version of the petition along with addendum post initiation, the Authority notes that the domestic industry filed a non-confidential version of the petition, along with the confidential version. The domestic industry filed information regarding imports from various sources, prior to initiation of the investigation. In order to ensure that the interests of the interested parties are safeguarded and they are allowed to file comments on the additional information filed post application, such information was included as an addendum to the petition for circulation to the interested parties.
- 40. In respect of the requests made by the interested parties to exclude Georgia from the scope of the subject countries, the Authority has noted that on the basis of evidence on record, there is no exports of the subject goods to India during the POI and preceding years i.e., no dumping and consequent injury. There is no surplus capacity available with the only Georgian producer during the POI as evidenced from the information shared by the applicant as well as the interested parties. Further, there is no surplus capacity available with the only Georgian producer during six months post-POI. It has been also noted that any other country has not imposed any anti-dumping duty against Georgia. In view of the facts available with the Authority, it has been noted that there is no evidence of likelihood of recurrence of dumping and injury in the event duty is allowed to expire on the import of the subject goods from Georgia. Accordingly, Georgia has been excluded from the subject countries and the investigation has been conducted only in respect of the imports of subject goods originating in or exported from Russia and Iran (hereinafter referred to as the “subject countries”).
- 41. With regard to the contention that Georgia should be dropped as a subject country, the Authority notes that exporter is the sole producer of the subject goods in Georgia and there have been no exports of the subject goods from Georgia to India during the POI and the preceding two years.
- 42. As per the information on record with the Authority, the capacity of the exporter is *** MT during POI and ***MT during six months post POI. The production of the producer/exporter during the POI and the six months post POI are ***MT and ***MT respectively as per the information available with the authority.
- 43. The Authority after examining the facts as provided above notes that the exporter is operating at its maximum capacity and no surplus capacity was available with him during the POI and the six months post POI. It has been also noted that any other country has not imposed any anti-dumping

duty against Georgia. The Authority notes that there is no evidence of likelihood of recurrence of dumping and injury in the event duty is allowed to expire on the import of the subject goods from Georgia. Therefore, the Authority terminates the investigation with respect to the producer/exported from Georgia. The subject countries for the purpose of this determination consists of Russia and Iran.

44. With regard to the transshipment of subject goods from different countries, the Authority has noted some entries of transshipment of subject goods originating in the subject countries. Since DGC&S data reports only country of consignment and not the country of origin, the Authority has relied upon facts available on record to determine the volume of exports from Russia as below.
45. With regard to the contention that there is no transshipment as per the DGC&S data, the Authority notes that the volume of imports from Russia as reported in the DGC&S data are much less than the volume of exports as per the Russian Customs data as well as the data submitted by the participating producers/exporters. The data as per responses of the participating producers shows that the volume reported are comparable to that in the Russian customs data.
46. As regards the duration of duties imposed, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to the domestic industry against injurious dumping. The present investigation has been initiated to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury, in the event of expiry of duty. Should the Authority find that dumping and injury are likely to continue or recur in the absence of duties, the anti-dumping duties shall be extended, notwithstanding the period of imposition of duties or the number of investigations.
47. With regard to PJSC Acron the Authority notes that PJSC Acron has been registered as an interested party in the present investigation and the submissions made on behalf of the exporter has been taken on record. However, since the exporter has not exported the product under consideration to India during the period of investigation, the current dumping margin cannot be determined.
48. With regard to the contention that the present investigation has been initiated without any evidence on record, the Authority notes that the applicant has provided a duly substantiated application claiming likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the absence of duties. At the time of initiation of investigation, the Authority prima facie satisfied itself of the need for initiation of sunset review investigation concerning present anti-dumping duties based on the evidence furnished by the domestic industry establishing likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the present duties are allowed to expire.
49. Regarding the contention that the domestic industry has not filed a revised petition after removing Indonesia, the Authority notes that the domestic industry filed a duly documented petition based on which the present investigation was initiated, the non-confidential version of the same has been circulated to all the interested parties. Once the investigation is initiated, there can be no fresh application post initiation of the investigation. The Authority has made its observations hereinbelow on the basis of data, excluding that for Indonesia and Georgia as the subject countries.
50. Some interested parties have contended that there is variation in data submitted by the domestic industry. The Authority notes that the data on record has been verified by the Authority and thereafter used for the analysis given hereinunder. Wherever necessary, clarifications have been sought from the applicant regarding any inconsistency in the data.
51. The domestic industry has emphasized that the users circulated the non-confidential version of the response filed by them belatedly. The Authority finds delays in circulation of responses to be undesirable. However, in the facts of the present case, no prejudice has been caused to the interests of any interested party. The Authority has considered submissions made by all interested parties, even after the date of written submissions, in the interest of justice.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the other interested parties

52. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. The normal value estimated for Russia is based on data for previous years adjusted for changes to export price indicates skewed adjustments just to show dumping.

- b. Russian customs data has been used to work out export price because the price in it is too low and abnormally high adjustments towards ocean freight and inland transport charges have been shown to work out an artificial high dumping margin.
- c. The applicant used the Uzbekistan data and some DRI investigation data to determine the export price from Iran, because the DGCI&S data would not show any dumping.
- d. At present, the imported Ammonium Nitrate prices as per International Market Price are about USD 650 PMT - 670 PMT, implying that there is no dumping.
- e. The particular market condition referred in the petition has already been taken into account in the determination of dumping margin. But the capacity to produce and dump, will depend upon several other factors which the applicant has not established.
- f. Existence of a “particular market situation” cannot be examined for the first time in a sunset review investigation in terms of Rule 23(1B) and could have been examined only in a changed circumstances review.
- g. Any particular market situation arising out of government intervention, can be examined only by way of an anti-subsidy investigation, as noted in case of Uncoated Copier Paper from Indonesia.
- h. The Authority had not accepted the contention of the applicant regarding purchase of gas through Gazprom in the original investigation, and the applicant did not challenge the same in appeal. The issue cannot be raised at this stage now.

G.2. Submissions by the domestic industry

53. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- a. The non-confidential version of the response filed by EuroChem group is deficient as it has not reported any adjustments for fair comparison of normal value and export price. In case no adjustments are reported in the confidential response, then the same must be rejected for being incomplete.
 - b. Royalty paid by EuroChem Trading GmbH is a direct selling expenses since the company does not have any manufacturing facility and thus, it must be reduced while determining the export price.
 - c. The Authority is requested to examine whether the records maintained by JSC Azot are in accordance with GAAP of Russia. If the records are not as per GAAP, the cost of production should not be determined based on the records of the producer.
 - d. Commission received by Rawfert Offshore SAL for exports to India must be adjusted in the determination of export price.
 - e. The price of natural gas in Russia are government controlled and available to the producers at significantly lower prices as held by European Commission in Council Regulation 661/2008. Therefore, the cost of production and the prices in the domestic market of the exporters are suppressed. The cost of production of the responding producers should be adjusted to reflect undistorted prices.
 - f. The normal value for Russia has been determined based on selling price in Russia. Since the prices for the period of investigation were not available the previous year prices have been adjusted in order to determine the normal value. The other interested parties have not provided any evidence to refute the claim.
 - g. The DGCI&S data shows country of consignment and not country of origin therefore, the applicant has used Russian customs data for determining the total exports from Russia to India.
 - h. Russian customs data is a better source to calculate net export price as it records exports at FOB level while the export price reported in DGCI&S data would be the price at which the trader has sold in India. Therefore, the margin of the trader, as well as expenses incurred are added in the price reported in DGCI&S data.

- i. Since the subject goods are being transshipped and DGCIS data contains only country of consignment and not country of origin, the applicant have identified country of origin as per secondary sources.
- j. While the other interested parties have submitted that the international prices of Ammonium Nitrate are \$650-670 per MT, the import price in India from the subject countries is \$244 per MT. The international prices of the subject goods have increased due to increase in cost of production globally.
- k. Contrary to the contentions raised by the other interested parties, Rule 23 of the Anti-Dumping Rules provides that normal value, export price and dumping margin has to be determined as per the provisions of Rule 10. Thus, all obligations pertaining to determination of normal value apply to sunset review investigation.
- l. Since the producers / exporters from Georgia and Iran have not filed any response, the Authority is requested to continue the same quantum of anti-dumping duty on imports from Georgia and to determine normal value and export price for the producers from Iran based on facts available in the petition itself.
- m. The normal value for Iran has been constructed based on cost of production of the domestic industry duly adjusted for SG&A expenses and reasonable profits.
- n. The Authority may determine export price for imports from Iran based on the information filed in the petition wherein the applicant has taken CIF price reported in import data and adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission.
- o. The other interested parties have agreed to the fact that there is a particular market situation in Russia. The Authority is requested to consider it for determination of dumping margin.
- p. Since PJSC Acron has not exported the subject goods to India no individual dumping margin and injury margin can be awarded to them.
- q. Contrary to the contentions of the other interested parties, the applicant has not requested the Authority to examine the countervailability and quantum of subsidies provided but has highlighted that a particular market situation exists in Russia due to state-controlled prices of natural gas.

G.3. Examination by the Authority

54. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

55. The Authority sent questionnaire to the known exporters / producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers / exporters from the subject countries have filed the exporters' questionnaire response:
- a. Azot, JSC (Novomoskovsk)
 - b. Cistech International Pte. Ltd.
 - c. Drey Moor Fertilizers Overseas Pte Ltd, Singapore
 - d. EuroChem Trading GmbH
 - e. EuroChem Trading RUS, LLC
 - f. JSC Azot, Kemerovo
 - g. JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk
 - h. Rawfert Offshore SAL
 - i. Rhino Rock Limited
 - j. SBU Nitrotrade AG
56. With regard to the reliance on Russian customs data at the stage of initiation, the Authority finds that owing to the transshipment of goods exported from Russia through other countries, the DGCIS data has not captured the complete volume. Therefore, the Authority finds that the Russian customs data provided sufficient prima facie evidence for the determination of export price of the subject goods from Russia. However, the Authority has determined the export price for cooperating producers based on the responses filed by them.
57. With regard to the contention that there is a particular market situation in Russia due to state-controlled prices of natural gas, the Authority notes that the present investigation is a sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of the product under consideration from Iran, Georgia and Russia. The domestic industry in the previous investigation raised the same contention which was duly addressed by the Authority. The domestic industry has not shown any change in circumstances with regard to prices of natural gas since the previous investigation.

G.4. Determination of Normal Value for Russia

Normal value for Azot, JSC (Novomoskovsk), JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk Group

58. From the data filed by Azot, JSC (Novomoskovsk) & JSC Nevinnomyssky Azot, the cooperating producers and exporter from Russia, it is noted that they have exported ***MT of the subject goods to India through traders to unrelated customers. The exporter has sold ***MT in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of the subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. The adjustments claimed by the producer/exporters have been considered to arrive at the normal value for the quantity sold in the domestic market. The weighted average Normal Value for Azot, JSC (Novomoskovsk) and JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk so determined is mentioned in the table below.

Normal value for JSC Azot, Kemerovo Group

59. From the data filed by JSC Azot Kemerovo, the cooperating producer and exporter from Russia, it is noted that it has exported ***MT of the subject goods to India through traders to unrelated customers. The exporter has sold *** MT in the domestic market to unrelated customers. In order to determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of the subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. The adjustments claimed by the producer/exporter has been considered to arrive at the normal value for the quantity sold in the domestic market. The weighted average normal value for JSC Azot, Kemerovo so determined is mentioned in the table below.

Normal value for all non-cooperative producers from Russia

60. Normal Value for non-cooperative producers of Russia has been taken based on the facts available in accordance with Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.5. Determination of export price for Russia

Export price for Azot, JSC (Novomoskovsk), JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk Group

61. In the exporters' questionnaire response, the producer / exporter stated that during the POI they have exported *** MT to unrelated parties in India through trader. The Authority has further made adjustments in order to arrive at the export price at ex-factory level. Accordingly, the export price is provided in the table below showing the dumping margin calculation and percentage.

Export price for JSC Azot, Kemerovo (Producer) Group

62. In the exporters' questionnaire response, the producer / exporter stated that during the POI they have exported *** MT to unrelated customers in India through traders. The Authority has further made adjustments in order to arrive at the export price at ex-factory level. Accordingly, the export price is provided in the table below showing the dumping margin calculation and percentage.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Russia

63. Export price for non-cooperative producers/exporters of Russia has been taken based on the facts available in accordance with Rule 6(8) of the Rules. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.6. Determination of normal value for Iran

64. The Authority notes that none of the producers/ exporters from Iran have filed exporter's questionnaire responses. In view of non-cooperation from all producers/ exporters in Iran, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.7. Determination of export price for imports from Iran

65. The Authority notes that none of the producers/exporters from Iran have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from the producers/exporters from Iran, the export price for the product under consideration for the subject countries has been computed based on DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission. The Authority notes the information provided by the domestic industry with regard to imports in DGCI&S data being under-reported. In the absence of any response from Iran and any information from other parties, the Authority has considered the information provided by the domestic industry as facts available on record, and determined the export price on the basis thereof.

G.8. Dumping Margin

66. Based on the normal value and the export price determined as above, the dumping margin for producers / exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below. The dumping margin so determined is negative for the cooperating producers/exporters. However, the dumping margin determined for non-cooperating producers / exporters in the subject countries is above de-minimis.

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
Russia						
1	Azot, JSC (Novomoskovsk) and JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk	***	***	(***)	(***)	Negative
2	JSC Azot, Kemerovo	***	***	(***)	(***)	Negative
3	Non-cooperative/ residual exporters	***	***	***	***	10-20
Iran						
1	Non-cooperative/ residual exporters	***	***	***	***	70-80

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1. Submissions by the other interested parties

67. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury, causal link and likelihood of dumping and injury:

- a. There are no imports from Georgia and Indonesia and imports from Iran have also decreased, and only imports from Russia have increased.
- b. There is a marginal increase in import from Russia in the period of investigation but there is a drastic decline in the total imports. The applicant has claimed that demand has declined, without providing actual data.
- c. The price undercutting must be examined in the light of profits to the applicant, which have been positive and significant, except during the pandemic.
- d. The applicant is able to price its products much higher than the cost of production, thus, the question of price suppression/depression does not arise.
- e. The production and capacity utilization of the applicant increased during the injury period and declined only during the period of investigation due to the pandemic.
- f. The domestic sales of the applicant have increased during the investigation period except period of investigation and its preceding year, both of which were affected by the pandemic. The applicant has not lost market share to alleged dumped imports.
- g. The applicant did not face accumulation of inventories except during the period of investigation, which was due to the pandemic.
- h. The applicant has been efficiently converting its capital into profits and was making enough financial gains with optimum utilization of its capital until the pandemic.
- i. Even if the imports are increasing at dumped prices, they are fully neutralized by the anti-dumping duty, and thus, cannot be considered as causing injury.
- j. As per the applicant's own admission in their 2020 Annual Report Ammonium Nitrate business is on record high performance and there is no threat to this business.
- k. The applicant has specifically stated in its Annual Report of 2020 that its operations in multiple locations were scaled down or shut down due to the lockdowns imposed after the outbreak of the pandemic.
- l. While the balance sheet shows that net profit of Technical Ammonium Nitrate improved, the data on record shows decline in profits during the period of investigation.

- m. Taking advantage of its position, the applicant has set up a new plant which is expected to go into production in 2024.
- n. There is a huge demand supply gap in India necessitating imports, which is evident from the data available in the PESO website.
- o. The injury to the domestic industry is caused by decline in export sales, which caused decline in production and capacity utilization, and increased fixed costs per unit. The Authority should make the adjustments in the cost of domestic sales on account of the significant decline in the export sales.
- p. Employment and domestic finance cost have increased abnormally over the injury period, even when the capacity remained the same.
- q. The profitability of the applicant was impacted due to the significant increase in the interest costs and depreciation and amortization expenses.
- r. The import data provided by the applicant is misleading and there are significant contradictions between import volume of the subject countries provided in Proforma IVA and the import data provided in the import statement of the petition. Further, there are discrepancies in the data filed by the applicant when compared to the import data as per DGCIS.
- s. The applicant has stated different figures of production and capacity for Georgia at different places to show likelihood.
- t. The applicant has admitted that they did not suffer injury, even due to imports from other sources; and there is no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
- u. The information provided by the applicant regarding the likelihood of recurrence of injury are devoid of any material evidence for an 'objective examination' based on 'positive evidence'. The information provided does not meet the requirements prescribed under Pakistan – BOPP Films, as it is speculative.
- v. Since there is a demand-supply gap in the country, India is a price-taker, and the exporters would be able to charge higher price in the market.
- w. If India is a more price attractive market as compared to others, it goes to prove that there is no dumping and that Indian market allows the domestic producers are able to sell at high price and make profits.
- x. Merely existence of excess capacities does not show likelihood. The applicant must provide adequate evidence to show the price trends in the domestic market and external market to establish a likelihood of dumping in the imminent future which is in consistence with the approach in Indian Spinners Association v. Designated Authority and White Cement from UAE and Iran, Rubber Chemicals, MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT, from China PR and PX-13 (6PPD) from China PR and Korea RP. Further, in the present case, the subject countries are themselves suffering shortage of the product under consideration.
- y. 100% of the exports from Georgia have been alleged to be dumped, without establishing the normal value or providing complete data for exports.
- z. The data presented in the application shows that the capacity in Iran and domestic demand in Iran is fully balanced and there is no exportable surplus.
- aa. The application does not indicate source of information for surplus capacities.
- bb. The applicant claims that although the producers in Russia already hold significant excess capacities, they are planning further capacity expansions. At the same time the applicant has enclosed a news item which shows that the domestic demand in Russia is on the rise.
- cc. JSC Azot, Kemerovo has not dumped the subject goods into India, and has no surplus capacities.
- dd. JSC Rustavi Azot has no surplus capacities, has not exported the subject goods to India, and has not engaged in dumping. Therefore, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

- ee. The applicant claims that once the duties are removed the third country exports from the subject countries will be diverted to India which contradicts its own statement that such imports will be at dumped prices.
- ff. The applicant claims that 86% of the third country exports from Russia are also at dumped prices without providing any data for the same.
- gg. The petition does not provide any information as to the likely volume of trade that could be diverted to India and price thereof due to trade measures imposed by other countries.
- hh. Since the applicant is a dominant player, and imports, which were suffering anti-dumping duty, had to adjust to the price level of the applicant. Therefore, the imports were lower priced. However, once duty is removed, the import price would increase.
- ii. No other country has imposed anti-dumping duty against Georgia.
- jj. Australian Commission has withdrawn the anti-dumping duties against Russia vide notification dated 20th May 2021 which proves no likelihood of dumping and injury from Russia.
- kk. The supply of ammonia has declined significantly in 2021, while prices have increased, which shows that the subject imports are likely to decline further.
- ll. The prices of product have increased, due to shortage of supply caused by increased demand for the product as fertilizer in many cold countries. If the anti-dumping duties are revoked, even if imports enter the domestic market, they will not be injurious to the applicant.
- mm. North America and Europe are much more price attractive for the exporters than India as the prices have seen a spike, without any downward trend, due to shortage of the product.
- nn. The applicant has kept silent on the inventories of Ammonium Nitrate with the producers/exporters of the subject countries during the period of investigation.
- oo. The applicant should submit the segregated data on injury from imports from other countries, and further provide an opportunity to all other interested parties to comment on the same.
- pp. As per the annual report of the applicant, it has made significant investments worth INR 225 crores and had enhanced its capacity from 1200 MT per day to 1320 MT per day, and further expects to enhance it upto 1400 MT per day.
- qq. The depreciated plants of the domestic industry are the cause of inefficiencies faced by the domestic industry, which is reflected in cash profits.

H.2. Submissions by the domestic industry

68. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury, causal link and likelihood of dumping and injury:
- a. While the demand has remained constant as compared to the base year, the imports from Russia have increased by 25%.
 - b. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant has not mentioned in its annual report that Ammonium Nitrate business is on record high. Since the annual report pertains to 2020-21, and anti-dumping duty is in force, there was no threat to Ammonium Nitrate business in imminent future at the time when the report was published.
 - c. While the balance sheet refers to profits of the company as a whole, the data submitted for the investigation pertains to only subject goods.
 - d. Imports of the subject goods from Bulgaria, Turkey, Uzbekistan and Ukraine are not causing injury to the domestic industry as the price of imports is significantly higher than the price of imports from Russia.
 - e. Contrary to the submissions of the other interested parties, imports from Iran increased more than 10 times in the period of investigation as compared to previous year. Producers in Georgia are unable to sell subject goods in India at fair prices which is evident from the fact that even though they hold excess capacities, the imports from Georgia have stopped post imposition of duties.

- f. Contrary to the submissions of the other interested parties, the data on record shows that a number of import transactions are priced below the price of domestic industry even with anti-dumping duty in force. The domestic industry has lost market share due to increase in imports from Russia. The production, capacity utilisation and sales of the domestic industry have declined.
- g. Even if price undercutting is evaluated in light of profits made by the applicant, it would be seen that while applicant earned ***% profits, the price undercutting during the period of investigation was ***%. The profits of the domestic industry are likely to reduce due to cessation of anti-dumping duty and it is likely to incur losses.
- h. The production and capacity utilization of the applicant declined prior to pandemic in 2019-20.
- i. Contrary to the submissions of the other interested parties, 2019-20 was not impacted by the pandemic which is evident from the fact that the demand and imports increased in this period. The sales of the domestic industry declined in 2019-20.
- j. Contrary to the submissions of the other interested parties, the accumulation of inventories is not due to decline in demand owing to the pandemic. The production of the domestic industry was much less than the demand in the country and hence, the accumulation of inventories is only due to the subject imports.
- k. While the other interested parties have contended that the domestic industry has not suffered injury, they have not given any evidence that there is no likelihood of dumping and injury.
- l. The plans of the domestic industry to establish a new plant do not indicate absence of likelihood of injury. Rather, it indicates that dumping is required to be prevented, to allow the new plant to reach break-even.
- m. IHS Fertecon Nitrates Report has been provided to the Authority in order to show the excess capacities. While the name of the source has been shared, the same being third party information cannot be shared with the other interested parties.
- n. The other interested parties have failed to demonstrate lack of positive evidence or that the Authority is unable to undertake an objective examination.
- o. The producers in the subject countries have continued to dump the subject goods, despite anti-dumping duties in force.
- p. The producers in Georgia and Russia are exporting the product under consideration to other countries at dumped and injurious prices. ***% exports from Georgia and ***% exports from Russia are at dumped prices.
- q. The subject imports from Russia have increased decrease in the demand. In the absence of anti-dumping duty in force, exports are likely to increase further and take away the market share of the domestic industry.
- r. The capacities and production in the subject countries are in excess of demand in the said countries making the producers highly export oriented. The producers in Iran and Russia hold idle capacities which are 5 times the demand in India.
- s. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant has provided price trends as well as information with regard to continued dumping in India, dumped and injurious imports to other countries by producers in Georgia and Russia, India being a price attractive market as well as likely injury in case of imports at current prices.
- t. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant has provided export data from Georgia to other countries to the Authority. The cost of production of Georgia has been determined based on cost of production of the domestic industry adjusted for SG&A expenses and reasonable profits. The exports from Georgia to other countries is below the estimated cost of production.
- u. The Authority is requested to consider average export price of dumped and injurious transactions from Georgia to all other countries in order to determine the likely export price to

India as previously done by the Authority in the sunset review investigation on imports of Ductile Iron Pipes from China PR.

- v. Contrary to the submissions of the other interested parties, the article only shows the normal value. While the article relates to 2019, the applicant has provided data for 2020 which shows surplus capacities despite increase in demand.
- w. India is an important market for the producers in the subject countries as exports to India constituted 75% of the total exports from Iran, 30% of the total exports from Georgia and 7% of the total exports from Russia prior to imposition of anti-dumping duty.
- x. Russian producers have lost market due to imposition of anti-dumping duty on imports from Russia in Australia, European Union and Ukraine.
- y. The final report issued by the Australian Commission shows that the dumping margin in the said investigation was positive which proves that producers in Russia are engaged in unfair trade practices.
- z. Mere fact that no other country has imposed anti-dumping duty against imports from Georgia, does not indicate that there is no likelihood of dumping and injury.
- aa. India is a more price attractive market as significant exports from Georgia and Russia to other countries are at prices below the prices prevailing in India.
- bb. The price attractiveness of India indicates that the exporters have an added incentive to divert their exports to India as they will be able to get better prices in India as compared to exports to other countries. Likelihood of dumping has to be analysed with respect to normal value and not third country prices.
- cc. The imports are likely to suppress and depress the prices of the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty which is evident from the fact that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry even though anti-dumping duty is in force.
- dd. The domestic industry has been able to earn profits only due to anti-dumping duty in force. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry will likely be forced to match import prices. Thus, there is likelihood of price suppression/ depression.
- ee. The subject imports are entering the market at prices below the cost of sales of the domestic industry. In case of cessation of duties, the prices are likely to decline further.
- ff. Due to the low prices of natural gas, the producers in Russia are able to produce and supply subject goods at significantly lower prices than the fair price for the Indian market.
- gg. In the event of cessation of the anti-dumping duty, the sufficient capacity in the subject countries is enough to wipe out the Indian industry from the market. The domestic industry will be forced to reduce prices in order to sustain in market and is likely to suffer losses, cash losses and record a negative return on investment in such a scenario.
- hh. As per the response filed by the producers in Russia, India constitutes a small market for them. Despite that, exports from Russia are accounting for more than 20% of the demand in India, even with the duties in force which clearly shows the surplus capacities held by the producers in Russia.
- ii. Participation of a new shipper in the present investigation clearly shows the interest of the producers in the Indian market.
- jj. The imports from other countries have not caused injury to the domestic industry.
- kk. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant is not required to provide volume of exports that may be diverted to India. The exports from Russia are not growing at the same pace as production in Russia.
- ll. The Indian market is not a price taker as evident from the fact that despite a demand-supply gap prior to imposition of duty, the exporters had to resort to dumping to sell the product. Further, the global capacities of the subject goods are more than global demand creating a surplus.

- mm. Likelihood analysis is required to be conducted for the country as a whole and not individual producers. In case the Authority decides to rely on information submitted by JSC Azot, Kemerovo, the same should be first disclosed to the domestic industry. The exporter has claimed all relevant information confidential due to which the applicant is unable to defend its interests.
- nn. JSC Rustavi Azot has not filed a response in the present investigation. Since likelihood information has not been submitted by the exporter in part-II of the questionnaire, the Authority may kindly rely on facts available as held done in the anti-dumping investigation on imports of Purified Terephthalic Acid.
- oo. Contrary to the submissions of the other interested parties, fertilizers are a seasonal product and increase in demand for fertilizers is temporary in nature.
- pp. Since Russian imports increased over the injury period in India, it is evident that Russian producers need market more than what North America and Europe can provide.
- qq. The applicant has provided all the information available to it regarding likelihood of dumping and injury. The Authority may analyse inventories of product under consideration with the producers in the subject countries in accordance with the response filed by them. There is no requirement to establish each parameter listed in Annexure – II to show likelihood.
- rr. The performance of the domestic industry has been segregated for domestic and export markets. The exports by the applicant have been insignificant over the injury period and cannot account for injury to the applicant.
- ss. The segregated data for injury for imports from other countries is irrelevant as the domestic industry has not suffered any injury.
- tt. By stating that imports suffering anti-dumping duty had to adjust to the price level of the applicant, the other interested parties have conceded that the exporters have absorbed the anti-dumping duty. In such a case, the duties should be enhanced. Russian producers are able to manipulate the price due to availability of cheaper natural gas.
- uu. The present investigation being a sunset review, there is no requirement to establish a causal link between the likely dumping and likely injury as observed by the Appellate Body in United States – Anti dumping measures on OCTG from Mexico. Nevertheless, the injury to the domestic industry is not likely due to any other known factors.
- vv. Increase in employment and finance cost is irrelevant as the applicant has not claimed injury. Interest cost as well as profitability have declined in the period of investigation.
- ww. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant earned higher profits as its plants are depreciated, thus the same cannot be a cause of inefficiency.
- xx. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Ammonium Nitrate plant of the applicant did not suffer any shutdown due to the pandemic.
- yy. Intangible assets cannot be excluded for determination of non-injurious price as is evident from the provisions of Annexure – III to the Anti-Dumping Rules and Manual of Operating Procedures for Trade Remedial Investigations.
- zz. Even if intangible assets are excluded for determination of non-injurious price, they cannot be excluded for determination of injury.

H.3. Examination by the Authority

- 69. The Authority has examined the arguments and counter arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 70. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."

71. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
72. With regard the contention that financial statements of the applicant show an improved performance, the Authority notes that the financial statements relate to the company as a whole. As per the provisions of para (vi) of Annexure – II to the Anti-Dumping Rules, the effect of imports on parameters of the domestic industry shall be assessed in relation to the like article only.
- “(vi) The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers’ sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.”*
73. Therefore, analysis of the effect of dumped imports is required to be undertaken in relation to the domestic production of the like product where the separate data permit such examination. Only in the cases where such examination is not possible due to collective data, the Authority is required to examine the production of narrowest group or range of products which includes the domestic like product. In the present case, separate data for the performance in terms of production, sale and profitability of the like article has been provided by the domestic industry. Since such separate data is on record, and has been verified by the Authority, it shall form basis of the injury analysis, in accordance with the provisions of para (vii) above. Accordingly, the performance of the applicant in its total operations is not relevant.
74. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.

I. Assessment of demand / apparent consumption

75. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	99	95
Subject imports	MT	1,57,788	80,513	75,396	1,10,339
Other imports	MT	46,808	1,49,896	2,02,905	1,06,596
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	114	100

76. It is seen that the demand for the subject goods increased till 2019-20 but declined thereafter in the period of investigation. The applicant has submitted that decline in demand during the period of investigation is due to prolonged monsoons, low demand in the infrastructure sector due to change in government and the impact of the Covid-19 pandemic which is temporary. This has not been disputed to by other interested parties.

II. Volume effect of the dumped imports

77. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S, the Russian customs data and other facts available on record with regard to transshipment of goods. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury period and the period of investigation are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Subject imports	MT	1,57,788	80,513	75,396	1,10,339
Georgia	MT	21,620	-	-	-
Iran	MT	56,512	21,555	979	10,388
Russia	MT	79,656	58,958	74,417	99,951
Other imports	MT	46,808	1,49,896	2,02,905	1,06,596
Total	MT	2,04,596	2,30,409	2,78,301	2,16,935
Subject countries import in relation to					
Domestic production	%	***%	***%	***%	***%
	Trend	100	44	46	74
Consumption	%	***%	***%	***%	***%
	Trend	100	47	41	72
Total Imports	%	77%	35%	27%	51%

78. It is seen that:
- The volume of subject imports declined till 2019-20 but increased in the period of investigation.
 - The subject imports in relation to domestic production declined in 2018-19, and thereafter increased till the period of investigation.
 - The subject imports in relation to consumption declined till 2019-20 then increased in the period of investigation. The share of subject imports in total imports followed the same trend.

III. Price effect of the dumped imports

79. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject countries with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

80. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

S. No.	Particulars	UOM	POI
1	Import Volume	MT	1,10,339
2	Import Value	₹ Lacs	20,046
3	CIF Price	₹/MT	18,168
4	Custom duty	%	8%
5	Custom duty amount	₹/MT	1,363
6	Cess on custom duty	₹/MT	136
7	Landed Price	₹/MT	19,667
8	Net selling price	₹/MT	***
9	Price undercutting	₹/MT	***
10	Price undercutting	%	***%
11	Price undercutting	Range	10-20

81. It is noted that price undercutting during the period of investigation is positive and significant for subject countries. In view of the positive price undercutting, the Authority finds that the Indian market cannot be considered a price-taker. Despite the demand-supply gap, the imports have entered at lower prices.

82. The other interested parties have submitted that the price undercutting should be analysed in the light of the profits made by the domestic industry. However, the Authority notes that while price undercutting is seen only for the period of investigation, the profitability trends are seen over the period. The Authority notes that since the price undercutting is positive and significant, the domestic industry is likely to be forced to match the import prices in case of expiry of anti-dumping duty. In such a case, the profitability of the domestic industry is likely to be adversely impacted.

b. Price suppression/depression

83. In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	114	112
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	107

84. It is noted that the cost of sale as well as the selling price of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in selling price is not in tandem with the increase in cost of sales of the domestic industry.

IV. Economic parameters of the domestic industry

85. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

86. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Total Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	102	95
Capacity Utilization: Plant	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	123	107	96
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	99	95

87. The Authority notes that:

- The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.
- The capacity utilization, production and sales of the domestic industry increased till 2018-19 but declined thereafter.
- However, since the demand for the product under consideration had itself declined during the period of investigation, the decline suffered in capacity utilization, production and sales of the domestic industry, in the period of investigation can be attributed to the same.

b. Market share

88. Market share of the dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic industry	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	100	86	95
Subject imports	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	46	42	70
Other imports	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	286	379	229

89. It is noted that the market share of the domestic industry declined in 2019-20 but increased in the period of investigation. Similarly, the market share of the subject imports declined till 2019-20 but increased in the period of investigation. However, the imports from other countries gained market till 2019-20.

c. Inventories

90. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	13	18	103

91. It is noted that the inventories of the domestic industry declined in 2018-19, but increased in 2019-20. Thereafter, the inventories have increased in the period of investigation.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

92. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	114	112
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	107
Profit / (loss)	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	85	79
Profit / (loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	84	75
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	88	81
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	172	108	110

93. The Authority notes that:

- The profitability of the domestic industry declined in 2019-20 and POI.
- The return on capital employed of the domestic industry has increased in 2018-19 but decline in 2019-20.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Profit before interest	Rs. lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	101	83
Capital employed	Rs. lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	95	77
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	106	108

94. The Authority has also taken note of the concerns raised by other interested parties that the profitability of the domestic industry has declined due to increase in finance and depreciation costs. Accordingly, the Authority has examined the trend of EBIDTA of the domestic industry over the period. The Authority notes that the EBIDTA of the company has followed the same trends as profit before interest above.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
EBIDTA	Rs. lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	102	87

e. Employment, wages and productivity

95. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	149	149

Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	102	95
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	69	63
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	111	127

96. It is noted that the number of employees as well as the wages paid by the domestic industry increased over the injury period. The productivity per day and productivity per employee decreased in the period of investigation, with the decline in production.

f. Growth

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	16	(12)	(8)
Domestic sales	%	-	12	(11)	(4)
Profit/(loss) per unit	%	-	2	(17)	(6)
Cash profits	%	-	10	(20)	(8)
Return on capital employed	%	-	72	(37)	2

97. It is noted that both the volume and profitability parameters of the domestic industry showed improvement in 2018-19, but declined thereafter. However, the return on capital employed has increased in the period of investigation.

g. Ability to raise capital investment

98. The Authority notes that the domestic industry is making further investment for production of subject goods in India. Owing to the current anti-dumping duties in force, the ability to raise capital investment of the domestic industry has not been impacted.

h. Magnitude of dumping

99. It is seen that there is no dumping from co-operative producers/exporters, however dumping from non-co-operative producer/exporters is found to be positive.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

100. The Authority observes that this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this regard, the WTO Panel in EC – Footwear observed that –

“In original anti-dumping investigations, investigating authorities must determine whether the domestic industry of a Member is materially injured by dumped imports. At this stage, the focus is on the existence of “material injury” at the time of the determination. That determination is made under Article 3, based on information concerning the necessary and relevant factors for some previous period. In contrast, in an expiry review, an anti-dumping measure has been in place for some time, and investigating authorities must, based on a fresh analysis, determine whether the expiry of that measure would be likely to lead to continuation or recurrence of injury”.

101. Thus, in a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether revocation of a measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination of injury in an original investigation. A similar view was taken by the Hon’ble CESTAT in the decision of P.T. Asahimas Chemicals vs. Designated Authority, Ministry of Finance [2015 (328) E.L.T. 417 (Tri. - Del.)], wherein it was held –

“10. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the question as to whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.

11. In the light the aforesaid legal position, we are of the view that the question to be addressed is not whether there is current dumping, but whether revocation of duty would result in recurrence of dumping and injury.”

102. Therefore, in case of a sunset review investigation, existence of current injury to the domestic industry is not relevant to examine whether duties are required be continued or not. The Authority in a review investigation is required to analyze whether there exist likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of existing measures.
103. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
104. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Para (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
105. The importers have contended that the price of imports is lower because they had to adjust their prices in accordance with the anti-dumping duty and the prices of the applicant. The importers have further contended that the prices would increase in the absence of duties. However, it does not suggest that the imports are not likely to be dumped or cause injury to the domestic industry in the absence of duties.
106. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.
- a. **Continued dumping despite existence of anti-dumping duty**
107. The Authority notes that there is continued and significant dumping of the subject goods from Russia and Iran, in spite of the duties in force. Continued dumping during the existence of duties indicates likelihood of continuation of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty.
- b. **Increase in imports despite decline in demand and anti-dumping duty in force**
108. It is noted that after declining in 2018-19, the volume of imports from the subject countries increased over the remaining injury period, despite the decline in demand thereafter. Such increase in imports despite duties suggest that the subject imports are likely to increase further in the event of cessation of duty.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Russia	MT	79,656	58,958	74,417	99,951
Iran	MT	56,512	21,555	979	10,388

Georgia	MT	21,620	-	-	-
Subject imports	MT	1,57,788	80,513	75,396	1,10,339
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	114	100

c. Third country dumping

109. It is noted that the producers / exporters in the subject countries are dumping the subject goods in third countries as well in addition to India. The data on record shows that significant exports to third countries from Russia are at dumped prices.

Particulars	Georgia	Russia	Total
Total exports	4,29,433	78,82,381	83,11,814
Exports at dumped prices	4,29,433	68,06,500	72,35,933
Exports at dumped prices	100%	86%	87%
Exports at dumped prices in relation to demand in India	***%	***%	***%
Range	90-100%	1300-1500%	1400-1600%
Exports at injurious prices	424,259	7,185,514	7,609,773
Exports at injurious prices	99%	91%	91%
Exports at injurious prices in relation to demand in India	***%	***%	***%
Range	80-90%	1400-1500%	1500-1600%

Source: Trade map data

d. Significant idle capacities held by producers in subject countries

110. The domestic industry has provided a Market Research Report titled IHS Fertecon Nitrates Report which contains information regarding the capacity, production and demand in the subject countries. The Authority notes that the producers in the subject countries hold significant production capacities, in excess of domestic demand. The production of the producers is not sufficient to utilize capacities, leaving them with significant idle capacities.
111. The domestic industry has also submitted that JSC Azot, Kemerovo has recently expanded its capacity by 250 KT and is further planning a capacity expansion of 790 KT which is planned to be commenced by 2022 and a total fresh capacity of 1,140 KT in addition to the currently installed capacities are planned to be commenced by 2026.

Figures in thousand tons

Particulars	Georgia	Iran	Russia	Total
Capacity	450	221	11,306	11,977
Production	456	188	8,816	9,460
Demand	89	133	5,799	6,021
Idle capacities	0	33	2,490	2,523
Demand in India	-	-	-	486
Idle capacity in relation to Indian demand	***%	***%	***%	***%
Range	Nil	5-15%	500-550%	500-550%

Source: Market Research report

e. Export orientation of the producers/exporters

112. The applicant has claimed that the production of the product under consideration in Georgia and Russia is significantly more than the demand in the respective countries.:

Figures in '000 MT

Particulars	Georgia	Russia	Total
Production	456	8816	9272
Demand	89	5799	5888
Production meant for exports	367	3017	3384
Share of production meant for exports	80%	34%	36%

Source: Market Research Report

f. Measures imposed by other countries

113. The Russian producers faced trade remedial measures in European Union and Ukraine. As per the report submitted by the domestic industry, European Union may become an unattractive market for the Russian producers due to the imposition of such measures. Further, there was an anti-dumping duty imposed against exports from Russia in Australia as well, which has been revoked only in 2021. This underlines that the exporters in Russia are engaging in dumping practices in other countries as well.

g. Price attractiveness of India as a market

114. The applicant has claimed that the Indian market is a more price attractive market as compared to other markets for the producers in Russia as significant exports from the said countries are at prices below the prices prevailing in India.

Particulars	Russia
Total exports	78,82,381
Exports below Indian prices	72,03,348
Exports below Indian prices	91%
Exports below Indian prices in relation to demand in India	***%
Range	1400-1600%

Source: Trade Map data

h. Likely price suppression or depression

115. The Authority notes that the landed price of the subject imports is undercutting the domestic selling price. Further, the landed price of the subject imports has remained significantly below the selling price of the domestic industry. In the event of cessation of duties, such prices are likely to create a strain on the prices of the domestic industry, and force it to reduce its prices. Therefore, the subject imports are likely to have a depressing effect on the prices of the domestic industry.

i. Imports entering India below the cost of sales

116. It is noted that the subject imports are already entering the country at prices lower than the cost of sales of the domestic industry. Cessation of present duties would result in such imports entering the country at even lower prices, forcing the domestic industry to lower its prices in order to compete, resulting in decline in profitability. Further, the imports have entered the Indian market at injurious prices.

Particulars	Unit	Actual	Likely	Change
Cost of sales	Rs/MT	***	***	-
Selling price	Rs/MT	***	***	-17%
Profit / loss	Rs/MT	***	(***)	-128%
Profit / loss	Rs Lakhs	***	(***)	-129%

Profit margin (on cost)	%	***%	(***)%	-129%
Cash profits	Rs Lakhs	***	***	-98%
Return on investment	%	***%	(***)%	-107%

j. Imports at injurious prices

117. It is seen that the subject imports have entered the Indian market at injurious prices and below the cost of sales and selling price of the domestic industry despite duties in force.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

118. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
119. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Name of Producer	Non-injurious price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range%)
Russia						
1	Azot, JSC (Novomoskovsk) and JSC Nevinnomyssky Azot Nevinnomyssk	***	***	***	***	0-10
2	JSC Azot, Kemerovo	***	***	(***)	(***)	Negative
3	Non-cooperative/residual exporters	***	***	***	***	0-10
Iran						
1	Non-cooperative/residual exporters	***	***	***	***	10-20

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

120. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

121. It is noted that other than the subject imports, there are imports Bulgaria, Turkey, and Ukraine. However, the price of imports is significantly higher than the price of imports from subject countries.

b. Contraction in demand

122. The Authority notes that the demand for the subject goods increased consistently through the injury period but has declined in the period of investigation. Even though the demand has declined, the subject imports have increased. Therefore, the domestic industry is not likely to suffer injury due to contraction of demand.

c. Pattern of consumption

123. It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods, which is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

124. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the likely injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

125. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore, is not likely to cause injury to the domestic industry.

f. Productivity

126. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has remained stable over the injury period and, is not the likely cause of injury to the domestic industry.

g. Export performance of the domestic industry

127. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury likely to be suffered by the domestic industry cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

128. Some of the interested parties have contended that the injury to the domestic industry is due to decline in export sales. The Authority notes that the domestic industry is majorly involved in sales in domestic market only. The exports by the domestic industry were negligible over the injury period. Thus, any decline in exports cannot cause injury to the domestic industry.

h. Performance of other products

129. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

i. COVID-19

130. Some of the interested parties have claimed that the injury to the domestic industry in terms of decline in sales during 2019-20 and the period of investigation is due to COVID-19 pandemic. The Authority notes that the demand had declined during the period of investigation. However, the remaining demand was nevertheless sufficient for the domestic industry to maintain its capacity utilization. Nevertheless, the imports increased while the sales of the domestic industry declined. The Authority further notes that the applicant did not suffer any shutdowns during the period of investigation on account of Covid-19.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**K.1. Submissions by the other interested parties**

131. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the Indian industry's interest:

- a. The applicant has been able to establish itself at a dominant position in the market to the detriment of the user industries.

- b. The explosive manufacturers operate on a very thin margin and are bound to pass on the increase of the price of their critical raw material i.e., Ammonium Nitrate to the downstream user industry and that will create a cascading effect at all levels and affect the general public at large. By comparison, the sole manufacturer is enjoying handsome profits.
- c. While the applicant is earning handsome profit after imposition of the duty, the user industry is suffering because of high price and drying up of alternate sources of supply.
- d. The purpose of anti-dumping duty is to protect present investments and not future investments.
- e. Soaring freight cost and halted import activities due to lack of containers have further increased prices. Owing to high prices, some of the parties have not booked imports since November 2021.
- f. The farmers in Russia have been impacted due to the acute shortage of Ammonium Nitrate. Thus, to ensure availability of fertilizers, the Russian Ministry of Finance decided to prohibit the export of product under consideration from 1st December 2021.
- g. The applicant has underplayed the impact of anti-dumping duty on the user industry.
- h. The applicant is trying to maintain its monopoly position. The applicant is itself announcing creation of a monopoly for the AN solid.
- i. All mining companies including Coal India Limited, Singareni Colliery Company Limited, NMDC and other public sector and private sector units suffered for want of explosives for four months during the period of investigation.
- j. There is a huge demand-supply gap in the market. There is a deficit of 6 KT during the financial year 2020-21. In the pre-pandemic period, there was a deficit of 103 KT. The users faced shortages due to pandemic and lockdowns, explosion in Beirut followed by vigilance measures at Vishakhapatnam.
- k. There is a huge gap in the demand and supply of Ammonium Nitrate in the country. The user industry is facing the issues of short supply since applicant is a sole manufacturer with limited capacity.
- l. Extension of duty would threaten the viability of the downstream industries and cause a domino effect on the overall Indian economy. Since international prices of Ammonium Nitrate are already at an all-time peak, the coal prices will also go up, causing increase in the cost of electricity, thereby making manufacturing costlier, which will ultimately lead to inflated prices for goods and services for the end consumers. India recorded a power supply shortage of 1,201 million units in October 2021, which was the highest in 5.5 years, due to a crunch in coal stocks available with thermal plants.

K.2. Submissions by the domestic industry

132. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest:
 - a. The effect of anti-dumping measures on public interest must be studied from the perspective of interests of different set of parties – (a) the domestic producer of the product under consideration, (b) the domestic consumers of the product under consideration, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, (d) the general public and (e) purpose/ objective of imposition of anti-dumping duties.
 - b. The demand for the subject goods has continuously increased in the past five years. Therefore, the continuation of anti-dumping duty will not have an adverse impact on the user industry.
 - c. The profitability of the major users in India increased significantly till 2019-2020 therefore, the user industry did not suffer from the current anti-dumping duties in force and are not likely to suffer due to continuation of the current duties.
 - d. The user industry is not impacted by any price fluctuation of the subject goods as the contracts entered by them with the mining sector industries have a price variation formula which takes into account any fluctuation in prices of the subject goods. Solar Industries India Limited, in its Annual Report of 2020-21 reported that it passes on the cost increase to the customers.

- e. Contrary to the submissions of the other interested parties, the purpose of the anti-dumping duty is to eliminate injury caused due to unfair trade practices. Considering the landed price of imports and the injury margin, the anti-dumping duty should be enhanced in order to protect the proposed investment by the applicant.
- f. The user industry is already enjoying concessional basic customs duty of 2.5% on the imports from subject countries over the existing anti-dumping duties.
- g. The impact of continuation of anti-dumping duty on the mining sector will be to the tune of only 0.84%. The effect of the duty will be diminishing beyond the mining sector.
- h. While the other interested parties have made statements regarding the impact of anti-dumping duty on the downstream industry, they have failed to quantify the impact of the same.
- i. Cessation of present duties may lead to sickness of the Indian industry and can even force the producers to exit from the market, making India completely import reliant market.
- j. The subject goods are mainly used to produce explosive slurry which is used in the mining of coal, and it fulfills 65% of the power requirement of the country. Therefore, it would not be beneficial for the country to be entirely reliant on imports.
- k. Imposition of the duties would be in the interest of the consumers since high degree of export dependency would mean that the consumers are at the mercy of the exporters.
- l. Procuring from the domestic industry will result in stability of fair price in the market, uninterrupted supply, growth of the downstream industry and a reliable business partner for the users, while allowing them to hold lower inventories.
- m. Anti-dumping duties are not a ban on imports from subject countries. Rather, the duty only ensures that the imports shall enter the market at fair prices.
- n. The applicant has the capacity to meet more than 85% of the demand in India. The rest of the demand can be fulfilled by imports from other countries. Since subject goods are first converted into melt form, demand-supply gap must be considered after inclusion of AN in melt form, which would show that the capacity of India is equivalent to demand.
- o. Demand-supply gap is not a ground for non-imposition of anti-dumping duty as held in *Nocil Limited V. Government of India* and *DSM Idemitsu Limited V. Designated Authority*. The Authority has recommended imposition of anti-dumping duty in a number of cases where there was a demand-supply gap in India.
- p. The domestic industry has undertaken significant investments to cater to the Indian demand. If the cheap unfair priced imports are not prevented, the planned investment by the domestic producers would be under threat.
- q. Considering the safety issues with the product under consideration, the imports may be mishandled which is evident from the fact that the license of warehouses at Vizag port have been cancelled.
- r. There is no significant difference in the manufacturing process of the domestic industry and the exporters. Thus, there is no need for such a high dependence on the imports.
- s. Not only are the producers in the subject countries involved in unfair trade practice of dumping, but also engaging in circumvention of the anti-dumping duty imposed by the Central Government.
- t. If the anti-dumping duty is removed, duty will lead to further dumping of Ammonium Nitrate in the country and is likely to put the investment made by the applicant at risk.
- u. If dumping is allowed to destroy the competition in the market, it would discourage future investment in the product and the demand-supply gap would only widen.
- v. Contrary to the claim of the other interested parties, instead of cascading effects, there shall be significantly diminishing effects of continuation of anti-dumping duty on the downstream industries.

- w. It would be in the interest of the users to have local availability of the subject goods, to avoid any disruption such as Beirut explosion, to the supply chain in future.
- x. The power crisis in the country was due to inability of the industries to import coal as the demand for coal increased significantly resulting in global shortage and significant increase in the international coal prices. Moreover, the shortage was also due to the flooding of coal mines due to the rains.

K.3. Examination by the Authority

133. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition / continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
134. The other interested parties have argued that public interest must be looked into from the perspective of the user industry. The Authority notes that the examination is with regard to impact of duties on public at large, and the same is not limited to consumers. Therefore, the interests of all stakeholders must be considered in examination of public interest. While the issue of the public interest must be examined with attention to the user industry, however the interests of the important elements of the Indian industry cannot be completely brushed aside, which includes the domestic industry, other Indian producers, upstream supplying industry, ultimate consumers and general public at large. Further, the investigating authorities in different jurisdictions, such as European Union, United Kingdom, Brazil, New Zealand, etc. also examine the interests of the domestic industry along with the interests of other stakeholders in their public interest examination. Thus, in order to examine the overall public interest of the Indian industry, the Authority is required to take a wholistic and inclusive approach by considering the interests of all stakeholders.
135. The Authority considered whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
136. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. While the users / consumers have filed submissions with regard to adverse impacts of continuation of anti-dumping duty, they have failed to quantify the same. Further, it is noted that the subject goods are majorly used to manufacture slurry which is used in manufacturing explosives. As per the evidence on record the downstream industry is a pass-through industry and any fluctuations in the prices of the subject goods is passed on to further downstream industry.
137. With regard to the impact of the continuation of anti-dumping duties on the downstream industry, the Authority notes that there would be no cascading effect on the general public as the explosives manufactured by the downstream industry is mainly used in the mining sector in India, and the maximum impact on the mining sector would be only 0.84%.

Particular	UoM	Prices of domestic industry at highest profitability	Considering import price
Current Price	Rs/MT	***	***
Difference	Rs/MT	***	
% Increase	%	***%	
Cost of AN to Mining	%	4.40%	
Increase in Cost to Mining Sector	%	0.84%	

138. The above impact quantified by the domestic industry has not been disputed by the other interested parties with cogent evidence or information.
139. With regard to the performance of the user industry, the Authority notes that the user industries have continued to maintain their profitability over the injury period, even due to the current anti-dumping duties in force. Hence, there is no likely detrimental impact on the performance of the user industry as the revenue and profits of the users have increased over the injury period.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Revenue	Rs. Lacs	2,05,443	2,24,050	2,72,745	2,54,176
Profits before tax	Rs. Lacs	23,386	23,101	31,282	24,923
Profits as a percentage of revenue	%	11	10	11	10

Source: *Financial statements of the users**

The above analysis includes the performance of the following users:

- i. Ideal Industries Explosives Limited
 - ii. Solar Industries Limited
 - iii. Premier Explosives Limited
 - iv. Rajasthan Explosives Chemicals Limited
 - v. Nallabolu Industries Private Limited
 - vi. AKS Expo-Chem Private Limited
 - vii. Ambals Explosives Private Limited
 - viii. Regenesi Industries Private Limited
 - ix. Sri Vishnu Explosives Private Limited
 - x. Beezaasan Explotech Private Limited
 - xi. Bharat Explosive Limited
140. It is further noted that the user industry has a price variation formula which takes into account any fluctuation in prices of the product under consideration, as evident from procurement tender issued by Coal India Limited. This implies that any price increases would be passed on by the users.
141. The Authority further notes that the end users such as Coal India cannot be considered as being significantly impacted by the duties. As per information on record, Ammonium Nitrate constitutes less than 2% of the cost and revenue of Coal India. In such a situation, the impact of duty on such a small component of cost would be miniscule in the overall operations of the user.

	UoM	2018-19	2019-20	2020-21
Total revenue of Coal India	Rs. Crores	99,586	96,080	90,026
Total expenses of Coal India	Rs. Crores	78,294	78,453	75,806
Cost of explosives consumed	Rs. Crores	1,886	1,793	2,008
Cost of AN*	Rs. Crores	1,132	1,076	1,205

Share of explosives cost in total revenue	%	1.89%	1.87%	2.23%
Share of explosives cost in total expenses	%	2.41%	2.29%	2.65%
Share of AN cost in total revenue	%	1.14%	1.12%	1.34%
Share of AN cost in total expenses	%	1.45%	1.37%	1.59%

Source: Annual report of Coal India

*Cost of AN determined based on price variation clause in Bulk Rate Contract of CIL, wherein purchase of explosives is benchmarked at 60% to price of ammonium nitrate.

142. The Authority also notes that the weighted average component of anti-dumping duty in the import price has reduced over the period, that is, more imports are being made on payment of low or nil duty.

Particulars		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Total imports (MT)		205	259	276	242
ADD wise imports in MT	NIL	145	156	248	152
	US\$ 11.42	14	60	28	90
	US\$ 25	-	24	-	-
	US\$ 26.07	8	-	-	-
	US\$ 53.99	-	-	-	-
	US\$ 60.35	39	19	-	-
Share of ADD volume		30%	40%	10%	37%
Share of Non-ADD volume		70%	60%	90%	63%
Weighted Average ADD (\$/MT)		13.3	9.3	1.2	4.2

143. The Authority notes that while the weighted average duty was USD 13.3 per MT in 2017-18, it has declined to USD 4.2 per MT in the period of investigation, that is, only 1.87% of the import price. Further, 63% of the imports made were not subject to anti-dumping duties. Therefore, the duty cannot be considered to have caused a significant price increase in the market.
144. Some interested parties have contended that the applicant has established itself at a dominant position at a detriment of the user industry and is trying to create a monopoly in India. The Authority notes that the users have been able to maintain their profitability over the injury period, and there is no detrimental impact of anti-dumping duty in force. Although the applicant is the sole producer of Ammonium Nitrate in solid form in India, the subject goods are used eventually only in melt form. Thus, the applicant directly competes with the producers of Ammonium Nitrate in melt form and cannot create a monopoly in India. The applicant also competes with the imports of subject goods from subject countries as well as non-subject countries. Hence, it is not possible that the applicant is able to create monopoly in India.
145. Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand- supply gap in India. The Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The continuation of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge demand-supply gap.
146. The Authority also notes that while there is a demand-supply gap in the country, the imports at present far exceed such gap. That the product under consideration can also be imported from other countries, such as Bulgaria, Turkey, Uzbekistan and Ukraine.

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Bulgaria	MT	14,500	1,05,109	76,123	38,618
Egypt	MT	-	-	44	-
Japan	MT	-	-	19	-
Kazakhstan	MT	-	-	15,798	-
Korea RP	MT	3,398	660	500	-
Turkey	MT	-	38,100	1,05,926	52,500
UAE	MT	20,910	1,234	-	-
Uzbekistan	MT	-	4,793	4,495	-
Ukraine	MT	-	-	-	15,200
Iraq	MT	-	-	-	278

Source: DGCI&S Data

147. The volume of imports made from these countries were sufficient to address the demand-supply gap. The Authority notes the demand-supply position in the country is as below. While the imposition of anti-dumping duty would not prevent imports, in any case, users can continue to source the subject goods from other countries.

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Demand	488,020	547,197	558,768	486,152
Capacity in India	483,600	483,600	483,600	483,600
Other imports	46,808	149,896	202,905	106,596
Capacity of domestic industry + other imports	530,408	633,496	686,505	590,196
Supply in excess of demand	42,387	86,299	127,737	104,044

148. The Authority further notes that while AN melt is not like article to the imported goods, it is nevertheless a directly competitive product. Therefore, the demand-supply situation can be better evaluated after considering the demand and capacity for both the like article and AN melt.

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Demand (DGCI&S)	***	***	***	***
Capacity in India*	***	***	***	***
Other imports (DGCI&S)	53,308	1,53,412	2,14,454	1,18,304
Capacity of domestic industry + other imports	***	***	***	***
Supply in excess of demand	***	***	***	***

From the above, it is evident that even after excluding imports from subject countries, there was sufficient supply of the subject goods in the Indian market.

149. With regard to the demand-supply gap, the Authority also takes note of the significant capacity additions being planned by the domestic producers. As per information supplied by various producers of ammonium nitrate, in all forms, the applicant, Chambal Fertilisers, GNFC, RCF and NFL are all planning to expand capacity. These include expansions of current capacity, brownfield plants as well as greenfield plants. Such capacity expansions would increase the total capacity in the country by 9 lakh tons per annum. The Authority notes that such capacity additions would help further bridge the demand-supply gap in the country. However, if competitive conditions in the market are not maintained, the viability of the planned capacity additions may be jeopardized.

150. Some of the interested parties have contended that coal manufacturing companies were suffering due to scarcity of subject goods in India. The Authority notes that the subject goods are not used directly by the coal manufacturing companies. These companies use explosives manufactured using subject goods. The explosive manufactures have not contended that there was scarcity of the subject goods in India. The capacity utilisation of the domestic industry has declined over the injury period and the inventories have increased. In case of scarcity of subject goods in India, there should not have been any accumulated inventories.
151. It has been represented by the users that owing to the Russian embargo, restrictions on certain ports and Beirut explosion, the availability of the product under consideration was impacted in the country. The Authority does not find any nexus between these events and the imposition of duty. To the contrary, such events would have disrupted supply, even in the absence of anti-dumping duties. It is also worth noting that such international supply disruptions underscore the importance of domestic manufacturing. The Authority, therefore, does not find that the imposition of duties would aggravate the demand-supply situation. The Authority also considers that it is imperative to encourage domestic manufacturing, to ensure that the Indian consumers are not reliant on imports, and are in a position to source the subject goods even in face of any embargo or other international factors disrupting supply.

L. POST-DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS

152. The post disclosure submissions have been received from the interested parties and the domestic industry, and it is noted that most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

L.1. Submissions by the other interested parties

153. The following post-disclosure submissions have been made by the other interested parties. The other interested parties have reiterated their submissions with regard to scope of like article and the domestic industry, determination of the normal value, absence of injury, absence of likelihood of continuation of dumping and injury, absence of causal link, inconsistencies in data, effect of explosion in Beirut and measures at Vishakhapatnam port, existence of demand-supply gap, embargo by Russia and confidentiality claimed by the domestic industry.
- i. While the Authority has taken a full year to investigate, the interested parties have been given only a day to give comments. Further, the Authority would have less than 24 hours to consider the comments.
 - ii. The entire likelihood analysis relates to Georgia and Russia only and does not cover Iran.
 - iii. Since the cooperative producers from Russia have negative dumping margin, the entire volume of Russia to India is un-dumped.
 - iv. Low density ammonium nitrate should be excluded from the scope of duty specifically.
 - v. The methodology for determination of residual dumping margins, and mere reference to Rule 6(8) of the Rules is not sufficient. Further, cost of production of the domestic industry cannot be relied upon for determination of normal value for Iran.
 - vi. The disclosure statement also does not record whether the conditions required under the rules for a cumulative assessment has been met.
 - vii. No source of information for third country dumping has been identified.
 - viii. Increasing price of AN domestically and internationally, apart from high demand supply gap in the country, is impacting bulk explosive manufacturing and availability of explosive for the mining sector.
 - ix. The domestic industry is making fresh investments for production of ammonium nitrate and ammonia.
 - x. There is a huge demand-supply gap in the country, and the demand has increased over the period.
 - xi. As per Article 5.8, where any exporter was found to be not dumping in the original investigation, there should be immediate termination against such exporter.

- xii. India is not a major market for the exporters in Russia.
- xiii. No duties should be imposed on cooperative producers, found not to be dumping.
- xiv. There has been an increase in prices of product under consideration globally, such as countries Europe, Russia and North America in 2021.
- xv. Imports from third countries are priced below the non-injurious price.
- xvi. The price revision formula of Coal India tenders does not reflect the market prices in real time. If anti-dumping duty is extended, the explosive manufacturers would not be able to recover

L.2. Submissions by the domestic industry

154. The domestic industry reiterated its submissions with regard to likelihood of dumping and injury from Georgia, and consideration of intangible assets in the determination of non-injurious price. In addition, the post-disclosure submissions have been made by the domestic industry:
- a. The exporters from Georgia should have been asked to provide information regarding third country exports.
 - b. Since the present investigation is based on likelihood of dumping and injury, and not that of present injury, the same anti-dumping duty should continue.
 - c. CIL has experienced a huge increase in profits, as well as GOCL which is a major user of ammonium nitrate.

L.3. Examination by the Authority

155. The Authority notes that most comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings. The Authority has examined the fresh issues raised by the interested parties.
156. The Authority noted that the domestic industry has claimed consideration of intangible assets in the determination of NIP. However, the Authority noted the intangible assets claimed by the domestic industry is in the form of Goodwill and cannot be considered for NIP.
157. As provided in the relevant part of this final findings, Georgia has been excluded as a subject country owing to lack of evidence of likelihood of dumping and injury due to cessation of present anti-dumping duty.
158. The disclosure statement had been issued on 7th June, 2022 and the interested parties had been asked to file comments by 8th June, 2022. The interested parties have expressed grievance with being provided only one day for filing comments to the disclosure statement. However, in order to provide interested parties time to file comments, the Authority had extended the deadline by one day to 9th June, 2022. The Authority is constrained from providing further time to the interested parties to file comments due to the refusal of the Central Government to provide an extension of time to the Authority to conclude the investigation.
159. Regarding the likelihood of dumping and injury from Iran, the Authority notes that there is evidence of present dumping from the country. Further, the imports from Iran have increased in the recent period, after declining till 2018-19. The price of such imports is also below the selling price of the domestic industry, resulting in significant price undercutting. Further, the imports are entering at injurious prices, below the cost of sales and non-injurious price of the domestic industry. This shows that in the absence of duties, dumping is likely to continue, the volume of imports is likely to increase further, and cause injury to the domestic industry.
160. Contrary to the claim of interested parties, the negative dumping margin for the cooperative producers does not imply that the dumping margin for the entire country is negative, inasmuch as the responding producers do not constitute the entirety of the producers in the country.
161. Since the product under consideration is restricted to ammonium nitrate having bulk density in excess of 0.83 g/cc, no specific exclusion with regard to ammonium nitrate having a lower density is required.

162. The normal value for non-cooperative producers and for Iran have been determined as per consistent practice of the Authority. The interested parties have not submitted any evidence, which may be more suitable for determination of normal value. Therefore, the Authority has relied upon facts available.
163. The interested parties have contended that the cumulative analysis of injury has been conducted without examining whether the requirements thereof are satisfied. The Authority notes that, in case of a sunset review, while cumulation is allowed, the conditions thereof are not applicable. The Panel in the case of United States – Sunset Review of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Argentina took a view that the conditions set forth in Article 3.3 do not apply to sunset reviews. Therefore, the Authority is not required to examine whether all conditions of cumulation are satisfied before proceeding with a cumulative analysis.
164. As already disclosed in the relevant part of the present findings, the analysis of third country dumping is based on Trade Map data. Even though such data was supplied by the applicant in the petition itself, it has not been controverted with evidence by any interested party during the course of the investigation.
165. The interested parties have emphasized the demand-supply gap and the high prices of the subject goods impacting the explosives sector and availability of explosives for the manufacturing sector. The domestic industry, on the other hand, has relied upon the performance Coal India Limited and GOCL, which shows that both explosives manufacturers and users of explosives have seen a significant increase in profits, and the coal offtake has also increased. The Authority notes significant capacity additions being planned by the domestic producers. As per information supplied by various producers of ammonium nitrate, in all forms, the applicant, Chambal Fertilisers, GNFC, RCF and NFL are all planning to expand capacity, by a total of 9 lakh tons per annum. These include expansions of current capacity, brownfield plants as well as greenfield plants. The Authority notes that such capacity additions would help further bridge the demand-supply gap in the country. In any case, the Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The continuation of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge demand-supply gap. Further, the subject goods can also be imported from other countries, such as Bulgaria, Georgia, Indonesia, Turkey, Uzbekistan and Ukraine.
166. As regards the request for termination of investigation against producers found not to be dumping in the original investigation, the Authority notes that such termination would not be in accordance with the settled jurisprudence and its own practice. During the original investigation, nil duty was levied on the exporter, but the investigation against it was not terminated. The exporter also did not ask for such a termination. The Authority has consistently taken a view that it can conduct sunset reviews against an exporter having zero duties in the original investigation. In the case of *Robin Resources v. Union of India*, the Hon'ble CESTAT also noted as follows.
- “9. We note that the DA can consider where an exporter was awarded zero duty in the original investigation and has now found to be dumping which is likely the cause injury to DI, then AD duty can be considered for imposition with reference to dumping margin and injury margin established during the review. We note that the DA followed the requirements of Articles 2 and 3 of the ADA and the relevant provisions of AD Rules. We also note that regarding appellants, the DA has examined and reviewed all the aspects of original investigation and in addition examined whether expiry of initial notification is likely to lead a recurrence of dumping/injury to the DI. As already noted that this is like a fresh investigation insofar as appellant is concerned and we find no legal infirmity in such action by the DA...”
167. As regards the contention of the interested parties that India is not an important market for Russia, it is noted that even during the present period of investigation, the imports from Russia increased. Further, such imports are at injurious prices, below the selling price and cost of sales of the domestic industry. The exporters from Russia hold significant surplus capacities. Moreover, India is a price attractive market, which would encourage the exporters to divert exports to India. Therefore, the evidence on record shows that there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of expiry of duty.

168. The interested parties have claimed that the prices of the subject goods have increased in 2021, particularly in Russia, Europe and North America. The Authority notes that the information on record shows that Russia has a huge surplus capacity, over and above its domestic demand. Further, Europe and North America have imposed restrictions against the exports from Russia, as a result of which some markets are not available to Russia.
169. The interested parties have also contended that the imports from other countries are priced below the non-injurious price. The Authority has examined the data on record and found that there are significant imports from Bulgaria, Turkey and Ukraine. However, such imports are priced above the non-injurious price.
170. Some of the importers and users have also emphasized that the existing anti-dumping duties have caused significant hardships to the users. However, they have not refuted the evidence provided by the domestic industry that the financial statements of users do not show a deterioration in performance.

M. CONCLUSION

171. Having regard to the contentions raised, the information provided, the submissions made and the facts available before the Authority as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. The product produced by the domestic industry is the like article to the product under consideration imported from the subject countries.
 - b. There are no exports of the subject goods from Georgia to India during the POI and preceding years. There is no surplus capacity available with the only Georgian producer during the POI as evidenced from the information shared by the applicant as well as interested parties. Further, there is no surplus capacity available with the only Georgian producer during six months post-POI. As per the evidence on record, no other country has imposed anti-dumping duty on imports of the subject goods from Georgia. There is absence of current dumping and injury to the domestic industry due to imports from Georgia as well as there is no likelihood of dumping and injury due to imports from Georgia and thus, Georgia has been excluded from the subject countries.
 - c. There is continued dumping from Russia and Iran, despite anti-dumping duty in force, from the subject countries. In light of the evidence on significant idle capacities, export orientation, third country dumping, measures imposed by other jurisdictions as well as price attractiveness of India, the Authority notes that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case of cessation of the present anti-dumping duty in force.
 - d. While the cooperative producers have not been found to be dumping, the dumping margin and injury margin for non-cooperative producers from the subject countries is positive and significant.
 - e. From the foregoing, the Authority concludes that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry by imports from Iran and Russia in the event of cessation of existing anti-dumping duty.

N. RECOMMENDATIONS

172. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, causal link and likelihood of dumping and injury.
173. Having found no evidence of current dumping or injury, or likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of expiry of duty due to imports from Georgia, the Authority does not find that continuation of anti-dumping duty on the imports of ammonium nitrate originating in or exported from Georgia is warranted. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duty on imports of Russia and Iran are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from Russia and Iran is required to be continued

further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from Russia and Iran as per column 7 in the duty table below, for a further period of two (2) years.

Duty Table

SN	Tariff Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	31023000	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>	Russia	Any country including Russia	JSC Azot JSC Nevinnomyssky Azot	Nil	USD	MT
2	-do-	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>	Russia	Any country including Russia	JSC Azot, Kemerovo	Nil	USD	MT
3	-do-	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>	Russia	Any country including Russia	Any other than SN 1 and 2	16.91	USD	MT
4	-do-	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without</i>	Any country other than Russia and Iran	Russia	Any	16.91	USD	MT

		<i>additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>						
5	-do-	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>	Iran	Any country including Iran	Any	31.24	USD	MT
6	-do-	<i>Ammonium nitrate” whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc</i>	Any country other than Russia and Iran	Iran	Any	31.24	USD	MT

174. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, as amended from time to time.

O. FURTHER PROCEDURE

175. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority